RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107
समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053
विशेष संपादक
मुकेश कुमार सिंह
सहायक संपादक
कोमल सुल्तानिया
राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337
संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433
राजनीतिक ब्यूरो
अमरेंद्र शर्मा 9899360011
प्रभाकर कुमार राय
प्रबंधक
अविनाश कुमार 8287266244
विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह 9546224277
क्राइम ब्यूरो
एसएन श्याम
मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार
जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334114515
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति, रंजीत कुमार
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318
प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 8, अंक : 8, अप्रैल 2021, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

8 कांग्रेस से डरी हुई डबल इंजन सरकार

तीरथ सिंह बने मुख्यमंत्री '.. 10

भारत में सिनेमा का पदार्पण... 17

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आरएसएस ... 20

जब तक वैक्सीनेशन पूरा ... 44

आईपीएल जरूरी क्यों

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

कोरोना के कारण जब लोग घर से निकलकर बाजार जाने में भी हिचक रहे हैं, तब दुनिया भर से बड़े-बड़े खिलाड़ी भारत आकर खेलने पर राजी हुए तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि उन्हें यहां सुरक्षित रहने का भरोसा है। उनका भरोसा टूटने न पाए, यह जिम्मेदारी हमारी है। आईपीएल का 14वां सीजन शुरू हो रहा है जो 30 मई तक चलेगा। इसे निर्विवाद रूप से क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है। इन डेढ़-दो महीनों में क्रिकेट की जो धूम रहेगी और फैंस का जो क्रेज दिखेगा उसकी तुलना किसी और आयोजन से नहीं हो सकती। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस बार इसका रूप थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन इसका आयोजन होना ही कम राहत की बात नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को केवल इस खांचे में नहीं देखा जा सकता कि चंद निजी हाथों ने टीमें खरीदीं और उन्हें मैदान में लड़ने को उतार दिया। भारतीय क्रिकेट आज अगर ऐसे मुकाम पर है, जहां से दूसरे खेल उसे अपना रोल मॉडल बना सकते हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह लीग भी है। इसने ऐसी बेशुमार प्रतिभाओं को चमकने का मौका दिया, जो इसके बगैर अंधेरे में गुम हो जाते। यही नहीं, इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी हैं जो क्रिकेट के दायरे के बाहर भी इसे उपयोगी बनाए हुए हैं। यही कारण है कि कोविड-19 के चलते जहां दूसरी कई गतिविधियां बंद की गईं वहीं आईपीएल के साथ ऐसा कोई जोखिम नहीं लिया गया। यूएई में और तमाम पाबंदियों के साथ ही सही, पर इसका 13वां सीजन भी बाकायदा आयोजित हुआ। पाबंदियां इस बार भी हैं। आयोजन स्थलों की संख्या सीमित करके 6 कर दी गई है। भारतीय बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर टीम को पूरे टूनार्मेंट के दौरान केवल तीन बार यात्रा करनी पड़े। यह सब इसलिए ताकि वायरस से सुरक्षा के लिए बायो बबल का जो घेरा तैयार किया गया है, उसमें सेंध न लगने पाए। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि जब दुनिया के बड़े नाम भारतीय जमीन पर खेल रहे होंगे, उन्हें देखने के लिए स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में कोई नहीं होगा। लीग के पिछले सीजन में भी ऐसा ही हुआ था, पर तब मैच दुबई में हो रहे थे। इस बार खिलाड़ी और फैंस दोनों के लिए मन को संभालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यह लीग पहले भी बड़ी-बड़ी मुश्किलें पार कर चुकी है। इसी से उम्मीद जगती है कि इस बार भी सबकुछ सही होगा। अगले करीब दो महीने ऐसी कठिन परीक्षा के होंगे जिसमें फेल होने का जोखिम भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं ले सकता। कोरोना के कारण जब लोग घर से निकलकर बाजार जाने में भी हिचक रहे हैं, तब दुनिया भर से बड़े-बड़े खिलाड़ी भारत आकर खेलने पर राजी हुए तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि उन्हें यहां सुरक्षित रहने का भरोसा है। उनका भरोसा टूटने न पाए, यह जिम्मेदारी हमारी है।

कोरोना की दूसरी लहर में फुस्स हो गया टीकाकरण अभियान

धानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने तो दिल्ली स्थित एम्स में जाकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है, फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर ली, वहीँ देश के अधिकाँश हिस्सों में अभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं मिल पायी है। ये भी देखा जा रहा है कि टीके के प्रति जहाँ एक ओर लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं हो रहा है, वहीँ टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ये स्थिति जहाँ चिंता बढ़ाने वाली है, वहीँ यह टीके के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने वाली भी है। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने उम्मीद जगाई थी कि जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, कोरोना के नए मामले उतने की कम देखने को मिलेंगे, लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। जैसे-जैसे वैक्सीन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उससे दोगुनी रफ़्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है।

पिछले साल मार्च में कर्फ्यू और लॉकडाउन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली-थाली पीटने और घरों में दिए जला कर प्रकाशोत्सव मनाने जैसे उपक्रम करवा कर कोरोना को भगाने की कोशिश में सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लगवा दिया था, अबकी साल नाइट कर्फ्यू की जगह ह्यकोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करने और 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जन्मजयंति एवं 14 अप्रैल को बाबा भीमराव आंबेडकर जन्मजयंति को ह्यटीका उत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है। भारत की मासूम और नासमझ जनता ह्यउत्सवों का क्या मतलब समझती है और किस प्रकार मिलजुल कर और इकट्ठी हो कर मनाती है,

कोरोनाकाल में इसके अनेक नजारे देखने के बाद भी चुनावी राज्यों में लगातार बड़ी-बड़ी रैलियां करवा रहे प्रधानमन्त्री द्वारा कोरोना को भगाने के लिए ह्यटीका उत्सव मनाने का ऐलान करने से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए और क्या हो सकता है?

देश में स्वास्थ सेवाओं को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने की बजाय चुनावी राज्यों में रैलियों-उत्सवों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाली जनता के जबरदस्त जमावड़े को देख कर देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे खिल उठते हैं। बीमारी और मौत का आह्वान करती भीड़ को देख कर वह मुस्कुराते हैं। हाथ हिला-हिला कर उसका स्वागत करते हैं। आश्चर्य !

बीते एक साल में केंद्र और राज्य की सरकारें ना तो अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलिंडर की व्यवस्था कर पाई हैं और ना ही बीमारों के उपचार के लिए अस्पतालों को पर्याप्त बेड उपलब्ध हो सके हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या लगभग सभी अस्पतालों में इतनी कम है कि महामारी के भीषण रूप इख्तियार कर लेने की स्थिति में मरीजों को बचा पाना डॉक्टरों के लिए लगभग नामुमकिन सा है। बीते एक साल में कोरोना से संक्रमित होने वाले तीन चौथाई लोग होम आइसोलेशन में रह कर ठीक हुए हैं, क्योंकि वहां उनकी देखभाल करने वाले उनके अपने परिजन थे, जिन्होंने बिना भय के अपने मरीज को नियमित रूप से गर्म पानी, भंपारा और बुखार-खांसी की दवाएं देकर बीमारी से उबार

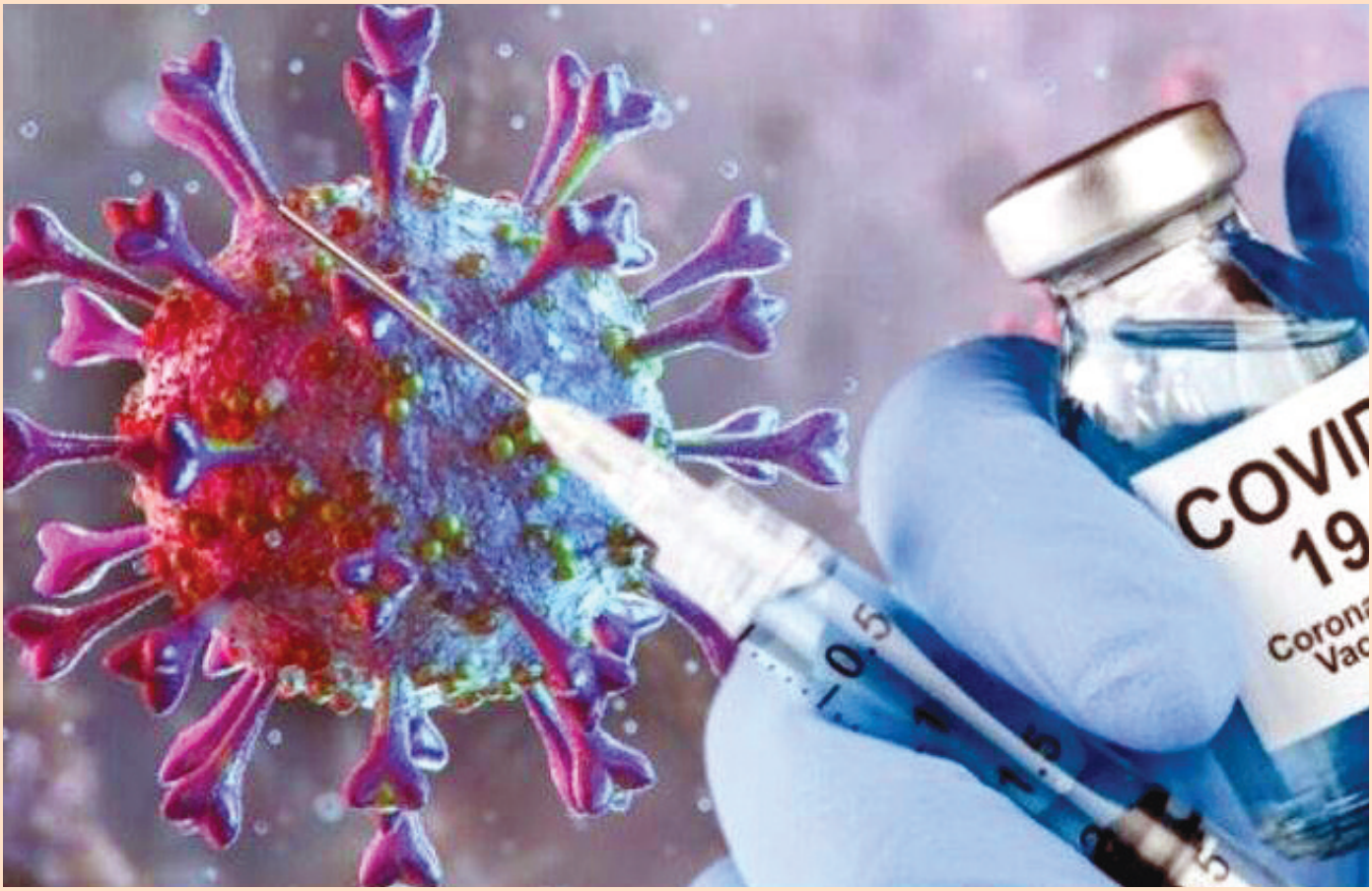

लिया, जबकि अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर कोरोना मरीज मौत का शिकार हुए हैं, क्योंकि वहां उनके पास जाने में मेडिकल स्टाफ को डर लगता था, ऐसे में उपचार तो क्या ही हुआ होगा।

अधिकाँश अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जिसमें मास्क, ग्लोव्स, गाउन, एप्रन, फेस प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, स्पेशल हेलमेट, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्टर, गोगल्स, हेड कवर, शू कवर, रबर बूट्स शामिल होते हैं, नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी जान पर रिस्क नहीं लिया।

हैरानी की बात है कि कोरोना काल का एक साल बीत जाने पर भी यह कमी अस्पतालों में बनी हुई है। बीते साल मेडिकल स्टाफ के जिन लोगों ने इन बातों की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से की, उन्होंने अपनी नौकरियां गवां दीं। अस्पतालों की अव्यवस्था और कमियों को दूर करने की बजाय प्रधानमन्त्री लोगों से तालियां बजवाते रहे। किसी अस्पताल ने कोरोना मरीजों के परिजनों को उनसे मिलने या देखने की अनुमति नहीं दी, मृत्यु हो जाने पर लाश को पॉलिथीन में पैक कर सीधे शमशान भेज दिया गया, इसलिए उपचार की तमाम सच्चाइयां अस्पतालों की चारदीवारी में ही दफन हो कर रह गयीं।

बेकाबू होती कोरोना की रफ़्तार

बीते एक साल से लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार था। इस दौरान भारत में करीब बीस दवा कम्पनियाँ कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिसमें सबसे अव्वल रहा अदार पूनावाला का पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया। कोरोना काल से पहले तक अदार पूनावाला का नाम आम जनता नहीं जानती थी, मगर कोरोना ने उन्हें नाम और दाम दोनों दिया। यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद होकर सीरम इंस्टिट्यूट उनसे मिलने पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना के खात्मे के लिए कोवीशील्ड नाम की वैक्सीन बनायी है। जबकि इसी के समानांतर हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन का निर्माण किया है। बायोटेक के एमडी डॉ। कृष्णा एल्ला हैं। इस समय भारत में यही दोनों वैक्सीन लग रही हैं। इस साल जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू होने पर दोनों ही कंपनियों ने भरोसा दिलाया था कि उनके द्वारा निर्मित वैक्सीन लेने के बाद कोरोना की रोकथाम प्रभावशाली तरीके से होगी। मगर अब इन वैक्सीनों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

देश में अब तक सात करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। खासकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई लोगों को दोबारा संक्रमण हो रहा है तो कहीं वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 40 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए हैं, जबकि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेस मिल चुकी हैं, वहीँ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भी 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें से पांच अस्पताल में ही भर्ती हैं। अन्य डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया हैं। जानकारी के अनुसार इनमें से ज्यादातर डॉक्टर वे हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे और जिनको वैक्सीन लग चुकी थी। इन खबरों के चलते देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच वैक्सीन को लेकर अब कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक राजेश पांडेय अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने 5 फरवरी और दूसरी डोज 5 मार्च को ली थी। अधिकारी ने कोरोना वैक्सीन लेते हुए अपनी फोटो भी पोस्ट की थी।पुलिस महानिरीक्षक राजेश पांडे के साथ उनकी पत्नी और एक सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। उनके सुरक्षाकर्मी ने भी वैक्सीन की दो डोज ली थी, जबकि पत्नी ने अभी एक डोज ली है। उनके बेटे को तीन दिन पहले संक्रमण हुआ था। इसके बाद एक बार फिर सवाल पैदा हुआ कि आखिर वैक्सीन की दो डोज लेने के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा, जबकि वैक्सीन निमार्ताओं ने दावा किया था कि दो डोज लेने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए शरीर में प्रभावी इम्युनिटी विकसित हो जाती है।

मामला सँभालने की कोशिश

इस बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक रिपोर्ट जारी कर मामले को सँभालने की कुछ कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनः संक्रमण के मामले बहुत कम हैं, और इस संबंध में वायरस के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को समझने की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 4।5 फीसदी है। इनमें पहली और दूसरी बार हुए संक्रमण में

वायरस के जीनोम का अध्ययन नहीं किया गया है। पुनः संक्रमण की यह दर अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में बताई गई 1 फीसदी रि-इंफेक्शन के दर से कहीं अधिक है। संभव यह भी है कि कोविड-19 का दोबारा संक्रमण वायरस के अलग वैरिएंट्स की वजह से हो। अब तक के वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह वायरस लगातार अपना जीनोम बदल रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के कई वैरिएंट्स सामने आए हैं। लेकिन इन पर समुचित अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मानते हैं कि कई लोगों को वैक्सीन की दो डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है? मगर इस पर उनका कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उन पर इस वायरस का असर कम दिखेगा और वो गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे। उनमें हल्के लक्षण हो सकते हैं। उन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की मौत होने की संभावना भी कम है।

कितनी कारगर है वैक्सीन

संक्रमण से बचाव में वैक्सीन के प्रभावी होने के संबंध में वैक्सीन निमार्ताओं के दावों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि अमूमन सभी वैक्सीन निमार्ताओं ने अपनी वैक्सीन को संक्रमण से बचाव में 70-80 फीसदी कारगर बताया है।

अब यदि वैक्सीन को 70 फीसदी ही कारगर माना जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि 30 प्रतिशत लोगों में संक्रमण का जोखिम वैक्सीन लेने के बाद भी बना रहता है। यानी 10 में से 3 लोगों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। उन्हें संक्रमण हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है कि किसे संक्रमण हो सकता है और किसे नहीं। भारत में इस वक्त जो दो वैक्सीन झ्र कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है, उसके निमार्ताओं का कहना है कि यह संक्रमण से गंभीर स्थिति पैदा होने और मौतों को रोकने में 100 फीसदी तक कारगर है।

वैक्सीन निमार्ता कंपनियों के इस दावे का सीधा अर्थ यह है कि अगर किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है और निर्धारित समय के भीतर उसका दूसरा डोज ले लिया है, तो उसमें संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति पैदा नहीं होगी और इस वजह से उसकी जान नहीं जाएगी। कंपनियों का कहना है कि उनके दावे वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हैं और इस तरह विज्ञान के नजरिये से देखें तो वैक्सीन संक्रमण के कारण गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा होने की स्थिति से बचाता है और मौतों को भी रोकता है। साथ ही यह एक बड़ी आबादी, तकरीबन 70 फीसदी लोगों को संक्रमण की चपेट में आने से बचाता भी है।

किस तरह काम करती है वैक्सीन

इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन की दो डोज लेना जरूरी है। कोवैक्सीन का दूसरा डोज जहां 28 से 42 दिनों के भीतर लिया जा सकता है, वहीं कोविशील्ड का दूसरा डोज 42 से 56 दिनों के बाद लिया जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं झ्र यूं तो वैक्सीन का असर पहले डोज के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन वायरस से लड़ने में यह प्रभावी नहीं होता और इसलिए दूसरा डोज लेने की सलाह दी जाती है। दूसरा डोज लगवाने के 14 दिनों बाद वैक्सीन वायरस से लड़ने में प्रभावी हो जाती है। मगर सवाल यह है कि जिस रफ़्तार और जिस टूटी-फूटी व्यवस्था के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वह इतने बड़े देश में पांच साल में भी पूरा नहीं होगा।

टीकाकरण अभियान लक्ष्य से बहुत पीछे

गौरतलब है कि देश में टीकाकरण अभियान की शुरूआत जनवरी मध्य में हो गयी थी मगर 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी तक सिर्फ सात करोड़ के करीब लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। टीकाकरण की शुरूआत के वक़्त जो लक्ष्य रखा गया था उसके मुताबिक अब तक 10 -15 करोड़ लोगों को टीके लग जाने चाहिए थे। यह ठीक है कि जब से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगवाने की हरी झंडी मिली है तब से टीकाकरण की रफ्तार कुछ बढ़ी है, लेकिन यह अब भी लक्ष्य से बहुत पीछे है। आखिर प्रतिदिन 50 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य जो केंद्र और राज्यों की सरकारों ने रखा था, क्यों नहीं हासिल हो पा रहा है? जवाब है झ्र देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्टाफ की बेतरह कमी, अस्पतालों की कमी, जागरूकता की कमी और टीके के प्रति लोगों के दिलों में अविश्वास।

केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और पात्र लोग टीका लगवाने में तत्परता का परिचय दें।

खराब हो रहे हैं टीके

गाजियाबाद जिला अस्पताल की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर ऋतु वर्मा कहती हैं कि टीके की बोतल खुलने के चार घंटे बाद वह बेकार हो जाती हैं। यदि इस बीच पर्याप्त संख्या में लोग टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचते हैं तो टीके का नुकसान होता है। वहीँ कोवैक्सीन की डोज देने के लिए कम से कम दस लोगों के समूह का इंतजार करना होता है।

कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर गृह मामलों की संसदीय समिति ने भी जताई चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे तो टीकाकरण पूरा होने में कई साल लग जाएंगे। राज्यसभा में पेश गृह मंत्रालय की अनुदान की मांग संबंधी रिपोर्ट पर समिति ने यह भी चिंता जताई है कि काफी संख्या में लोगों को टीके की दूसरी खुराक नहीं लग पा रही है। समिति कोविड -19 के वर्तमान टीकाकरण प्रक्रिया पर गौर कर रही है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति का कहना है कि अभी तक भारतीय आबादी के एक फीसदी से भी कम लोगों का टीकाकरण हुआ है और इस दर से पूरी आबादी के टीकाकरण में कई साल लग जाएंगे।

यह समझना कठिन है कि जब टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, तब फिर सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने की सुविधा देने से क्यों बचा जा रहा है?

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि टीकों के खराब होने का एक कारण वांछित संख्या में लोगों का टीकाकरण केंद्रों में न पहुंचना है। यदि पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध हैं तो फिर घर-घर टीके लगाने का भी कोई अभियान शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि जो लोग अपने काम-धंधे के सिलसिले में घरों से बाहर निकलते हैं और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगे, भले ही उनकी उम्र 45 वर्ष से कम क्यों न हो। ऐसे उपाय इसलिए आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि अब अपेक्षाकृत कम आयु वाले लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब जब कोरोना संक्रमण के खतरे ने फिर से सिर उठा लिया है, तब फिर पात्र होते हुए भी टीका लगवाने में देरी करने का कोई औचित्य नहीं।

वहीँ जो लोग किसी न किसी कारण टीका लगवाने से बच रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हाल-फिलहाल कोविड महामारी से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा और वह अभी भी घातक बनी हुई है, ऐसे में टीका लगवा लेना ही बेहतर है क्योंकि इससे कुछ बचाव तो होगा। इस सम्बन्ध में सरकार को जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, मगर वह तो राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। जहां बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। भारी भीड़ इकट्ठा करके कोरोना को न्योता दिया जा रहा है।

पूनावाला ने माँगा सरकार से पैसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में 35 हजार करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रखे थे। उन्होंने कहा था कि यह नई आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एक हिस्सा होगा और जरूरत पड़ी तो और भी पैसा खर्च किया जाएगा। इससे साफ है कि भारत सरकार कोरोना वैक्सीनेशन पर पैसा तो खर्च करने को तैयार है, मगर वैक्सीन कंपनियां जो अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पर वैक्सीन दे रही हैं, वो अब इस ह्यआपदा में अवसर ढूंढ कर कुछ कमाना भी चाहती हैं। जैसा कि सीरम इंस्टिट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने साफ भी कर दिया है।

दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निमार्ता कंपनी कहलाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस समय अपने देश में आपूर्ति को पूरा करने की जरूरत एवं अपने अंतरराष्ट्रीय समझौते के बीच फंसी हुई है। सीरम के सीईओ अदान पूनावाला कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की आपूर्ति में देरी होने के चलते कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। इसलिए कोवीशील्ड का उत्पादन दोगुना करने के लिए हम भारत सरकार से ग्रांट के रूप में मदद चाहते हैं। अदार पूनावाला ने कोविड-19 वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की है।

पूनावाला का कहना है कि हमने पहले ही हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। हमें अपनी क्षमता निर्माण के लिए अन्य नए तरीके तलाशने होंगे। हमें मोटे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो एक छोटा आंकड़ा नहीं है। कंपनी प्रति दिन 20 लाख खुराक का उत्पादन कर रही है। हमने अकेले भारत में 10 करोड़ से अधिक खुराक दी हैं और अन्य देशों को लगभग छह करोड़ खुराक का निर्यात किया जा चुका है। हम वैक्सीन पर कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। दुनिया में कोई भी दूसरी वैक्सीन कंपनी इतनी घटी कीमतों पर टीके उपलब्ध नहीं करा रही है। सीरम

इंस्टीट्यूट अन्य के मुकाबले भारत की अस्थाई जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। कंपनी वर्तमान में छह से सात करोड़ टीके प्रति माह उत्पादन कर रही है। उम्मीद है कि कोविशील्ड वैक्सीन की उत्पादन क्षमता हम जून से प्रति माह 11 करोड़ तक बढ़ा देंगे मगर इसके लिए हमें सरकार से मदद चाहिए।

अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार अदार पूनावाला की तीन हजार करोड़ रूपए की मांग पूरी कर पाएगी। फिर देश की अन्य कंपनियां जो वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं क्या वे भी सरकार से ऐसी ही मदद नहीं चाहेंगी?

कोरोना की तेज रफ़्तार और वैक्सीन पर राजनीति

कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन को लेकर राजनीति भी जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हल्ला मचा रखा है। वहीँ कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर ठप हो गए हैं। संक्रमण के दूसरी लहर के चपेट में महाराष्ट्र बिलबिला रहा है मगर यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त खुराकें मौजूद नहीं है। यहाँ हर रोज आने वाले नए मामलों का आंकड़ा 50 हजार से अधिक है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है, ह्यमहाराष्ट्र की आधी जनसंख्या के बराबर गुजरात है। गुजरात को अब तक 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है, जबकि हमें केवल 1।04 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई। राज्य में केवल तीन दिन के लिए 14 लाख वैक्सीन बचे हैं। वैक्सीन की कमी के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द वैक्सीन के 40 लाख डोज उपलब्ध कराएं।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए संघर्ष कर रहे देश के कई राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन की कमी रिपोर्ट की जा रही है। यहां तक कि कई राज्यों में आधे से अधिक वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। देश के संक्रमित राज्यों में महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में वैक्सीन के स्टॉक में आई कमी को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं।

हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन व सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने महाराष्ट्र सरकार की वैक्सीन की कमी के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपनी कमियों को छिपाने के लिए दहशत का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन की कमी और 18 साल से अधिक उम्र के सभी युवाओं को टीका लगाने की मांग संबंधी बयान इसी सिलसिले दिए जा रहे हैं।

दिल्ली के स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब जो वैक्सीन का स्टॉक है, वह केवल अगले 4-5 दिनों तक का ही है। उन्होंने और वैक्सीन की मांग केंद्र से की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की कमी की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ह्यअगले एक-दो दिनों के लिए हमारे पास वैक्सीन का

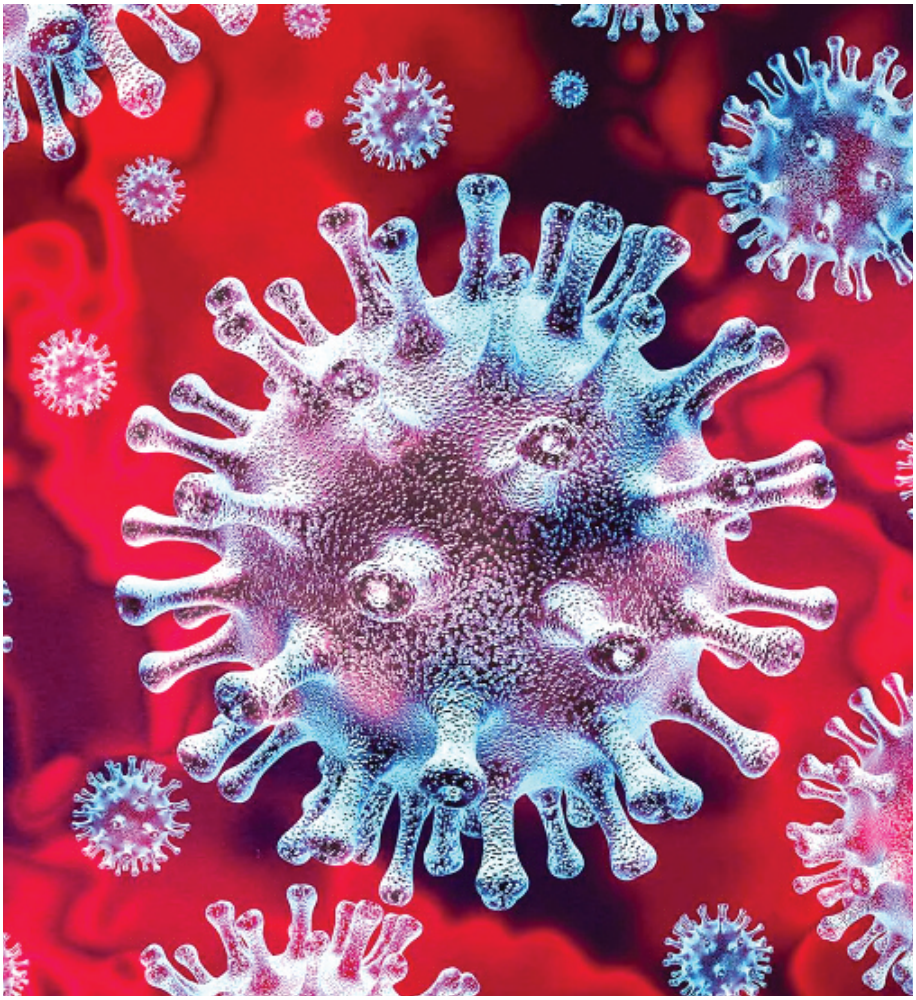

स्टॉक है। हमने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से वैक्सीन की मांग की है और उम्मीद है कि वे इसे पूरा करेंगे।

तेलंगाना में भी कोविड-19 वैक्सीन का काफी कम स्टॉक बचा है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री ई। राजेंद्र के अनुसार केंद्र से कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त डोज की मांग की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के एक करोड़ डोज की मांग की है।

ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वैक्सीन के लिए अपनी मांग रखी है। राज्य सरकार के अनुसार, उनके पास केवल तीन दिन का स्टॉक है। ओडिशा ने केंद्र से कहा है कि राज्य को 15 से 20 लाख कोविशील्ड की डोज उपलब्ध कराई जाए। ओडिशा का कहना है कि राज्य में आधे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं।

विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। उनका आरोप है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सही ढंग से तैयारी नहीं की गयी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नागरिक जागरूक नहीं है, वहीँ जगह जगह से टीके की कमी या इनके खराब होने की खबरों ने स्थिति को और घातक बना दिया है।

सरकार ने रोका वैक्सीन का निर्यात

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते विपक्ष के हमले और किरकिरी से बचने के लिए भारत सरकार से फिलहाल दूसरे देशों को सप्लाई होने वाली कोरोना वैक्सीन पर ब्रेक लगा दिया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत की तरफ से ग्रांट के तौर पर अंतिम सप्लाई 2 अप्रैल को 2 लाख कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बांग्लादेश को की गई है, जबकि कमर्शियल तौर पर अंतिम सप्लाई 29 मार्च को 25 हजार वैक्सीन की फिलिस्तीन को की गई है। जबकी 29 मार्च को ही यमन को कोवैक्स यानी गावी अलायंस के तहत 3।60 लाख कोरोना वैक्सीन भेजी गई हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से करीब 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन की मांग अन्य देशों ने की है। ऐसे देशों की संख्या 50 से भी अधिक है जो भारत से कोरोना वैक्सीन चाहते हैं। ब्राजील से 20 मिलियन की मांग है जबकि अर्जेंटीना भी 20 मिलियन वैक्सीन डोज भारत से चाहता है। भारत से अब तक कुल करीब 65 मिलियन वैक्सीन दूसरे देशों को सप्लाई की गई है। इसमें करीब 11 मिलियन ग्रांट के तौर पर, 38 मिलियन कॉमर्शियल तौर पर और लगभग 18 मिलियन कोवैक्स के तहत भारत ने आपूर्ति की है। भारत अब तक 84 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति कर चुका है।

वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही अब दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति कर पाएगा। हाल के दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ी है वैसी स्थिति में दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति कराना भारत के लिए फिलहाल मुश्किल है। हालांकि इस फैसले की समीक्षा अगले कुछ दिनों में होगी।

बिहार : शराबबंदी का सच

बिहार के गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी शराब कांड में 13 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उनमें से 9 लोगों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। बिहार (ठपींत) के गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी शराब कांड में 13 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उनमें से 9 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, उन्हीं 9 लोगों में से एक दोषी राजेश चैधरी की पत्नी का कहना है, मेरे पति पेंट का काम करते थे, वो शराब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो खजूरबानी में रहते थे इसलिए उन्हें फंसाया गया कि वो शराब बेच रहे थे। पांच साल पहले गोपालगंज में खजूरबानी इलाके में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में पिछले सप्ताह स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए 13 लोगों को दोषी माना था, जिसमें 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। वहीं, सजायाफ्ता लोगों के परिवार वालों का कहना है कि ये कैसा फैसला है कि पुरुषों को फांसी की सजा दी गई है और महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसी मामले में जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त हुए 10 पुलिस वालों के संबंध में राज्य सरकार के आदेश को न केवल पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया बल्कि सबको वापस सेवा में बहाल ककोर्ट से सजा मिलने के बाद दोषियों के परिवार वालों ने कहा कि पुलिस जो लोग हैं सब झूठे केस बनाकर हम लोग के पति और सास को फांसी और उम्रकैद का सजा दिलवा दिए हैं लेकिन उन लोगों को नौकरी क्यों मिला, हम लोगों को रियायत चाहिए। विद्यार्थी देवी के चार परिजनों को सजा मिली है। वह कहती हैं, इन लोगों को फांसी की सजा क्यों मिली जब पुलिसकर्मी आजाद घूम रहे हैं।

वे लोग गलती किए और वे ही आजाद घूम रहे हैं और पासी लोगों को सजा मिली है। मंजू देवी ने कहा, श्सब नीतीश कुमार की चाल है। राज्य में शराबबंदी हो चुकी है लेकिन 100 फीसदी शराब मिल रही है। क्यों नहीं सब लोगों को बंद करते हैं। पासी लोगों को सजा दे दिए हैं।श्ने का भी आदेश दे दिया। ये गोपालगंज की घटना अपवाद नहीं बल्कि इन दिनों शराबबंदी से संबंधित घटनाओं में तेजी से सुनवाई हो रही है। दरभंगा में प्रेम चंद साहनी को तो पांच लीटर शराब बरामदगी के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है और साहनी पर एक लाख का जुमार्ना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने इस बारे में कहा, श्शराब रखने के जुर्म में पांच साल का साधारण कारावास और एक लाख रुपये का अर्थ दंड और न देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।श इन दिनों पूरे बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी चारों और जमकर छापेमारी कर रहे हैं। हर जगह भारी मात्रा में शराब की जब्ती हो रही है। कई जगह पर शराब के गोदाम को थाने में भी बदला गया है लेकिन बिहार में विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथनी और करनी में फर्क है। मंत्री के भाई की जमीन पर शराब मिलने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, श्अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका नियम हैं कि जिस जमीन पर शराब मिलेगी तो वहां थाना या विद्यालय बनाया जाएगा। सत्ता संरक्षण देने का काम कर रही है।श वहीं नीतीश कुमार के पास उनकी सरकार द्वारा चार महीने तक इस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसका कोई जवाब तो नहीं लेकिन वो कहते हैं, श्जब तक हैं छोड़ेंगे थोड़े ही, हम तो पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। पहले की तुलना में कितनी ज्यादा कार्रवाई हो रही है, कितने बाहर के लोग पकड़े जा रहे हैं। हर तरफ कार्रवाई हो रही है। आप लोग भी नजर बनाए रखे हैं।

कांग्रेस से डरी हुई डबल इंजन सरकार

कांग्रेस पार्टी का सब से खराब समय होने के बावजूद भाजपा को आज भी उस की आहट डरा रही है। मोदी और शाह अपनी सरकार के कार्यकाल की रीतिनीति और उपलब्धियों का बखान करने की जगह कांग्रेस के 70 साल का अपना पुराना राग आलाप रहे हैं। इस डर के पीछे आखिर वजह क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्रांउड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 मिनट के भाषण में अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी व राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के बजाय कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहे। उन के भाषण से यह लग रहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की नहीं, बल्कि कांग्रेस की सरकार चल रही हो।प्रधानमंत्री ही नहीं, भाजपा के तमाम दूसरे नेता भी बंगाल में कांग्रेस विरोध को बुलंद किए हुए हैं।

क्या ये भाजपाई नेता मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का मूल गोत्र कांग्रेस है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस भाजपा के साथ गठबंधन में रह चुकी है। भाजपा वह पार्टी है जिस की स्थापना के प्रेरणास्त्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन का जन्म बंगाल में हुआ था। भाजपा में बंगाल के विचारों-संस्कारों-परंपरा की महक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस से अधिक कांग्रेस को कोसा।असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरूआत करीमगंज से करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ही हमला बोलते कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने असम को नुकसान पहुंचाया है। उस के भ्रष्ट और वोटबैंक आधारित प्रशासन ने असम को भारत का सब से कटा हुआ राज्य बना दिया था। कांग्रेस सरकारों और उस की नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। लोगों को गुमराह करने और वोट लेने में कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है।

आज कांग्रेस असम में तालाचाबी के आसपास घूम रही है जबकि उस के कुछ कार्यकर्ता इस विचारधारा के खिलाफ थे, बता दें कि तालाचाबी एआईयूडीएफ पार्टी का चुनाव चिह्न है। प्रधानमंत्री तालाचाबी शब्द के सहारे कांग्रेस और एआईयूडीएफ पार्टी के चुनावी तालमेल पर हमला कर रहे थे। इस समय असम में सरकार भाजपा की ही है चाहे वह दलबदल से बनी हो।बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिल्ली में हुए बटला हाउस एनकांउटर का जिक्र किया। जिस का पश्चिम बंगाल से कुछ लेनादेना नहीं है। इस का जिक्र करने का मुख्य कारण शायद यही है कि उन्हें तो कांग्रेस को घेरना था। उन्होंने कहा, दिल्ली की अदालत ने बटला हाउस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। आतंकी को फांसी की सजा हो गई। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही थी, तो ममता दीदी आतंकियों के साथ खड़ी दिख रही थीं। यह कैसे उन्होंने कहा साफ नहीं क्योंकि ममता तो कांग्रेस को 1998 में छोड़ चुकी थी।

आतंकियों ने जांबाज पुलिसकर्मी मोहन चंद्र शर्मा को मार दिया था। बंगाल के लोग देखें और सम झें कि कौन देश के साथ खड़ा था और कौन आतंकियों के। बटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में जामिया क्षेत्र में हुआ था।केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, गृहमंत्री और भाजपा के नंबर दो नेता अमित शाह भी कांग्रेस विरोध को ही बारबार दोहरा रहे हैं। असम के मार्गरीटा में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर राज्य को बांट रही है। कांग्रेस ने उन दलों के साथ गठबंधन किया जो देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ है तो केरल में मुसलिम लीग के। बंगाल में उस ने इंडियन सैक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि अजमल के हाथों में असम सुरक्षित नहीं रहेगा। असम के लोग यह तय कर सकते हैं कि उन की भलाई को ले कर कौन चिंतित है -नरेंद्र मोदी या बदरुद्दीन अजमल?बंगाल में बांकुरा की रैली मे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक ही थाली के चट्टेबट्टे हैं। उन्होंने भी दोहराया कि अलगअलग चुनाव लड़ कर भी ये दोनों दल एकदूसरे की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस देश को तोड़ने वालों के साथ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो सीएए कानून लागू करेगी। 2014 तक कांग्रेस ने कैसे देश को तोड़ा यह सफाई देने की जरूरत उन्होंने नहीं सम झी।बंगाल के मिदनापुर में विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस एक छोटी पिछलग्गू पार्टी है फिर नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल ने कांग्रेस की करतूतें देखी हैं, वामदलों का 34 साल का शासन देखा है और तृणमूल कांग्रेस के 10 साल का समय भी। पिछले 70 साल की बरबादी को हम दूर

करेंगे। हमें 5 साल का मौका दे कर देखिए। कांग्रेस ने अलगअलग दलों के साथ मिल कर देश को 70 साल में केवल बरबाद किया है। 44 साल पहले कांग्रेस पश्चिमी बंगाल में राज कर रही थी पर भाजपा को आज भी वही बारबार याद आती है।असम के डिब्रूगढ़ में भी मोदी ने कांग्रेस को ही निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सब से पुरानी पार्टी उन लोगों का समर्थन कर रही है जो चाय से जुड़ी भारत की छवि को तारतार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कांग्रेस को इस के लिए माफ कर सकते हैं? क्या उस को सजा नहीं मिलनी चाहिए? 2004 से 2014 तक चाय के व्यापार में कांग्रेसी दखल कैसे था, यह साफ उन्होंने नहीं किया।असम के गोलाघाट में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस लूट की इंजन है और अपनी खाली तिजोरी को भरने के लिए किसी भी कीमत में सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस एक समय में केंद्र और असम दोनों में सत्ता में थी। कांग्रेस ने दोनों जगहों पर रहने के बाद असम की दोहरी अनदेखी की। उस के दौर में दोहरा भ्रष्टाचार और दोहरी घुसपैठ हुई। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि पिछले 6 सालों में उस ने कितने घुसपैठियों को वापस उन के अपने देश भेजा। नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं ताकि असमी बंगाली अरौर बांग्लादेश के मूल लोग भाजपा से प्रभावित हो सकें।कांग्रेस आलाप बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावप्रचार में भाजपा कांग्रेस विरोध का आलाप करती रही है। जहां कांग्रेस कोई बड़ी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का नाम ले कर भाजपा मोदी के 7 सालों की हुकूमत की असफलता को छिपाना तो चाहती है।

वह यह भी जानती है कि जब भी भाजपा से लोग नाराज होंगे और कोई विकल्प न होने पर वे अपनेआप कांग्रेस को वोट दे देंगे जैसे कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हुआ। भाजपा का कांग्रेस से डर पुराना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। भाजपा ने उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केंद्र सरकार की कुरसी से नीचे उतार अपनी बहुमत वाली सरकार बनाई। उस के बाद भी भाजपा कांग्रेस से डरती रही।2014 व 2019 के बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भाजपा का विजय रथ थम गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने का फिर बहुमत मिला। कांग्रेस की फिर हार हुई। इस के बाद भी भाजपा का कांग्रेस से खौफ खत्म नहीं हो रहा। 5 राज्यों झ बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी इन राज्यों में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में नहीं है। मोदीशाह की जोड़ी कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी दल मान कर उस पर हमला कर रही है, औरों पर नहीं। उसे यह भी लगता है कि कभी दूसरों की जरूरत हो सकती है।मोदीशाह के बयानों को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनाव 5 राज्यों का नहीं, बल्कि लोकसभा का हो रहा है। कांग्रेस के लगातार कमजोर होने के बाद भी भाजपा का डर खत्म नहीं हो रहा। कमजोर होने के बावजूद आज कांग्रेस पूरे देश में मौजूद है हालांकि कम ही राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ने की हालत में है। अधिकतर राज्यों

में उसे चुनाव लड़ने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पर यह उस की कमजोरी नहीं ताकत है। कांग्रेस की यह निर्भरता बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस को महज 25 सीटें दीं। बंगाल में वामदलों ने 92 ही सीटें दीं। असम, केरल और पुदुचेरी में कांग्रेस की हालत थोड़ी बेहतर तो है लेकिन वह पहले से कमजोर हालत में है। असम में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही पर अब वहां उसे 5 दलों के साथ तालमेल करना पड़ा है।पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भाजपा आईटी सैल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए अपशगुन हैं। वे पुदुचेरी गए तो वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई। राहुल गांधी से अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारें डरने लगी हैं जहां कांग्रेस बहुमत में है। महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों को भी सचेत हो जाना चाहिए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस में जो मुकाम हासिल हो चुका है वह और किसी गांधी को हासिल नहीं हुआ है। निशाने पर गांधी परिवारकांग्रेस के जी-23 गुट ने कांग्रेस की पतली हालत के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार माना है। इस पर भी कांग्रेस का इतिहास और उस की यूनिटों की हर जगह मौजदूगी से भाजपा को लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर उस के मुकाबले कोई दल है तो वह कांग्रेस ही है। इस कारण भाजपा कांग्रेस का विरोध ही नहीं कर रही, कांग्रेस में विभाजन को भी हवा देने का काम कर रही है। इस के तहत ही कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद का संसद भवन में नरेंद्र मोदी द्वारा महिमामंडन किया गया। भाजपा कांग्रेस में ऐसे लोगों को हवा देने का काम कर रही है जो पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हुए गांधी परिवार को दरकिनार करने के लिए आवाज उठाएं।

भाजपा को लगता है कि यदि गांधी परिवार नहीं रहा तो ही कांग्रेस समाप्त हो सकेगी।उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी को भाजपा ने पूरा सहयोग दिया। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के विरोध का कोई मौका जाने नहीं देती हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से वर्तमान में सांसद हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति की तुलना करते हुए राहुल गांधी ने अपने विचार रखे, तो स्मृति ईरानी ने उन के बयान को उत्तर भारत का अपमान बताना शुरू कर दिया।भाजपा और संघ दोनों को कांग्रेस से अधिक गुरेज गांधी परिवार से है। वे यह जानते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार ही एकजुट रख सकता है। उन्हें यह भी मालूम है कि कांग्रेस में सब का दिमाग एक जैसा है। गांधी परिवार के हटते ही कांग्रेस में अलगअलग विभाजन हो जाएंगे। इसलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस आलाप कर रही है ताकि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला दे कर उस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सकें।

कांग्रेस में राहुल-प्रियंका की जोड़ी भाजपा की परेशानी का सब से बड़ा सबब बन रही है। कांग्रेस ने अपने बहुत सारे विचारों को दरकिनार कर तालमेल की राजनीति करनी शुरू कर दी है जिस से भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। महाराष्ट्र इस का एक बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया पर भाजपा को हमेशा राहुल और प्रियंका पर आक्रामक होते देखा जा सकता है। 2024 के भावी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ भाजपा को रोक सकती है। कांग्रेस ने जिस तरह से उदार हिंदुत्व को अपनाना शुरू किया है उस से भाजपा में चिंता की लहर दौड़ पड़ी है।भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी जब पूर्वोत्तर के राज्यों में बोलते हैं तो भारत के पश्चिमी राज्यों के खिलाफ जहर उगलते हैं। जब वे दक्षिण के राज्यों में जाते हैं तो उत्तर के राज्यों के खिलाफ जहर उगलते हैं। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि विभाजन की राजनीति अब काम नहीं करेगी। 1947 में जो कांग्रेस शासन में आई थी वह आज की भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा रूढ़िवादी थी। सिवा जवाहरलाल नेहरू, उस के सारे नेता घोर परंपरावादी थे और ज्यादातर की संतानें अब भाजपा में हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल का दलबदल तो नरेंद्र मोदी ने जबरन कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद बिना उन की सहमति के करा लिया। 1947 और 2021 में कांग्रेस में बहुत फर्क हुआ है पर भाजपा को आज भी जो डर सता रहा है वह उस के नेताओं के बयानों से स्पष्ट है। भाजपा नेता अब तरहतरह से राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। भाजपा के फायरब्रैंड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के पुरुलिया में हुई रैली में राहुल गांधी के खिलाफ हुंकार भरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल और ममता दीदी जय श्रीराम के नारे से चिढ़ते हैं। 2014 से पहले ये लोग मंदिर में जाने से डरते थे। देश के अंदर ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी जो मानती थी कि मंदिर में जाने पर उस का सैक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। अब ममता दीदी मंदिर में जा कर चंडीपाठ कर रही हैं और राहुल गांधी भी मंदिर में जा कर माथा टेक रहे हैं।वहीं, जनता को अब वे सारी बातें यकीन में बदलती दिख रही हैं जिन के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी सम झाया था। राहुल गांधी ने सीएए, एनआरसी, घुसपैठ, तालाबंदी, नोटबंदी, जीएसटी और चीन विवाद जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जो सवाल उठाए थे, समय के साथसाथ वे सब सच साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच राहुल गांधी का भरोसा बढ़ रहा है। यह भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे सकता है। ऐसे में भाजपा इस भरोसे को खत्म करने के लिए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस विरोध का राग ही आलाप रही है।

तीरथ सिंह बने मुख्यमंत्री 'अपना पत्ता' किया फिट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटा कर भाजपा ने अपने नेताओं को संदेश देने का काम किया है कि हर विद्रोह को दबाया जाएगा। कांग्रेस की तरह अब भाजपा में भी विद्रोही स्वरों को दबाने के लिए पार्टी नेताओं पर हाईकमान के फैसले थोपे जाने की शुरूआत हो गई है। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं के बीच विद्रोह का प्रभाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर न पड़े, इस के लिए पार्टी हाईकमान ने स्थानीय नेताओं की राय जाने बिना अपने फैसले से नया मुख्यमंत्री चुना। स्थानीय नेताओं के गुस्से को दबाने के लिए ऐसा फामूर्ला 80 के दशक में कांग्रेस में अपनाया जाता था, जिस में कांग्रेस हाईकमान ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्रियों को बदलता था। वर्ष 1982 में श्रीपति मिश्रा अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इस के पहले वे विधानसभा अध्यक्ष भी थे।

श्रीपति मिश्रा ने वाराणसी तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी। 1962 में वे पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। कई महत्त्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कभी उन का नाम नहीं लिया गया। अचानक 19 जुलाई, 1982 को उस समय की कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने श्रीपति मिश्रा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया 2 अगस्त, 1984 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्रीपति मिश्रा को जिस दौर में मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता थे। साल 2000 में श्रीपति मिश्रा से जब मेरी उन के लखनऊ स्थित सरकारी आवास में मुलाकात हुई थी तब सरस सलिल के लिए रिटायर मुख्यमंत्री के रूप में उन से बात की थी। उस समय उन्होंने कहा था, उन के नाम पर कोई विवाद नहीं था,

इस कारण हाईकमान उन को पंसद करता था। हाईकमान ने ही उन को मुख्यमंत्री बनाया था। 1980 के बाद जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया तो राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायकों की जगह हाईकमान के हाथ में आ गया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अफसर की तरह बनाया और हटाया जाता था। कहावत थी कि मुख्यमंत्री ताश के पत्तों की तरह से फेंटे जाते थे। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेसशासित हर राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव का काम हाईकमान करता था। कांग्रेस का हाईकमान तब इतना पावरफुल था कि उसे लगता था कि राज्यों में चुनाव उस के नाम पर जीता जाता है। ऐसे में उसे मनचाहे ढंग से मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है। कांग्रेस की इस सोच से दमदार नेताओं का पतन शुरू हो गया। परिणामस्वरूप एक दशक में ही पार्टी का राज्यों से जनाधार टूटने लगा। पार्टी सिमटने लगी। विरोध को दबाने के लिए उत्तराखंड से निकला संदेश श्रीपति मिश्रा का जिक्र उत्तराखंड में बनाए गए नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के संदर्भ में कर रहे हैं। ताश के पत्तों की

तरह फेंटे जाने की कांग्रेसी बीमारी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान ताकतवर हाईकमान को भी लग चुकी है।

साल 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया। 21 सालों में 10 मुख्यमंत्री कुरसी पर बैठ चुके हैं। यह हालत तब हुई जब उत्तराखंड में सत्ता कभी कांग्रेस और कभी भाजपा के साथ रही। दोनों ही दलों ने मुख्यमंत्री के नाम पर अपनेअपने नेताओं को ताश के पत्तों की तरह फेंटा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। भाजपा विधायक मंडल दल की मीटिंग में नए नेता के रूप में सब से पहले तीरथ सिंह रावत का नाम चुना गया। तीरथ सिंह रावत के नाम पर हाईकमान की मोहर पहले ही लग चुकी थी, इस कारण विधायक मंडल दल की मीटिंग में कोई हंगामा या विरोध नहीं हुआ। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पूरे प्रकरण पर नजर रखे थे। अगले साल उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना है। इस फेरबदल से विधायकों की नाराजगी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल, राज्यमंत्री धन सिंह रावत, सत्यपाल महाराज, अजय भट्ट और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी जैसे कई नाम दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे।

सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम चर्चा से बाहर था। इस के बाद भी जब उन को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सभी को हैरानी हुई। ऐसे में यह चर्चा होने लगी कि तीरथ सिंह रावत इतने ताकतवर कैसे हो गए कि भाजपा ने उन को मुख्यमंत्री बना कर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेनापति बना दिया। तीरथ सिंह रावत संघ यानी आरएसएस के प्रमुख सदस्य रहे हैं। संघ की विचारधारा का उन पर बहुत असर है। संघ परिवार के करीबी पौड़ी जिले के सीरों गांव के रहने वाले तीरथ सिंह रावत 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। 1997 में वे उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद के सदस्य बने। साल 2000 में जब अलग उत्तराखंड का गठन हुआ तो अंतरिम सरकार में वे पहले शिक्षामंत्री बने। 2007 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 2012 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। गुटबाजी के चक्कर में 2017 के विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायक होने के बाद भी उन का टिकट काट दिया गया। 2019 में लोकसभा का टिकट पा कर सांसद बने। मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी सियासी चर्चा में इन का नाम नहीं आया था। तीरथ सिंह रावत का नाम संघ और संगठन के मेहनती नेता के रूप में लिया जाता था। यही वह गुण था जिस की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में वे लोकसभा की अपनी सीट से इस्तीफा देंगे और फिर उत्तराखंड विधानसभा की किसी सीट को खाली करा कर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तीरथ सिंह रावत ने मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में कहा, केंद्रीय नेतृत्व से बात कर के कैबिनेट का गठन होगा। इस बयान से भी साफ है कि हाईकमान का कितना प्रभाव है। यही कुछ फामूर्ला उत्तराखंड के बड़े भाई कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में पहले किया जा चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई।

मुख्यमंत्री का नाम चुनने में भाजपा के नेताओं को दरकिनार कर के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वह फैसला भी हाईकमान का था। योगी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की सब से बड़ी वजह यह थी कि उन को भाजपा धर्म का ब्रैंड बनाना चाहती थी। आज भाजपा हर प्रदेश के चुनाव में योगी का प्रयोग धर्म के चेहरे के रूप में कर रही है। विवादों से निबटने की जुगत चुने गए विधायकों की जगह पर हाईकमान द्वारा थोपे जाने वाले नेताओं को कुरसी पर बैठाने के पीछे प्रदेश के नेताओं में होने वाले विवाद हैं। कांग्रेस में भी 1980 के बाद ऐसे विवाद शुरू हो गए थे। 2014 में लोकसभा चुनाव जीत कर भाजपा ने जब केंद्र में सरकार बनाई तो कई प्रदेशों में उस ने ऐसे नेता चुने जिन की कोई खास पहचान न थी। नए चेहरों को आगे लाने का काम भाजपा ने हर स्तर पर शुरू किया।

हालांकि, ज्यादातर ऐसे चेहरे सफल नहीं हुए। इस से पार्टी के अंदर बगावत तेज होने लगी। उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायकों ने विधानसभा में ही धरना दिया था। ऐसे में अब भाजपा हाईकमान ने अपने मन से फैसले करने शुरू कर दिए हैं। या यों कहें कि कांग्रेस की तरह अब भाजपा ने भी हाईकमान स्तर पर फैसले थोपने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन के खिलाफ भाजपा में विद्रोह था। भाजपा ने चुनाव के पहले अपने 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को हटाना उचित न सम झा, परिणामस्वरूप रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा वहां चुनाव हार गई। अब भाजपा विद्रोह करने वाले अपने नेताओं की नाराजगी को खत्म करने के लिए हाईकमान स्तर पर फैसले लेने लगी है। भाजपा अप्रत्याशित रूप से ऐसे नेताओं का चयन करने लगी है जो विवादों से निबटने में सफल होते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटा कर भाजपा हाईकमान ने अपने नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है कि उन के विद्रोह को दबा दिया जाएगा।

मसौढ़ी फुलवारी शरीफ दानापुर मनेर विक्रम पालीगंज के गरीब लाचार लोगों के दवाईयों का ऑनलाइन पेमेंट मुंबई से कर रहे हैं नौबतपुर वाले आर के शर्मा

समाजसेवी रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए जिस मानवीय उदारता का परिचय दिया है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय है. दूसरे सक्षम लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. जनप्रतिनिधि अगर अपने-अपने क्षेत्र के लोगों की मदद का बीड़ा उठा लें तो संकट की इस घड़ी में मानवता की यह बड़ी सेवा होगी. मूल रूप से नौबतपुर थाना अंतर्गत कोपा कला गांव निवासी रमेश कुमार शर्मा ने नौबतपुर लाख निसरपुरा शहर रामपुर पिपलावा मसौढ़ी पालीगंज अरवाल मसोढा दुल्हिन बाजार कन्पा पतूत लई दानापुर सगुना मोर नेउरा खगौल फुलवारीशरीफ जानीपुर बभनपूरा महंगूपुर पुनपुन इलाके के सैकड़ों लोगों की मदद

इस नंबर पर कॉल करने के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके के गरीब लोगों के दवाओं का खर्च आर के शर्मा द्वारा वाहन किया जा रहा है उन्होंने काफी अच्छी तकनीक विकसित की है कि अगर कोई लाचार व्यक्ति दवा खरीदने दवा दुकान पर जाता है और उसके पास पैसा नहीं है तो दवा दुकानदार उनके द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर उस मरीज का डिटेल और उसका बिल पर्ची भेजता है तो तुरंत उनके टीम के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है जिससे फजीर्वाड़े की भी आशंका नहीं होती.

की है. उनकी टीम के तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है । इस नंबर पर कॉल करने के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके के गरीब लोगों के दवाओं का खर्च आर के शर्मा द्वारा वाहन किया जा रहा है उन्होंने काफी अच्छी तकनीक विकसित की है कि अगर कोई लाचार व्यक्ति दवा खरीदने दवा दुकान पर जाता है और उसके पास पैसा नहीं है तो दवा दुकानदार उनके द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर उस मरीज का डिटेल और उसका बिल पर्ची भेजता है तो तुरंत उनके टीम के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है जिससे फजीर्वाड़े की भी आशंका नहीं होती.पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके तथा अपने हलफनामा में देश मे सबसे ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा देने वाले उम्मीदवार रहे उद्योगपति रमेश कुमार शर्मा बिहार के एक चर्चित आईपीएस अधिकारी के जीवन पर वसुंधरा जैसी हिंदी फिल्म बनाकर चर्चा में पहले ही आ चुके हैं ने कोरोना के कहर के बीच पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक अनूठी पहल की है . उन्होंने क्षेत्र के सभी दवा दुकानदारों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में अगर कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में दवा नहीं खरीद पाता तो आप उन्हें तुरंत दवा दीजिए और हाथों हाथ मेरे द्वारा दिए नंबर पर फोन कीजिए.आपको ऑनलाइन पेमेंट हमारी तरफ से किया जाएगा. यह सुविधा दानापुर, सगुनामोड़, फुलवारीशरीफ नौबतपुर ,मसौढ़ी ,बिक्रम ,पालीगंज और मनेर इलाके के लोगों के लिए उपलब्ध है.

रमेश कुमार शर्मा ने नवी मुंबई में फंसे बिहार के लोगों की सहायता के लिए भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इसके माध्यम से लोग उनकी टीम से संपर्क कर लॉक डाउन की स्थिति में भोजन और आवास की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. मुंबई से दूरभाष पर बात करते हुए रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जो कुछ भी क्षेत्र के लोगों के लिए हो सकता है वह सब कुछ मैं मुंबई से बैठे बैठे अपनी टीम के

माध्यम से कर रहा हूं . पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव में मैसेंजर के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी भेजी है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, लाचार है और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं तो वह दवा दुकान में जाए अपनी पर्ची दे और दवा दुकानदार उसकी पर्ची और जो पैसा होता है उसका बिल उनके द्वारा दिए गए नंबर पर भेजे. तुरंत रमेश जी की टीम ऑनलाइन पेमेंट करेगी.

पटना जिले के नौबतपुर थाना अंतर्गत कोपा कला गांव निवासी रमेश कुमार शर्मा मुंबई में बड़े व्यवसायी हैं. उन्होंने अपने दिवंगत पिता परशुराम सिंह की स्मृति में श्री परशुराम सिंह फाउंडेशन और माता जी की स्मृति में लखपति फाउंडेशन तथा पत्नी के स्मृति में लता फाउंडेशन का निर्माण किया है. इन संस्थाओं के माध्यम से वे सामाजिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहते हैं. पटना में उनका मुख्यालय नौबतपुर सिनेमा हॉल भवन है जहां से उनके कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हैं.

सारण प्रमंडल में जन जागरूकता अभियान में जुटी फिल्म अभिनेत्री ख्याति सिंह

कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में पूरी टीम के साथ उतरी भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री ख्याति सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की है पत्नी सारण प्रमंडल के दर्जनों पंचायतों में लोगों के बीच सैनिटाइजर मास्क का इनके टीम के द्वारा किया गया वितरण. लोगों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान. अरनव मीडिया की देखरेख में इनके द्वारा चलाया जा रहा है कोरोना जन जागरूकता अभियान हाईटेक तरीके से मोबाइल रेडियो के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है सही जानकारी. तरैया मसरख पानापुर महाराजगंज बनियापुर एकमा माझी गोरियाकोठी इलाके में विदेश से विगत एक महीने के बीच आए लोगों के सूची भी तैयार कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता .लोगों से डरने से नहीं बल्कि लोगों से दूरी बनाकर रहने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने नियमित अंतराल पर साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोने खासने और छींकने पर नेपकिन व मास्क का इस्तेमाल करने की भी लोगों को दी जा रही है.

कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिल्म अभिनेत्री ख्याति सिंह ने बताया कि जिस तरह से यह महामारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुकी है ऐसे समय में भारत और खासकर बिहार जैसे राज्य में जन जागरूकता अभियान ही इससे बचने का एकमात्र विकल्प है.

सरकारी एजेंसियों द्वारा जिस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उससे ग्रामीण इलाकों में लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंच पा रही है सामाजिक संगठनों को भी बढ़-चढ़कर इस महामारी से डटकर मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है इसी कड़ी में उनके द्वारा तरैया बनियापुर महाराजगंज बसंतपुर माझी एकमा गोरियाकोठी में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. ख्याति सिंह ने बताया कि अब तक कोरोना का कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढा जा सका है जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है ऐसे में बिहार जैसे जनसंख्या बहुल वाले राज्य में इस महामारी के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है.

बिहार में खासकर वैसे लोगों पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है जो खाड़ी के देशों समेत विदेशों में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं और इन दिनों इस महामारी के फैलने के बाद वापस आ रहे है उन सब के स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की मांग भी उन्होंने सरकार से की है.

राधा कृष्ण मेट्रो सिटी के प्रबंध निदेशक संजय प्रताप सिंह

संजय प्रताप सिंह के पूर्वज छपरा के कोठिया नराव से पटना आकर बस गए थे राजीव नगर में इन लोगों की खेती बाड़ी थी इनके पिता स्वर्गीय श्री राम पदारथ सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जबकि माता श्रीमती राम सिंगारी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला. तीन भाई और एक बहन के भरे पूरे परिवार में यह मझले भाई है।इनकी पढ़ाई-लिखाई पटना में ही हुई पटना के संत माइकल व ए. एन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की. राजीव नगर में जब सरकार ने अधिग्रहण प्रारंभ किया तो इनका परिवार विस्थापित हो गया। जीवन में कई उतार-चढ़ाव देख चुके संजय प्रताप सिंह ने पढ़ाई समाप्त होने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास शुरू किया पर वहां मन न रमा तो फिर ईट भट्ठे के व्यवसाय में पूरी तैयारी के साथ उतर मनेर में इनका खुद का संजय ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग नाम से ईट निर्माण की इकाई प्रारंभ हुई. पर यहां भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कटाव ने 3 वर्ष के अंदर ही इनके अच्छे खासे व्यवसाय को बर्बाद कर दिया. फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 1998 में राधे कृष्ण रियल ई एस्टेट नाम से अपनी कंपनी की शुरूआत की यहा किस्मत ने साथ दिया और व्यवसाय चल निकला पुनः 2007 में राधे कृष्ण मेट्रो सिटी का निर्माण कर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उतरे तथा राधे कृष्णा, राधे श्याम, राधे गोविंद और गोवर्धन गिरिराज नाम से 4 अपार्टमेंट का निर्माण पटना के गोला रोड मे किया. पटना के नवनिर्माण में उनका अहम योगदान रहा उन्होंने काफी साफ-सुथरे तरीके से अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया पटना के गोला रोड में राधे कृष्ण सिटी बसा दी. संजय जी कहते हैं कि 2005 से 2012 तक रियल स्टेट का व्यवसाय काफी बेहतर था प्राइस बढ़ रहा था रजिस्ट्री वैल्यू ठीक थी लेकिन सरकार के पास रिपोट पहुंचा कितयशुदा सर्किल रेट से ज्यादा बिल्डर ले रहे हैं तब सरकार ने एकाएक की रजिस्ट्री कॉस्ट में वृद्धि कर दी .सड़क बिजली पानी में शुरूआती दौर में नीतीश सरकार ने काफी बेहतर काम किया पर 2013 के बाद यह दौर थम सा गया .

पटना का सबसे ज्यादा विकास गोला रोड की तरफ हुआ।उसके बाद शिवाला होते हुए जमीन की चाह में लोग बिहटा की तरफ चले गए जितने भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं सब लोग रेरा का समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि वह बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि रेरा कानून आने के पहले जितनी भी बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ तथा उन बिल्डिंग का निर्माण हुआ और बिल्डर तथा ग्राहकों के बीच कोई विवाद नहीं है.

सरकार उन बिल्डिंगों की रजिस्ट्री ओपन करें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा की बिहार में रोजगार का सृजन होगा तभी पलायन रुकेगा यह सरकारी बिहार नहीं है यह हम सबका बिहार है और इस बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी है. रेरा के गठन के बाद बालू बंदी ने रियल एस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोजगार के लिए भूखमरी ला दिया .वे कहते हैं कि पूरे देश नहीं दुनिया में सबसे सस्ता श्रम बिहारियों का है बिहारी जहां भी जाते हैं अपनी कर्मठता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों से बिहार सरकार के पास पलायन रोकने और बेरोजगारी दूर करने का कोई भी प्लान ही नहीं अपने व्यवसाय के शुरूआती दिनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि 2005 से 2012 तक सबसे बेहतर माहौल रहा फिलहाल संजय प्रताप सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और भाजपा एन आर आई सेल से जुड़े हुए

है।पटना महानगर भाजपा एन आर आई सेल के अध्यक्ष है। इस सेल का गठन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश दौरे के बाद हुआ है और इसका मकसद है कि प्रत्येक राज्यों में सेल का गठन कर अप्रवासी भारतीयों से निवेश के लिए देश में माहौल तैयार किया जाय.उन्होने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है . वर्तमान समय में भी सामाजिक कुरीतियों व सामाजिक समानता के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष यही समाज कर रहा है.

मेहनत के बल पे अपने तकदीर की तस्वीर बदल रहा एक मिसाल हैं मिथुन राज

वक्त वक्त पर बदलाव जरूरी हैं तभी तो जिंदगी का दौर बदलेगा हमारी जन्म हमारे हाथ में नहीं पर जिंदगी कैसी हो इस तकदीर की तस्वीर तय करना जरूर हमारे कर्मों पर निर्भर करता हैं ये बात कहना आसान हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल लेकिन कुछ लोगों में मिथुन राज जैसा जज्बा होता हैं जो अपने कर्मों से तकदीर की तस्वीर बदल देते हैं ।

मिथुन राज का जन्म पटना के पतूत पंचायत के पकरंधा गांव के एक निम्नवर्गीय परिवार में हुआ, किसान परिवार का बेटा बचपन से ही रंगीन दुनियां के सपने देखने लगा फिल्मों में गहरी दिलचस्पी ने जिंदगी का रुख हमेशा के लिए फिल्मों की ओर मोड़ दिया परिवार अपेक्षाओ के विपरीत मिथुन ने बड़े शहर की ओर चले गए जहां करियर की दिशा तय होने वाली थी पर नादान मन के द्वारा लिया निर्णय इतना आसान कहां होना था बड़े शहर में काफी धोखे खाने के बाद धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी उसी समय एक नजदीकी दोस्त सुवेष की सलाह पर यशी फिल्म्स ट्रेनिग इन्स्टिट्यूट में फिल्म निर्माण ऐक्टिंग के साथ और भी कला सीखा ट्रेनिग के दौरान अनिकेत और सुरेश जैसे दोस्तों का साथ मिला जिन्होने करियर निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी फिर नये सिरे से करियर की शुरूवात कर जल्दी ही ये मेहनत रंग लायी बड़े चैनेल पर नामी प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिला और नयी नयी जिम्मेदारी मिलते चले गए अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नयी सीढ़ी चढ़ने लगे आज बड़े बड़े प्रॉडक्ट्सन हाउस से मिथुन राज को बुलाया जाता हैं और सुप्रसिद्ध कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुके हैं मिथुन राज फिल्म इंडस्ट्री में अपना गुरु अभय सिन्हा को मानते हैं जिन्होने करियर को सही दिशा दिखाया और इस काबिल बनाया यशी फिल्म्स के पंकज तिवारी हमेशा मिथुन का पथप्रदर्शन करते हुए आज अभीभावक की तरह काम करने के नये नये आधुनिक विधियां सिखाते हैं इसके वजह से ही वो आज अपने समाज के लिए आदर्श बन सके हैं ।

आज मिथुन राज गंगा चैनेल के बिग मेमसाब, मेमसाब नंबर-1.

एंटरटेनमेंट का मेला, रोज होई भोज जैसे बड़े कार्यक्रमों के हर सीजन में फ्लोर डाइरेक्शन का कार्य निरंतर देख रहे हैं इसके अलावा नये उभरते कलाकारों के लिए बड़े मंच उपलब्ध करवा रहे हैं ।

हाल ही में अपनी राजनीतिक शुरूवात भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के लोक संगीत विभाग पटना महानगर से कर चुके हैं बदलाव को अपने जीवन का अंग मान चुके मिथुन का मानना हैं एक विकासशील सोच से समाज की सेवा की जा सकती हैं सशक्त निर्णय से बिहार राज्य में कलाकारों के बड़े मौके उपलब्ध करवाया जा सकता हैं सरकार और कलाकार के बीच का समन्वय एक सच्ची मानसिकता के साथ चलने वाला दल ही कर सकता हैं इसी निश्चय के साथ राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं ।

बिहार के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं नरेंद्र सिंह

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य, कृषि एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री,आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी की पहल से बड़ी संख्या में युवाओं को पूरे बिहार के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में बंद पडे वेंटिलेटर(जीवन रक्षक मशीन) को चलाने हेतु वेंटिलेटर ऑपरेटर और नर्सिंग स्टाफ की नौकरी मिलने जा रही है।

बिहार के स्वास्थ्य,कृषि एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कुछ दिनों पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी,स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी को सुझाव दिया था एवं उन्होंने सरकार से माँग की थी कि बिहार के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर को चालू किया जाये।जिससे कि इस कोरोना संकट में गंभीर कोरोना मरीजों की जान वेंटिलेटर मशीनों की सहायता से बचाई जा सके।आदरणीय पूर्व मंत्री ने माँग की थी कि

वेंटिलेटर ऑपरेटर का कुशलतापूर्वक संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किए युवाओं और नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को जिले के सदर अस्पतालों में तत्काल बहाली की जाये।

आदरणीय पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी के इस सुझाव को मानते हुए सरकार ने बिहार के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में वेंटिलेटर ऑपरेटर और नर्सिंग स्टाफ की बहाली करने का निर्णय लिया है।

जमुई जिले अंग प्रदेश समेत संपूर्ण बिहार के ऐसे युवा जिन्हें वेंटिलेटर मशीन को कुशलतापूर्वक संचालित करने का ज्ञान है तथा ऐसे युवा जिन्होंने नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिले के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के समक्ष प्रशिक्षण का प्रमाण प्रस्तुत कर इन पदो पर नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

आदरणीय पूर्व मंत्री जी को सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट कराने के लिये समस्त प्रदेशवासियों की और से कोटि-कोटि आभार और धन्यवाद।

सारण के प्रभारी मंत्री बनाए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह

छपरा। जमुई जिले के चकाई से निर्दलीय विधायक व नीतीश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह को सारण का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना 339,1 मई 2021 के अनुसार जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में सुमित कुमार सिंह का मनोनयन सारण के लिए किया गया है।सुमित कुमार सिंह बिहार के किला के निर्दलीय विधायक हैं जो जमुई जिले के चकाई से चुनाव जीते हैं उन्हें नीतीश सरकार में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। सारण का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर सुमित कुमार सिंह के निजी मीडिया प्रभारी व सारण जिले के मशरख प्रखंड के अरना गांव निवासी फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य अनूप नारायण सिंह, अधिवक्ता सह वरिष्ठ भाजपा नेता सोनपुर ओम कुमार सिंह, अमनौर से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह मंटू तरैया से भाजपा विधायक जनक सिंह माझी से निर्दलीय प्रत्याशी रहे राणा प्रताप सिंह ने उन्हें बधाई दी है। मंत्री सुमित कुमार सिंह के निजी मीडिया प्रभारी अनूप नारायण सिंह ने कहा कि उनके सारण के प्रभारी मंत्री बनाए जाने से संकट की इस घड़ी में लोगों को तत्क्षण सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

भारत में सिनेमा का पदार्पण

अनूप नारायण सिंह

7 जुलाई 1896,बंबई का वाटसन थिएटर। लुमीयर ब्रादर्स नामक दो फ्रांसीसी अपनी फिल्में लेकर भारत आये। उक्त थिएटर में उनका प्रीमियर हुआ। प्रीमियर करीब 200 लोगों ने देखा। टिकट दर थी दो रुपये प्रति व्यक्ति। यह उन दिनों एक बड़ी रकम थी। एक सप्ताह बाद इनकी ये फिल्में बाकायादा नावेल्टी थिएटर में प्रदर्शित की गयीं। बंबई का यह थिएटर बाद में एक्सेल्सियर सिनेमा के नाम से मशहूर हुआ। रोज इन फिल्मों के दो से तीन शो किये जाते थे, टिकट दर थी दो आना से लेकर दो रुपये तक। इनमें 12 लघु फिल्में दिखायी जाती थीं। इनमें ह्यअराइवल आफ ए ट्रेनह्ल, ह्यद सी बाथह्ल तथा ह्यलेडीज एंड सोल्जर्स आन ह्वीलह्ल प्रमुख थीं। लुमीयर बंधुओं ने जब भारतीयों को पहली बार सिनेमा से परिचित कराया तो लोग बेजान तसवीरों को चलता-फिरता देख दंग रह गये। हालांकि उन दिनों इन फिल्मों के लिए जो टिकट दर रखी गयी थी, वह काफी थी लेकिन फिर भी लोगों ने इस अजूबे को अपार संख्या में देखा। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इस नयी चीज की तारीफों के पुल बांध दिये। एक बार इन फिल्मो को लोकप्रियता मिली , तो भारत में बाहर से फिल्में आने और प्रदर्शित होने लगीं। 1904 में मणि सेठना ने भारत का पहला सिनेमाघर बमाया, जो विशेष रूप से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए ही बनाया गया था। इसमें नियमित फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा। उसमें सबसे पहले विदेश से आयी दो भागों मे बनी फिल्म ह्यद लाइफ आफ क्राइस्टह्ल प्रदर्शित की गयी। यही वह फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फालके को भारत में सिनेमा की नींव रखने को प्रेरित किया।हालांकि स्वर्गीय दादा साहब फालके को भारतीय सिनेमा का जनक होने और पूरी लंबाई के कथाचित्र बनाने का गौरव हासिल है लेकिन उनसे पहले भी महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण के कई प्रयास हुए। लुमीयर बंधुओं की फिल्मों के प्रदर्शन के एक वर्ष के भीतर सखाराम भाटवाडेकर उर्फ सवे दादा ने फिल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने पुंडलीक और कृष्ण नाहवी के बीच कुश्ती फिल्मायी थी। यह कुश्ती इसी उद्देश्य से विशेष रूप से बंबई के हैंगिंग गार्डन में आयोजित की गयी थी। शूटिंग के बाद फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां से जब वह फिल्म प्रोसेस होकर आयी तो सवे दादा अपने काम का नतीजा देख कर बहुत खुश हुए। पहली बार यह फिल्म रात के वक्त बंबई के खुले मैदान में दिखायी गयी। उसके बाद उन्होंने अपनी यह फिल्म पेरी थिएटर में प्रदर्शित की । टिकट की दर थी आठ आना से तीन रुपये तक। अकसर हर शो में उनको 300 रुपये तक मिल जाते थे। उन्होने भगवान कृष्ण के जीवन पर भी एक फिल्म बनाने का निश्चय किया था लेकिन भाई की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने अपना कैमरा बेच दिया और फिल्म निर्माण बंद कर दिया।इसके बाद 1911 में अनंतराम परशुराम कशंडीकर, एस एन पाटंकर और वी पी दिवाकर ने यह कोशिश जारी रखी। 1920 में इन्होंने बालगंगाधर तिलक की अंत्येष्टि की फिल्म बनायी। 1912 में उन्होंने 1000 फुट की एक फिल्म ह्य सावित्रीह्ल बनायी। यह धार्मिक फिल्में बनाने की शुरूआत थी। नारायण गोविंद चित्रे और आर पी टिपणीस ने दादा साहब तोर्ने के निर्देशन में नाटक ह्य पुंडलीक ह्ल फिल्मा डाला और इसे 1909 में कोरोनेशन थिएटर बंबई में प्रदर्शित किया गया। कलकत्ता में हीरालाल सेन, धीरेन गांगुली, मद्रास में नटराज मुदलियार, महाराष्ट्र में बाबूराव पेंटर तथा अन्य लोग भी इस दिशा में सक्रिय थे।तसवीरें चलती-फिरती हैं, हंसती तथा इशारे करती हैं , सुन कर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। न बोलनेवाली उन तसवीरों को देखने के लिए लोग उतावले हो उठे। पांच दशक पूर्व ह्य टूरिंग टाकीजह्ल यानी चलते-फिरते सिनेमा अधिक थे। किसी बड़ी आबादी वाले शहर या कस्बे में तंबू तान दिया , दीवार कि जगह टीन लगा दी और सिनेमा शुरू । उस जमाने में एक ही प्रोज्क्टर होता था इसलिए फिल्म जितने रीलों की होती थी, उतनी बार प्रोजेक्टर रोकना पड़ता था और उतने ही मध्यांतर हुआ करते थे । परदे के पास बैठनेवाले दर्शकों के लिए काठ की फोल्डिंग कुर्सियां हुआ करती थीं। फिल्म में आवाज के सिवा सब कुछ होता था- बातचीत का हावभाव, मारपीट, घुड़सवारी वगैरह। सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ी, तो धीरे-धीरे कुछ सिनेमाघर भी बनने लगे। चूंकि वह अवाक फिल्मों का युग था इसलिए कहीं-कहीं पर सिनेमा प्रोजेक्टर का आपरेटर दर्शकों को समझाने के लिए फिल्म की कहानी उसी तरह बताता जाता था, जिस तरह आजकल कमेंटेटर खेल का आंखों देखा हाल बताता है। जब खलनायक के चंगुल में फंसी नायिका सहायता के लिए चिल्लाती और नायक घोड़ा दौड़ाता हुआ आता, तो आपरेटर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाते हुए बताता-अब आ रहा है नायिका का बहादुर प्रेमी, जो खलनायक को मार-मार कर भुरता बना देगा। कभी-कभी फिल्म के संवाद परदे पर लिखे दिखते थे। अगर फिल्म की कहानी आगे छलांग लगवानी होती तो बीच की घटनाएं लिख कर बता दी जाती थीं।अवाक फिल्मों के जमाने में लोग चलती-फिरती तसवीरों का आनंद लेने जाते थे। फिल्म में कौन काम कर रहा है, इसके प्रति उनका विशेष आकर्षण नहीं था। कलाकारों की लोकप्रियता तो तब बढ़ी , जब फिल्में बोलने लगीं । प्रारंभ में धार्मिक फिल्में ही ज्यादा बनती थीं। भारत की पहली फिल्म ह्यराजा हरिश्चंद्र ह्ल भी धार्मिक फिल्म थी। उस समय की कुछ प्रमुख अवाक धार्मिक फिल्में थीं फालके फिल्म कंपनी की- राजा हरिश्चंद्र, भस्मासुर मोहनी, सत्यवान-सावित्री और लंका दहन, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की झकृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, बालि-सुग्रीव, नल-दमयंती, परशुराम, दक्ष प्रजापति, सत्यभामा विवाह, द्रौपदी वस्त्रहरण, जरासंध वध, शिशुपाल वध, लव-कुश, सती महानंदा और सेतुबंधन, महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की- वत्सला हरण, गज गौरी, कृष्णावतार, सती पद्मिनी, सावित्री, मुरलीवाला तथा लंका, प्रभात फिल्म कंपनी की- गोपालकृष्ण। इसके अलावा कुछ और प्रयास हुए, जिनमें दादा साहब फालके की 1932 में बनी अवाक फिल्म ह्य श्यामसुंदरह्ल।उस वक्त धार्मिक फिल्मों की एक तरह से बाढ़ आ गयी थी। इसकी वजह यह कि उन दिनों भारतीय मानस में धर्म बड़े गहरे तक पैठा था और उसके प्रति लोगों में गहरी आस्था थी। नाटकों और रामलीला में धार्मिक कथाएं दिखायी जाती थीं, धार्मिक कथाओं से लोगों ने एक तादाम्य-सा स्थापित कर लिया था,इसलिए ऐसी फिल्में समझने में दिक्कत नहीं होती थी। उन दिनों धार्मिक झपौराणिक फिल्में कामयाब भी

होती थीं। ऐसा नहीं है कि तब अन्य किस्म की फिल्में नहीं बनती थीं, लेकिन प्रधानता धार्मिक फिल्मों की थी। यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि महिला पात्र की भूमिका निभाने के लिए महिलाएं काफी अरसे तक नहीं मिलीं। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की ह्यकीचक वधह्न तक यह स्थिति बरकरार रही। इस फिल्म में भी कीचक की पत्नी की भूमिका सखाराम जाधव नामक एक युवक ने की थी। इन सारी मुसीबतों और अड़चनों के बावजूद धार्मिक फिल्मों की यात्रा जारी रही और बोलती फिल्मों के युग तक इनका सिलसिला चलता रहा। इनके कथानक का आधार मूलतः रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य होते थे। राम-कृष्ण की जीवनलीला पर फिल्में बनीं , हनुमान जी पर और संतो-देवताओं पर फिल्में बनीं।बाद में मां की भूमिकाओं के लिए मशहूर निरुपा राय कभी धार्मिक फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थीं। उन्होंने कुल मिला कर तकरीबन 40 धार्मिक-पौराणिक फिल्मों में काम किया। वे चार फिल्मों में पार्वती और तीन में सीता की भूमिका में आयी थीं। परदे की देवी के रूप में वे इतना ख्यात हो गयी थीं कि जब उन्होंने ह्यसिंदबाद द सेलरह्न, ह्यचालबाजह्न और ह्यबाजीगरह्न जैसी स्टंट फिल्मों में काम किया , तो दर्शकों का उनकी इन फिल्मों के प्रति रुख अच्छा नहीं रहा। धार्मिक फिल्मों में उनकी कितनी धूम थी , इसका पता इससे चलता है कि लोग जिन सिनेमाघरों में उनकी धार्मिक फिल्में देखने जाते, वहां पूजा करते थे। उनकी धार्मिक फिल्में थीं-महासती सावित्री, सती मदालसा, नवरात्रि, चक्रधारी, रामस्वामी, वामन अवतार,गौरी पूजा, शेषनाग, अप्सरा, चंडी पूजा, जय हनुमान, राम हनुमान युद्ध, नागमणि, श्री रामभक्त विभीषण, नरसी भगत, हर हर महादेव, द्वारकाधीश आदि। इसके बाद उन्होंने कई सामाजिक फिल्मों में भूमिकाएं निभायीं और बाद में चरित्र भूमिकाएं करने लगीं। जयश्री गड़कर भी धार्मिक फिल्मों की होरोइन के रूप में काफी ख्यात हुईं। अपने जमाने में शोभना समर्थ भी धार्मिक फिल्म ह्यरामराज्यह्न की सीता के रूप में बहुत ख्यात हुईं। बाद के दिनों में अनिता गुहा, कानन कौशल आदि काफी

लोकप्रिय हुईं।बहरहाल, फिल्मों के निर्माण के शुरू के दौर में 60 प्रतिशत से भी अधिक फिल्में धार्मिक-पौराणिक कथानक पर बनती थीं। बाद के वक्त में बेरोजगारी से पीड़ित युवा वर्ग की रुचि धर्म में नहीं रह गयी। वह रोजी-रोटी की जुगाड़ में तबाह रहने लगा। ऐसे में धार्मिक फंतासी से उसे खुशी नहीं मिलती थी। वह हलकी-फुलकी मनोरंजक फिल्मों की ओर मुड़ गया। धार्मिक फिल्मों से युवा वर्ग विमुख हुआ, तो ऐसी फिल्में महज पुरानी पीढ़ी के लोगों तक सीमित रह गयीं।धार्मिक फिल्मों के बाद ऐतिहासिक फिल्मों का दौर आया। यह भी काफी लंबा खिंचा। रंजीत स्टूडियो ने 1934 में ह्यराजपूतानीह्न पेश की। इतिहास के प्रसिद्ध चरित्रों और घटनाओं पर फिल्में बनने लगीं। उस वक्त देश का माहौल ऐसा था , जिसमें ऐसी फिल्में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती थीं। वी. शांताराम ने एक फिल्म निर्देशित की ह्यउदय कालह्न जिसका नाम उन्होंने ह्यफ्लैग आफ फ्रीडमह्न (स्वराज्य तोरण) रखा। भला अंग्रेज सरकार को यह नाम क्यों भाने लगा। इस नाम पर एतराज हुआ और यह फिल्म ह्यथंडर आफ हिल्सह्न बन गयी। यह फिल्म वी. शांताराम ने प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर में बनायी थी और इसमें उनकी शिवाजी की भूमिका की बड़ी प्रशंसा हुई थी। 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्में वणकुद्रे शांताराम ने 12 वर्ष की अल्पायु में गंधर्व नाटक मंडली कोल्हापुर में छोटी-छोटी भूमिकाओं से अपना कैरियर शुरू किया। धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते गये। 1929 में उन्होंने कोल्हापुर में प्रभात फिल्म कंपनी चार अन्य लोगों की मदद से स्थापित की। इसके अंतर्गत उन्होंने ह्यमाई क्वीनह्न (रानी साहिबा) , ह्यफाइटिंग ब्लेड (खूनी खंजर), चंद्रसेना और स्टोलन ब्राइड (जुल्म) बनायी। उनकी ये सभी फिल्में अवाक थीं।1931 में ह्यआलमआराह्न से नयी क्रांति आयी। फिल्मों ने बोलना सीख लिया। अब तक फिल्में शैशव को पीछे छोड़ किशोरावस्था में पहुंच चुकी थीं। बोलती फिल्मों का युग आया , तो शांताराम की फिल्मों का भी नया दौर आया। उनकी पहली बोलती फिल्म थी ह्यअयोध्या का राजाह्न (1932)। 1942 में उन्होंने बंबई में राजकमल कलामंदिर की स्थापना की। प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर में ह्यजलती निशानीह्न,

ह्यसैरंध्रीह्न, ह्यअमृत मंथनह्न, ह्यधर्मात्माह्न, ह्यअमर ज्योतिह्न, के अलावा ह्यदुनिया न मानेह्न, ह्यआदमीह्न और ह्यपड़ोसीह्न जैसी सोद्देश्य फिल्में देने के बाद उन्होंने राजकमल कलामंदिर के बैनर तले ह्यशकुंतलाह्न, ह्यमालीह्न, ह्यपर्वत पर अपना डेराह्न, ह्यडाक्टर कोटणीस की अमर कहानीह्न, ह्यमतवाला शायरह्न, ह्यअंधों की दुनियाह्न, ह्यबनवासीह्न, ह्यभूलह्न, ह्यअपना देशह्न, ह्यदहेजह्न, ह्यपरछाईंह्न, ह्यअमर भोपालीह्न, ह्यसुंरगह्न, ह्यसुबह का ताराह्न, ह्यझनक झनक पायल बाजेह्न, ह्यतूफान और दियाह्न, ह्यदो आंखें और बारह हाथह्न, ह्यनवरगह्न, ह्यफूल और कलियांह्न, ह्यस्त्रीह्न, ह्यसेहराह्न, ह्यगीत गाया पत्थरों नेह्न, ह्यलड़की सहयाद्री कीह्न,ह्यबूंद जो बन गयी मोतीह्न, ह्यजल बिन मछली नृत्य बिन बिजलीह्न बनायी। शांताराम की फिल्मों की एक विशेषता रही है कि वे हर मायने में औरों से अलग होतीं। प्रस्तुतीकरण में नवीनता, संगीत में नवीनता और गायन में भी नवीनता`रामशास्त्रीह्न प्रभात चित्र ने उस वक्त बनायी थी, जब वी. शांताराम प्रभात को छोड़ चुके थे। यह फिल्म पेशवाओं के युग के इतिहास पर आधारित भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक फिल्म थी। इतने ऊंचे स्तर की ऐतिहासिक फिल्म उसके बाद नहीं बनायी जा सकी। इस फिल्म को देख कर ही सत्यजित राय फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित हुए। पेशवाओं के शासन के वक्त की सही स्थिति को फिल्म में पेश करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया गया था। कहते हैं कि निमार्ता एस फत्तेहलाल ने इसकी शूटिंग की हुई कई हजार फुट फिल्म रद्द करने की जिद की थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह फिल्म उतनी व्यावसायिक नहीं बन पायी, जितना वे चाहते थे। इसकी पटकथा और संवाद शिवराम वासीकर ने लिखे थे। कोई ऐतिहासिक चूक न रह जाये , इसके लिए पटकथा लेखन के वक्त प्रख्यात इतिहासकारों तक से सलाह ली गयी थी। इस फिल्म में संस्कृत के विद्वान रामशास्त्री द्वारा सत्तालोलुप पेशवा को सन्मार्ग पर लाने के प्रयास की कहानी कही गयी थी। इस फिल्म के तीन निर्देशक थे। इसकी शुरूआती शूटिंग के कुछ अरसा बाद ही राजा नेने ने प्रभात छोड़ दिया। इसके बाद विश्राम बेड़कर ने निर्देशन संभाला, लेकिन उन्होंने भी यह कंपनी छोड़ दी। अंततः गजानन जागीरदार के निर्देशन में यह फिल्म पूरी हुई। गजानन जागीरदार ने इसमें रामशास्त्री की भूमिका भी की थी। ललिता पवार आनंदीबाई बनी थीं । रामशास्त्री के बचपन की भूमिका में अनंत मराठे ने और पत्नी की भूमिका बेबी शकुंतला ने निभायी थी। सप्रू पेशवा माधवराव बने थे।वैसे भारत की पहली ऐतिहासिक फिल्म ह्यनूरजहांह्न 1932 में बनायी गयी थी। इसका निर्माण अदेर्शीर ईरानी ने किया था। इस फिल्म का निर्देशन हालीवुड में फिल्म निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने वाले एजरा मीर ने किया था। यह पहले अवाक फिल्म के रूप में बनायी गयी थी। बाद में बोलती फिल्मों का युग आते ही इसके कुछ खास हिस्से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में डब कर दिये गये। इसके मुख्य कलाकार थे झमजहर खान (पुराने) जमशेदजी , जिल्लू न्यामपल्ली, मुबारक और विमला। इस फिल्म के दोनों संस्करण (हिंदी-अंग्रेजी) बाक्स आफिस पर पिट गये। इसके बाद रमाशंकर चौधरी की फिल्म ह्यअनारकलीह्न आयी। यह भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी।हालांकि अवाक ह्यअनारकलीह्न खूब चली थी। ऐतिहासिक फिल्मों को नयी जान दी सोहराब मोदी

की फिल्म ह्यपुकारह्न (1939)ने । यह फिल्म बेहद कामयाब रही। और इसने ऐतिहासिक फिल्मों के लिए नयी राह खोल दी। मिनर्वा मूवीटोन की इस फिल्म में चंद्रशेखर, नसीम बानो, सोहराब मोदी और सरदार अख्तर ने प्रमुख भूमिकाएं निभायी थीं। यह फिल्म जहांगीर की इंसाफपरस्ती को दरसाती थी। सोहराब मोदी ने सर्वाधिक ऐतिहासिक फिल्में बनायीं। इनमें झसिकंदर, पृथ्वीवल्लभ, झांसी की रानी, मिर्जा गालिब, एक दिन का सुलतान, शीशमहल तथा राजहठ शामिल हैं।अन्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक फिल्में हैं-के आसिफ कृत स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की अविस्मरणीय फिल्म ह्यमुगले आजमह्न। इसमें दिलीप कुमार , मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे की प्रमुख भूमिकाएं थीं। संगीतकार नौशाद ने इसका बड़ा ही पुरअसर और कर्णप्रिय संगीत दिया था। सलीम और अनारकली की प्रेमकथा पर आधारित कई फिल्में बनीं, जिनमें एक फिल्मिस्तान की ह्यअनारकलीह्न भी थी। इसमें प्रदीप कुमार और वीणा राय की प्रमुख भूमिकाएं थीं।

संगीतकार सी. रामचंद्र ने इसका बड़ा सुरीला संगीत दिया था। इसके गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे। यह फिल्म भी बहुत सफल हुई थी। इस जोड़ी की एक और सफल फिल्म थी ताजमहल। इसके अलावा ऐतिहासिक कथानक पर कई फिल्में बनती रहीं। यहां तक कि सत्यजित राय की ह्यशतरंज का खिलाड़ीह्न तक यह सिलसिला चलता रहा। कमाल अमरोही ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ह्य रजिया सुलतानह्न बनायी जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रमुख भूमिकाएं थीं। संवादों के कठिन होने के चलते यह फिल्म दर्शकों के सिर के ऊपर से गुजर गयी। किसी को समझ न आने के कारण यह बाक्स आफिस पर पिट गयी हालांकि इसके भव्य सेटों की काफी प्रशंसा हुई। नायकों में प्रदीप कुमार ऐतिहासिक फिल्मों के काफी लोकप्रिय नायक थे। धीरे-धीरे फामूर्ला फिल्मों की भीड़ में ऐतिहासिक फिल्में कहीं दब गयीं।अवाक फिल्मों के जमाने में लोग चलती-फिरती तस्वीरों का आनंद लेते थे। फिल्म में कौन-कौन काम रहा है, इसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। कलाकारों की लोकप्रियता तब बढ़ी , जब फिल्में बोलने लगीं। आरंभ से ही दो तरह की फिल्में ज्यादा बनती थीं। धार्मिक-ऐतिहासिक या मारधाड़वाली स्टंट फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में। ऐतिहासिक फिल्मों के लोकप्रिय होने का कारण यह था कि एक तो इनके सेट भव्य होते थे और युद्ध के दृश्य होते थे। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि दर्शक को यह पता होता था कि वह सच्ची कहानी देख रहा है। मारधाड़वाली फिल्मों की सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी-नाडिया-जानकावस की। ये तो उन दिनों स्टंट फिल्मों के सुपर स्टार माने ही जाने जाते थे, इनके साथ काम करने वाला घोड़ा पंजाब का बेटा भी किसी सुपर स्टार से कम नहीं था। जिस फिल्म में ये तीनों होते थे वह फिल्म सुपर हिट होती थी। नाडिया वह नायिका थी जिसके हाव-भाव, अभिनय और आचरण पुरुषों जैसे थे। काले रंग का जैकेट और नकाब , हाथ में लपलपाता हंटर या चमचमाती तलवार, यही पोशाक थी उसकी। वह ऊंची जगह पर खड़ी होकर मुंह में दो उंगलियां डाल कर सीटी बजाती , तो घोड़ा पंजाब का बेटा भागता हुआ वहां आ खड़ा होता, जहां से कूद कर नाडिया को उसकी पीठ पर बैठना था, दूसरी सीटी बजते ही घोड़ा सतर्क हो जाता और नाडिया के कूद कर बैठते ही भाग खड़ा होता। ये तीनों उस जमाने में उतने लोकप्रिय थे , जितने आज के नामी कलाकार । वाडिया ब्रदर्स की फिल्मों में यह जोड़ी पेश की गयी। इस जोड़ी की सर्वाधिक हिट फिल्म थी ह्यहंटरवालीह्न।

(लेखक फिल्म सेंसर बोर्ड कोलकाता रीजन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं)

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आरएसएस ने मनाया हिन्दू नववर्ष

भारतीय संस्कृति के बारे में दी जानकारी

सुशान्त साईं सुन्दरम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मंगलवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिन्दू नववर्ष के रूप में मनाया गया. इस आयोजन में शाखा परिवार के लोगों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया. बच्चों और युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में आरएसएस के कार्यकताओं ने अहम बातें बताई. गिद्धौर अवस्थित अतिप्राचीन पंचमन्दिर परिसर में मंगलवार की सुबह भगवा ध्वज फहराकर आरएसएस ने हिन्दू नव वर्ष मनाया.

कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित आरएसएस के जिला संघ संचालक अधिवक्ता प्रकाश भगत ने कहा कि मन, वचन, कर्म से हम सभी को एक जैसा होना होगा. सभी के लिए अनुशासन आवश्यक है. शाखा में राजनीतिक बातों पर नहीं बल्कि संघ और सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा आवश्यक है. शनिवार को सफाई दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना है कि समाज के लिए काम करने में सक्षम हैं या नहीं. वर्तमान परिस्थिति में कई कुरीतियां हैं. हिंसा का दौर चल रहा है. यह नियंत्रित तब होगा जब एक विचार के तरफ चलेंगे और संगठित होकर काम करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओ को भाषा, प्रान्त, जाति के नाम पर तोड़ा जाता है. माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने संघ को आगे बढ़ाया. उन्होंने चारों धाम के शंकराचार्य को एकजुट कर एक मंच पर लाया. उन्होंने तभी घोषणा की की कोई हिन्दू पतित नहीं है. हिन्दू समाज मे सभी हमारा अंग है, सब एक हैं. हमें जाती-बिरादरी के अंदर जो कुरीतियां हैं उन्हें हटाना है. महाराणा प्रताप ने सभी को संगठित किया. उन्होंने प्रारंभ किया कि सभी जातियों को एकजुट कर अपनी सेना तैयार की. अगर हम सब भी एक साथ होंगे तभी हिन्दू समाज संगठित होगा. हमें हिन्दू समाज की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करना है. आज नववर्ष पर हमें अपने मित्रमंडली में सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए. सबको बताना जरूरी है कि हिंदुओ का नववर्ष है.

श्री भगत ने कहा कि संघ राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक संगठन है. हमें नववर्ष पर यह संकल्प लेना है कि हिन्दू समाज एकदूसरे के भाई हैं, सब एक हैं. इसका संकल्प लेंगे तभी आज का दिन मनाना सफल होगा. आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिवर्ष नववर्ष मनाना है. आरएसएस के गिद्धौर खंडकार्यवाह डॉ. संजय मंडल ने कहा कि राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन की गई थी. यह बहुत शुभ दिन माना जाता है. हिन्दू व्रत-त्योहार हिंदी तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है. हिंदी पंचांग की शुरूआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है. इसलिए हिन्दुओं को प्रतिवर्ष इस दिन नववर्ष मनाना चाहिए. इस अवसर पर भाजपा बिहार प्रेस पैनल सदस्य मनीष पाण्डेय, गिद्धौर प्रखंड प्रमुख व भाजपा नेता शम्भू कुमार केशरी, आरएसएस के सौरभ कुमार, नितीश कुमार, रजनीश कुमार, राकेश कुमार रावत, राहुल कुमार, शिवम कुमार, पप्पू यादव, शंकर यादव सहित कई अन्य कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे.

दिल्ली में रामराज्य की परिकल्पना साकार करने पर उतारू हो आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में रामराज्य की परिकल्पना साकार करने पर उतारू हो आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगता है रामायण सलीके से पढ़ी ही नहीं है। मुमकिन है कल को वे इस बात की हिमायत करने लगें कि धर्मकर्म करने वाले शंबूक की तरह दलितवध पाप नहीं है, बाली जैसे निर्दोष बंदर को धोखे से मारना क्षत्रिय धर्म है और चरित्र पर शंका होने पर जनता की मांग पर गर्भवती पत्नी का त्याग भी रामराज्य की परिकल्पना का ही बिंदु है।

अकसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर शक जताने वाले अरविंद की डिग्रियों के औचित्य पर शक हो आना कुदरती बात है कि दोनों में फर्क क्या। बूढ़ों को जनता के पैसे से अयोध्या का तीर्थ करवाने वाले अरविंद खुद अपनी लोकप्रियता को मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो आए हैं। बेहतर यह होगा कि वे इस धार्मिक अभियान में अपने भूतपूर्व कवि दोस्त कुमार विश्वास को साथ ले लें जो इन दिनों रामकथा बांचते लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं।

कसकता दोस्ताना

पिछले साल तक भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन के खानदान को गद्दार कहते रहते थे, अब उन के भाजपा में जाने के बाद यही बात राहुल गांधी इशारों में कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें वफादारी का इनाम देते मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कभी ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता सिंधिया ने भी राहुल की दादी इंदिरा गांधी के साथ ऐसी ही गद्दारी की थी, तब भी कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। यानी कलंक का टीका स्थायी रूप से सिंधियाओं के माथे पर चिपका रहा है। लेकिन यहां बात टीन एज की दोस्ती की है जो राहुल को ज्यादा साल रही है। इसे गिल्ट भी कहा जा सकता है और खीझ भी। रही बात सिंधिया की, तो वे, दरअसल, दिलोदिमाग से सनातनी हैं जो मजबूरी में कांग्रेस व राहुल से चिपके थे। राजघरानों के सपूतों को दोस्ती जैसे पाक जज्बे से ज्यादा सत्ता प्यारी होती है, यह उन्होंने साबित भी कर दिया।

बेशक मंदिर-मसजिद तोड़ी

आम भारतीय टोल नाके पर तो पैसा देने में कलपता है लेकिन सड़क किनारे अतिक्रमण की जमीन पर बने धर्मस्थल देखते ही जेब ढीली कर देता है। ऊपर वाले का न लिया कर्ज वह जिंदगीभर किस्तों में चुकातेचुकाते एक दिन खुद ऊपर चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है तो एक निरा अंधविश्वास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश पर फरमान जारी करते तुक की बात यह कही है कि ऐसे अवैध मंदिरमसजिद तुरंत हटाए जाएं।

यह बात योगीजी के संस्कारों से मेल खाती नहीं है।

शायद उन का सोचना यह रहा होगा कि जब अयोध्या में सब से बड़ा मौल बन गया है तो दरिद्रता फैलाती इन छोटीमोटी गुमटियों की जरूरत क्या। इस से कई पंडेपुजारियों का रोजगार छिन जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैसे ही ब्राह्मण उन से नाराज हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नया हुक्म क्या गुल खिलाएगा।

गडकरी की घूसखोरी

आंखों और मूंछों से मुसकराते रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की होली बदरंग भी हो सकती है बशर्ते उन पर लग रहा घूसखोरी का इलजाम परवान चढ़ पाए। किस्सा कुछकुछ चंद्रकांता संतति जैसा है। स्केनिया स्वीडन की कार कंपनी वौक्स्वैगन की ब्रांच है जो हैवी व्हीकल बनाती है। स्वीडन के मीडिया स्वेरगेस, जिस का प्रचलित नाम एसवीटी है, ने बीती 10 मार्च को एक रिपोर्ट में कहा है कि स्केनिया भारत में अपना कारोबार बिना किसी अड़ंगे के कर सके, इस बाबत नितिन गडकरी को एक लग्जरी बस तोहफे में दी गई जो 4 दिसंबर, 2016 को उन की बेटी केतकी की शादी में इस्तेमाल भी की गई थी। यह बात आम जनता में नहीं आई। लेकिन अंदरूनी बवंडर मचा तो स्केनिया की तरफ से सफाई आई कि यह बस एक प्राइवेट डीलर ने खरीदी थी, फिर इस का क्या हुआ, उसे पता नहीं। अब सच जो भी हो, कभी सामने आ पाएगा, इस में शक है लेकिन गडकरी की चुनरी में दाग तो लग ही गया है।

छेड़खानी की बीमारी कैसे मुकाबला करे नारी

छात्र हो या गृहिणी या कामकाजी महिला, घर से बाहर निकलते ही तरह-तरह की छेडखानियों का सामना करना उनकी नियति बन गयी है। सार्वजनिक स्थलों, मार्केट, पार्क या मुहल्ले में अक्सर तमाम सड़क छाप रोमियो से पाला पड़ता है। यहां तक कि अपने घरों में भी आज की नारी छेडखानी की महामारी से नहीं बच पाती। लड़कियां जब बचपन की दहलीज पार करती हैं, तभी से उनको छेड़छाड़ की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है।

छेडखानी का सामना लड़कियों को अपने घर में भी करना पड़ता है। रिश्तेदारों में ही कुछ ऐसे अभद्र पुरूष होते हैं जो घर आने पर बच्चियों को उठाकर गोद में बिठा लेते हैं और उनके यौवनांगों को सहलाते रहते हैं। भींच कर सीने से चिपका लेना आदि कई क्रियाओं द्वारा नाबालिग बच्चियों से छेडखानी चलती रहती है।

छेडखानी करने वालों की भी कई किस्में होती हैं। कुछ शेरो-शायरी की कलात्मक, शालीन भाषा में खूबसूरती के कसीदे पढ़ने वाले होते हैं। इनको चुपचाप अनदेखा करने से ही मुश्किल हल हो जाती है। इसके बाद नंबर उनका आता है जो छेड़छाड़ के नाम पर महज पीछा करते हैं। ऐसे लोग कायर, मूर्ख और भावुक होते हैं। इन्हें एक बार जोरदार डांट मिल जाये तो फिर दुबारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करते।

सबसे अधिक निकृष्ट वे होते हैं जो सार्वजनिक स्थलों, स्कूल-कॉलेज के सामने, मार्केट में, किसी पान की दुकान पर खड़े होकर आती-जाती लड़कियों पर फिकरे कसते हैं और उनके स्तनों की तरफ कामुक नजरों से देखते हैं।

यूं तो छेड़छाड़ के नित नये तरीके बराबर निकलते रहते हैं पर छेड़छाड़ के पुरातन तरीके भी ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। रास्ते चलते लड़कियों पर फिकरा कसना, रिक्शे या स्कूटी से आती-जाती लड़कियों का दूर-दूर तक पीछा करना, गांवों, छोटे शहरों में एकान्त पाकर दुपट्टा या साड़ी का पल्लू खींच लेना, चॉक के टुकड़े, खाये हुए फल के बीज या छिलके, यहां तक कि सिगरेट के टुकड़े लड़कियों पर फेंक देना आम बात होती है।

किसी मेले, दुर्गा पूजा, दशहरा आदि के अवसर पर तो छेडखानी उद्दंडता की सीमा को पार कर जाती है। आगे-पीछे चलना, धक्का मार देना, चाट-पकौड़ियों की दुकान पर साथ-साथ पहुंचकर खाना और फिकरे कसना खुशनुमा वातावरण को भी दूभर बना डालता है।

पता नहीं छेडखानी की प्रथा का चलन कब से प्रारंभ हुआ परन्तु इसकी महामारी संक्रामक बीमारी की तरह दिन-प्रतिदिन फैलती ही जा रही है और लड़कियों, महिलाओं का घर से निकलना तक दूभर करती जा रही है। प्रगति की दुनियां में इससे डरकर घर में बैठे रहना भी संभव नहीं है अतः इस परिस्थिति से जूझने के काबिल स्वयं को बनाना होगा। थोड़ी-सी समझदारी और कॉमनसेंस से छेडखानी की महामारी पर काबू पाया जा सकता है।

आपकी शारीरिक भाषा उस गुप्त हमलावर को यह बताती है कि वह आपसे नाजायज फायदा उठा सकता है या नहीं या आपके शरीर से कुछ छीन सकता है या

नहीं। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, ज्यादातर नारियों को छेडखानी की परेशानी में फंसा देती है। छेडखानी की महामारी से प्रतिकार करने के लिए इन उपायों को अपनाइए। घर से बाहर निकलते समय सलीकेदार वस्त्रों को पहनिए। अर्द्धनग्न वस्त्रों को पहनना छेडखानी को आमंत्रण देना होगा।

ध्यानाकर्षण करने वाले भड़कीले कपड़े, कीमती गहने आदि पहन कर मत निकलिए। स्तनों के उभार को छिपाए रखने के लिए दुपट्टा या साड़ी का पल्ला ठीक से रखिए।

ह्र रास्ते में चलते समय सिर झुका कर सिर्फ नीचे देखते हुए चलें। अपनी आंखें व कानों को खुला रखें तथा आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहें।

उन रास्तों से आना-जाना न करें या कम कर दें जहां का रास्ता सुनसाने हो। अंधेरे में तो ऐसे रास्तों से बिलकुल न जायें भले ही वह रास्ता शार्टकट या छोटा ही क्यों न हो।

दुर्भाग्यवश कोई विपरीत परिस्थितियां आ ही जाती हैं तो बजाय 'बचाओ बचाओइ चिल्लाने के खूब जोरों से चीखें या चिल्लायें। इससे लोगों का ध्यान तुरंत आकृष्ट होता है। बचाओ-बचाओ की आवाज सुनकर भी कोई मदद करने इस लिए नहीं आता है कि कौन मुसीबत में पड़े।

अधिकतर वैसी ही महिलाओं को हमलावर तंग करते हैं जो शारीरिक भाषा से स्वयं को कमजोर दिखाती हैं। उत्तेजक परिधान आपके आत्मविश्वास को कम करने वाले होते हैं। सहपाठियों या सहकर्मियों या बॉस की मानसिकता को अच्छी तरह समझ लीजिए और बेवजह ज्यादा घुलें-मिलें नहीं। ऐसी इमेज न बनायें जिससे वे आपको स्वतंत्र और उन्मुक्त विचारों वाली समझें।

छेडखानी का सामना लड़कियों को अपने घर में भी करना पड़ता है। रिश्तेदारों में ही कुछ ऐसे अभद्र पुरूष होते हैं जो घर आने पर बच्चियों को उठाकर गोद में बिठा लेते हैं और उनके यौवनांगों को सहलाते रहते हैं। भींच कर सीने से चिपका लेना आदि कई क्रियाओं द्वारा नाबालिग बच्चियों से छेडखानी चलती रहती है। छेडखानी करने वालों की भी कई किस्में होती हैं। कुछ शेरो-शायरी की कलात्मक, शालीन भाषा में खूबसूरती के कसीदे पढ़ने वाले होते हैं। इनको चुपचाप अनदेखा करने से ही मुश्किल हल हो जाती है। इसके बाद नंबर उनका आता है जो छेड़छाड़ के नाम पर महज पीछा करते हैं।

ह्र भविष्य में अन्य लाभ या प्रोन्नति पाने के लिए सस्ता रास्ता न अपनायें व इन कुटिल षडयंत्रकारियों से एकदम अलग रहें।

पति के मित्र या संबंधी के आने पर उसके समक्ष अनावश्यक मत रहिए। घर पर अकेली रहने पर बरामदे में बैठकर ही बातें करिए एवं अपने परिधान पर ध्यान अवश्य रखिए। किसी के द्वारा दी गई खाद्य सामग्री या प्रसाद को तुरंते मत खाइए। वह नशीला-मादक पदार्थ भी हो सकता है।

अत्यंत आवश्यकता न हो तो किसी किस्म की लिफ्ट या किसी की सहायता ग्रहण मत करिए। ऐसे में लोग अनुचित फायदा उठाने से नहीं चूकते। शालीनता की परिधि में रहकर छेडखानी की महामारी से स्वयं को बचाया जा सकता है।

स्वतंत्र व उन्मुक्त विचारों को अपनाकर, भड़कीली पोशाकों को पहनकर, अर्द्धनग्न शरीर का प्रदर्शन करके न सिर्फ परेशानियों में ही फंसेंगी बल्कि अपनी अस्मत को भी दांव पर लगा बैठेंगी। मनोबल, साहस व आत्मविश्वास से छेडखानी की महामारी को आप नियंत्रण में रख सकती हैं।

2021-22 के झारखंड राज्य के बजट में कमजोर व असुरक्षित किशोरियों के लिए लाभ

झारखंड में लक्ष्यपूर्ति (आउटकम) पर आधारित पहले बजट की घोषणा; विभिन्न विभागों के लिए तय किए गए लक्ष्य

साल 2021-22में झारखंड राज्य का बजट झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव द्वारा 3 मार्च 2021 को सदन में पेश किया गया था. बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गयाऔर कोविड-19 कीमहामारी के प्रकाश में, विशेष रूप से हाशिए पर रह रहे लोगों और कमजोर समुदायों के लिए, कल्याण और विकास को मजबूत करने की दिशा में राज्य ने प्रतिबद्धता दिखाई.

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के वार्षिक बजट का मुख्य फोकस जीवन और आजीविका को मजबूत करना है, और यह विभिन्न कार्यक्रमों में परिलक्षित हुआ, जो बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और खेल योजनाओं के माध्यम से कमजोर समूहों के लिए प्रावधानों को मजबूत करने की घोषणा की गई.झारखंड एक नया राज्य है औरइस की 50 फीसदीसे अधिक आबादी 24 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है. इस आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की महत्वपूर्ण जरूरतों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य कोविड-19 के संकट के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से काम कर रहा है. बजट में की गई कुछ प्रमुख घोषणाओं में इस आबादी की मुख्य जरूरतों को संबोधित करने के संकेत मिलते हैं. दिसंबर 2020 में जारी किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड-5 (एनएफएचएस-5) के आंशिक परिणामों ने कुपोषण के संकट पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.इस मायने में अखिल भारतीय आंकड़े भले ही प्रतीक्षित हैं, पहले चरण के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का डेटा इस क्षेत्र में ठहराव दिखाता है और कुछ राज्यों में पिछले पांचवर्षों में महिलाओं व बच्चों के पोषण की स्थिति से संबंधित कई संकेतकों में गिरावट दर्ज हुई है. झारखंड राज्य के बजट के हिस्से के रूप में की गई घोषणाओं में किशोरियों और युवा महिलाओं की पोषण और आहार संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने और केंद्रित करने की आवश्यकता को संबोधित किया गया है. विभिन्न योजनाएं और अभियान जैसे कि रअअटअफ (स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलेविएशन ऑफ मैलन्यूट्रीशन एंड एनीमिया रिडक्शन) जो बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण और खून की कमी पर केंद्रित, "साझा पोषण कार्याक्रम", जो किशोरियोंऔर युवा महिलाओं को सहायक भत्ते प्रदान करने के लिए प्रावधान तय करेगा और तीन वर्षसे छहवर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए हर सप्ताह तीनअंडे के रूप में "दोपहर का भोजन" उपलब्ध कराएगा, कुपोषण को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पोषण के साथ, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से

शिक्षा, आजीविका और खेल पर भी जोर दिया गया है. सरकार ने घोषणा की है कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले वित्तीय वर्ष के भीतर लक्ष्य के तौर पर 1000 पंचायतों को शून्य ड्रॉपआउट पंचायतें घोषित किया जाए. शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण प्रगति राज्य के 4639 स्कूलों में डिजिटल मोड और स्मार्ट कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता है.रअठडअछढ (कौशल संवर्धन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान और जागरूकता) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को आत्म निर्भर बनाना और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. प्रत्येक गांव में सिद्धो कान्हू खेल क्लबों की स्थापना भी युवाओं और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी. इसके अलावासरकार राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और महिलाओं के बीच फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहती है।.

इन घोषणाओं से किशोरियों और युवाओं के कल्याण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है. फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा प्रतिबद्धता और प्राथमिक रूप से काम करने की आवश्यकता है. साल2020-21 से 2021-22 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए बजटीय आवंटन में हुई महत्वपूर्ण कटौती से ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवा वितरण को मजबूत बनाने की आवश्यकता का संकेत मिलता है, जिनमें गर्भनिरोधक, मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और अन्य स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं तक पहुंच सहित प्रमुख किशोर-किशोरियांआवश्यकताओं को संबोधित करना शामिल है.किशोरी गर्भधारण, बाल विवाह और जल्दी शादी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कोशिश है.एनएफएचएस-4 के आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में 15 से 19 की उम्र के बीच की हर 8वींकिशोरीलड़की या तो गर्भवती है याकिशोरीमाँ है.साथ ही 20से 24 साल की उम्र की 38 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहलेहो जाती है.

किशोरियों और युवाओं की जरूरतों के लिए

मुख्य बिंदु

- किशोरियोंके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान:
- झारखंड राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य विकास की दिशा में कोशिशें
- किशोरियोंव महिलाओं में एनीमिया को दूर करने की कोशिश
- विशेष तौर पर किशोरियोंव महिलाओं में समग्र पोषण में सुधार की कोशिशें
- शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाना:
- डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना
- स्कूल ड्रॉप-आउट-रेट को कम करना
- झारखंड में उपेक्षित वर्गों के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की कोशिशें
- आजीविका और रोजगार को बढ़ाना:
- झारखंड में 5000 से ज्यादा युवकों के बीच कौशल निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम
- किशोरियोमें स्वाधिकार की भावना विकसित करना
- किशोरियोंकेखेलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी कोशिशों

जनसांख्यिकीयरूप से केंद्रित दृष्टिकोण लागू करना, जैसा कि बजटीय आवंटन और निर्णयों में परिलक्षित हो रहा है, झारखंड की प्रगति और बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है. हाल की घोषणाएं इस दिशा में किए गए वादों का संकेत देती हैं,और यह इंगित करती हैं कि राज्य इस पर त्वरित रूप से काम करें और राज्य की सामाजिक-आर्थिक संभावनाओं को साकार करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाए रखें.

अब-मेरी-बारी (अुटी१इं१) अभियान के माध्यम से 10३ङ्क19 दसरा एडॉलसेंट कोलैबोरेटिव,किशोर-किशोरियोंको उन उपकरणों और माध्यमों के जरिए मदद उपलब्ध कराता है, जो निर्णयकताओं के बीच उनकी आवाज को बेहतर ढंग से पहुंचा सकते हैं.अब जब हम इस अभियान के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तोहमारा ध्यान किशोरीगर्भावस्था को समाप्त करने और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों (रफ्ल्फ) के बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है. इस वर्ष का अभियान इस दिशा में समाधान-उन्मुख और समग्र प्रयास करने पर केंद्रित है. इस तरह के प्रयास युवाओं को अपनी शर्तों पर भौतिक और मनोसामाजिक समर्थन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ने और बेहतर ढंग से अपने लिए जगह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं.

महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी की क्यों आई नौबत, अन्य राज्यों में पांव पसार रहा कोरोना

सभी वायरस प्राकृतिक तौर पर म्यूटेट करते हैं यानी अपनी संरचना में बदलाव करते हैं ताकि उसके जीवित रहने की और प्रजनन की क्षमता बढ़ सके। कोरोना वायरस की जीने की यही इच्छा उसे खुद को बदलने पर मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी बदलने की इच्छी भारत में ना तो सरकारों में देखने को मिल रही है और ना ही जनता में। वरना एक साल बाद महाराष्ट्र में भला दोबारा से लॉकडाउन जैसी पाबंदी देखने को क्यों मिलती?

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात आठ बजे से राज्य में कड़ी पाबंदियाँ लागू करने की बात कही है।

भले ही उन्होंने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया, लेकिन कर्फ्यू से थोड़ा ज्यादा और लॉकडाउन से थोड़ा कम ही माना जा रहा है।

पिछले साल मार्च में जब कुछ घंटों की नोटिस पर देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया था।

महाराष्ट्र सरकार भी उनमें शामिल थी। केंद्र सरकार ने और देश के कई डॉक्टरों ने उस लॉकडाउन को ये कहते हुए जायज ठहराया कि इससे संक्रमण का चेन टूटेगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का वक़्त मिल जाएगा।

लेकिन एक साल बाद, जब मुख्यमंत्री दोबारा से 'ब्रेक द चेन' के लिए घोषणाएँ कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एक साल में हमने कोई सबक नहीं सीखा? और अगर लिया तो क्या इतनी जल्दी भुला दिया?

क्या पिछले लॉकडाउन के बाद दवाओं की कि ल्लत दूर करने की तैयारी नहीं हुई थी? जो अस्पताल बने, वेंटिलेटर खरीदे गए, आईसीयू बेड जोड़े गए - उनका एक साल में क्या हुआ?

महाराष्ट्र में वहाँ पिछले एक साल में स्थिति कितनी बदली है इसी का जायजा लेने के लिए हमने बात की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैप्टर के साल 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे से।

डॉक्टर अविनाश कहते हैं, लोगों ने मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिग से नाता तो तोड़ ही लिया। बुखार को भी हल्के में लेना शुरू कर दिया। नतीजा लोग अस्पताल देर से पहुँचने लगे। वो भी तब जब स्थिति हाथ से निकल गई। नतीजा रोज आ रहे नए आँकड़ो में देखा जा सकता है।

लेकिन डॉक्टर अविनाश के मुताबिक ऐसे सबक कई हैं जो राज्य सरकार सीख कर भूल गई। वो एक एक कर उन्हें गिनाते हैं।

"महाराष्ट्र में साल दर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च 0।5 फीसद तक रहा है। कोविड19 महामारी के बाद भी ये बढ़ा तो राज्य सरकार के बजट का 1 फीसद नहीं हो पाया है। 500 करोड़ रुपये के इजाफे की बात इस बार के बजट में किया गया है। महामारी के अनुपात में ये कुछ नहीं है। आईएमए के अनुमान के मुताबिक कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा कम से कम 5 फीसद होना चाहिए। महामारी के एक साल में कोई नया सरकारी अस्पताल राज्य में नहीं खुला है।"

डॉक्टर भोंडवे का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में केवल 10000 बेड्स हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। कोविड19 महामारी के दौरान 80 फीसद काम का बोझ प्राइवेट अस्पताल वाले उठा रहे हैं और 20 फीसदी ही सरकारी अस्पतालों के पास है। सारी सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल जिनमें बाईपास

सर्जरी की सुविधा हो, कार्डियोलॉजी सुविधा से लेकर अच्छे ऑपरेशन रूम हों और आईसीयू की सुविधा हो, वो तो ना के बराबर हैं। लेकिन इसके लिए वो केवल वर्तमान सरकार को ज़िम्मेदार नहीं मानते। उनके मुताबिक राज्य में सालों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ना तो अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और ना ही नर्सिंग कॉलेज। यही हाल लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन का है।

नतीजा महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड 1 लाख 25 हजार डॉक्टर हैं जबकि जरूरत दोगुने की है। उसी तरह से महाराष्ट्र में नर्स की कमी की खबरें पिछले साल भी आई थी। आज भी कमोबेश यही स्थिति है। जरूरत से लगभग 40 फीसद उनकी संख्या कम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में हर शिफ्ट के लिए दिन में तीन रजिस्टर्ड नर्स भी नहीं मिलती हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के नए कानून के मुताबिक जरूरी है।

लैब टेक्नीशियन जो डायलिसिस सेंटर में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर काम करते हैं उनकी कमी की वजह से स्थिति और खराब हो गई। जाहिर है ये सभी कमियाँ एक साल में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उस ओर एक कदम भी सरकार नहीं उठा पाई। ट्विटर पर इस तरह के कई शिकायतें आपको मिल जाएगी, जहाँ महामारी के एक साल बाद भी कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। टेस्ट हो जाने पर रिपोर्ट के आने में भी 2-3 दिन का इंतजार आम बात है।

पिछले साल मई में जहाँ महाराष्ट्र में केवल 60 सरकारी और प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर थे, वहीं लैब्स की संख्या बहुत कम थी। एक साल बाद टेस्टिंग की संख्या बढ़ कर 523 हो गई है पर लैब्स की संख्या अब भी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है।राज्य में हफ़्ते में अब 57 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। टेस्ट प्रति

नतीजा महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड 1 लाख 25 हजार डॉक्टर हैं जबकि जरूरत दोगुने की है। उसी तरह से महाराष्ट्र में नर्स की कमी की खबरें पिछले साल भी आई थी। आज भी कमोबेश यही स्थिति है। जरूरत से लगभग 40 फीसद उनकी संख्या कम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में हर शिफ्ट के लिए दिन में तीन रजिस्टर्ड नर्स भी नहीं मिलती हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के नए कानून के मुताबिक जरूरी है। लैब टेक्नीशियन जो डायलिसिस सेंटर में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर काम करते हैं उनकी कमी की वजह से स्थिति और खराब हो गई। जाहिर है ये सभी कमियाँ एक साल में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उस ओर एक कदम भी सरकार नहीं उठा पाई। ट्विटर पर इस तरह के कई शिकायतें आपको मिल जाएगी।

मिलियन की बात करें तो उसकी संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन रोज आ रहे मामलों को देखते हुए वो अब भी नाकाफी है। ये बात खुद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने स्वीकार की है। कुल टेस्ट में फ्ळ्ढउफ टेस्ट की संख्या भी काफी कम है, जो कोरोना के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है।

यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इस बार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई जगहों पर पूरा का पूरा परिवार पॉज़िटिव हो रहा है। ऐसे में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी ज्यादा करनी पड़ रही है और टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से टेस्टिंग फैसिलिटी पर बोझ भी बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, "आने वाले दिनों में राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाने में देरी होगी। 1000 किलोमीटर दूर के राज्यों से ऑक्सीजन लाने में होने वाली देरी घातक हो सकती है। मैंने प्रधानमंत्री से बात की है ताकि एयरफोर्स इसमें हमारी मदद करें।"

जानकारों की मानें तो ये हमेशा से सबको पता था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आएगी ही। मुंबई के जसलोक अस्पताल के मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारेख ने महामारी पर 'दि कोरोनावायरस बुक' और 'दि वैक्सीन बुक' नाम से दो किताबें लिखी है। वो कहते हैं, "मैंने अपनी पहली किताब में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बारे में लिखा था और बताया था कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर पहले पीक में राज्य में 30 हजार रोज नए मामले आ रहे थे, उसमें से 10 फीसद को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ रही थी, कितने लोगों को आईसीयू की, कितने को ऑक्सीजन और कितने को वेंटिलेटर की ये आँकड़े सरकार के पास होने चाहिए थे। रेमडेसिविर दवा के बारे में यही बात लागू होती है। आने वाले पीक के हिसाब से राज्य सरकार को अगले पीक में 60 हजार रोज के मरीजों की संख्या को सोच कर तैयारी करनी थी। हमारे पास ना तो कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर है और ना ही कोविड एप्रोप्रिएट एटिट्यूड" यानी जो बात मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को कह रहे हैं, ऐसी नौबत आती ही नहीं अगर कोरोना की पहली लहर के बाद महीने में दो बार इस बार समीक्षा बैठक करते और फॉरवर्ड प्लानिंग करते।

कोरोना: श्मशान कर्मचारियों का बुरा हाल

भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर साल 1918 में आए स्पैनिश फ़्लू की कहानी दोहराती हुई दिख रही है। साल 1918 के अप्रैल-मई महीने में स्पैनिश फ़्लू की पहली लहर आई, जो यूरोप के कई देशों में फैली। लेकिन धीरे-धीरे से फ़्लू कम होता गया, लगा मामला खत्म होने वाला है, लेकिन ये 'तूफान आने से पहले की खामोशी' जैसी थी। अगस्त, 1918 में स्पैनिश फ़्लू का एक नया म्यूटेंट आया और ये इतना खतरनाक साबित हुआ कि किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। यूरोप में ये ऐसे फैला, जैसे जंगल में आग फैल रही हो। ये तो बात थी साल 1918 की। अब जरा वर्तमान में आते है और बात भारत की करते हैं।

भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन डेढ़ लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों का आँकड़ा प्रतिदिन 1000 से ज्यादा हो चुका है। मरीज अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं और तो और दाह संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बीबीसी ने देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले राज्य के शवगृहों में काम करने वाले कर्मचारियों और दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करने वाले परिजनों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि हालात कैसे हैं। पुणे के एक सरकारी शवगृह में काम करने वाले वरुण जनगम फोन पर अपनी बात जल्दी-जल्दी बोलते हैं, जैसे कम वक़्त में कितना कुछ बता देना चाहते हों। फिर कहते हैं- मैडम थोड़ा काम है, हम आपको फ़्री होकर कॉल करते हैं। वरुण देश के उन तमाम शवगृह कर्मियों की झलक अपनी बातों से पेश कर जाते हैं, जो हर दिन, हर मिनट कोरोना से मारे गए लोगों के शव जला रहे हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों की मौत हुई है।महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और कुल कोरोना केस का 80% मामला इन राज्यों से सामने आ रहा है, इनमें भी महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है, जहाँ अब एक मई तक कई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं।

वरुण बताते हैं कि यूँ तो उनकी शिफ़्ट आठ घंटे रहती है, लेकिन इसके बावजूद काम इतना है कि उन्हें घंटों ओवरटाइम काम करना ही पड़ता है। हालाँकि वह उन कर्मचारियों में से हैं, जिनके पास अपना काम करने के लिए पीपीई किट उपलब्ध है। लेकिन गुजरात के राजकोट में कोविड 19 के शवों के लिए अधिकृत श्मशान पर काम करने वाले दिनेशभाई और धीरुभाई संक्रमण से मरने वाले लोगों को बिना किसी पीपीई किट या दस्तानों के जला रहे हैं। गुजराती के सहयोगी बिपिन

टंकारिया को उन्होंने बताया कि कोविड से पहले यहाँ औसतन एक दिन में 12 शव आया करते थे, लेकिन अब 25 शव आते हैं। दिनेशभाई और धीरुभाई कोरोना से मरने वालों के शव जलाते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की पीपीई किट नहीं दी गई है, कभी कभी एंबुलेंस के साथ आने वाले अस्पताल के लोग उन्हें दस्ताने दे देते हैं, वरना उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है, जो नियमों के तहत संक्रमित शवों को जलाते वक़्त पहनना जरूरी है। श्मशान पर काम करने वाले कर्मचारी ही केवल परेशान और हताश नहीं हैं, बल्कि वो लोग, जिन्होंने महामारी में अपनों को खोया है, उनके इंतजार और दुख भी अंतहीन हैं, ये लोग पहले अपनों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और फिर मौत हो जाने की स्थिति में उन्हें शव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक परिवार से बात की। गुजरात में राजकोट के पास स्थित मोरबी से आए हुए हेमंत जादव ने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनके रिश्तेदार के शव के लिए उन्हें 12 घंटे तक ज्यादा इंतजार करना पड़ा। सुबह पाँच बजे वे राजकोट के सिविल अस्पताल आए और शाम के सात बजे जब वे बीबीसी से बात कर रहे थे, तब तक उन्हें अपने भाई का शव नहीं मिल सका था।

हेमंत के भाई कोरोना वायरस से संक्रमित थे और एक अप्रैल से राजकोट सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे। हेमंत ने बताया, ह्यह्लफोन पर बात हुई थी तब मेरे भाई की तबीयत में सुधार आ रहा है, ऐसा हमें लग रहा था कि वो अब ठीक होकर घर आएँगे, पर उसके बाद हॉस्पिटल से फोन आया कि उनका निधन हो गया है। सरकारी आँकड़ों की मानें, तो बीते 24 घटों में गुजरात में 6690 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल 33,000 सक्रिय मामले हैं। खासकर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर हैं। सूरत के शवगृहों में लंबी कतारों में खड़े लोग अपनों की आखिरी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, लोगों को टोकन दे कर घंटों लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। लखनऊ से जानकारी दी है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का संक्रमण जहाँ लोगों पर कहर बनकर टूटा है, वहीं संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह और सुविधाओं की कमी पड़ गई है। लखनऊ के दो घाटों के अलावा कई अन्य शहरों में भी लोगों को अपने मृत परिजनों के दाह संस्कार के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। लखनऊ के बैकुंठ धाम शवदाहगृह का आलम यह है कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं और घाटों पर शवों को जलाने के लिए भी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। मंगलवार को अपने एक रिश्तेदार का दाह संस्कार करने गए देवेश सिंह ने बताया कि उन लोगों को खुद ही हर चीज की व्यवस्था करते हुए दाह संस्कार करना पड़ा। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किया गया है, लेकिन इन घाटों पर सामान्य मौत वाले शवों का भी अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

रफाल सौदे में भ्रष्टाचार के नए आरोप

लगभग 60,000 करोड़ रुपये वाले रफाल सौदे पर हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है

इसकी खास वजह फ्रांस की एक मीडिया कंपनी मीडियापार्ट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि रफाल की निमार्ता कंपनी डासो ने भारत के एक बिचैलिये को 10 लाख यूरो दिए जो सौदे से अलग दी गई राशि है।

इस बिचैलिये के खिलाफ ऑगस्टा हेलिकॉप्टर डील घोटाले में शामिल होने के इलजाम में जाँच चल रही है। किकबैक और भ्रष्टाचार पर मीडियापार्ट की तीन किस्तों वाली स्टोरी में रफाल स्कैंडल से संबंधित कुछ नए सवाल उठाए हैं, कुछ नई जानकारी सामने आई हैं।

इस फ्रांसीसी वेबसाइट ने रफाल लड़ाकू जेट की भारत में बिक्रीरू एक घोटाले को कैसे दबाया गया था की सुर्खी से चलाई अपनी स्टोरी में दावा किया कि इस विवादास्पद सौदे के साथ, डासो ने उस बिचैलिये को 10 लाख यूरो का भुगतान किया किया जिसकी एक अलग रक्षा सौदे (ऑगस्टा हेलिकॉप्टर डील) के संबंध में भारत में जाँच की जा रही है।इस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी एंटी-करप्शन एजेंसी श्एफएश की डासो के एक नियमित ऑडिट के दौरान इस अलग व्यवस्था की हकीकत सामने आई। रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जताई गई है कि इस जानकारी के बावजूद एफए ने अधिकारियों को सचेत नहीं करने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में इसे दबा दिया गया।रिपोर्ट के अनुसार बिचैलिये को ये पैसे रफाल विमानों का मॉडल सप्लाई करने के लिए दिए गए थे। इन मॉडल्स की संख्या के अनुसार प्रति विमान मॉडल का दाम 20,000 यूरो दिखाया गया था। रिपोर्ट ने सवाल उठाया है कि एक नकली विमान मॉडल की कीमत 20,000 यूरो कैसे हो सकती है।इस खबर पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सोमवार को सामने आई। कांग्रेस ने इस मामले की स्वतंत्र जाँच की माँग की।पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, श्देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमीशनखोरी, बिचैलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन-देन ने एक बार फिर रफाल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राहुल गांधी की बात आखिर सच साबित हुई ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशनखोरी और बिचैलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी, न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशनखोरी और बिचैलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब इस देश के सामने है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई।

उधर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर का खंडन किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट को निराधार करार दिया है।

दो साल पहले रफाल को लेकर भारत में काफी हंगामा खड़ा हो गया था। इसे मोदी सरकार के सबसे बड़े संकट के तौर पर देखा गया था। मामला उस समय जाकर थमा जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सौदे में सरकार को क्लीन चिट दिए जाने वाले अपने फैसले की समीक्षा की माँग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों वाले बेंच में उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ शामिल थे। रंजन गोगोई रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए थे।

साल 2016 में फ्रांस और भारत ने फ्रांसीसी रक्षा समूह डासो के 36 रफाल जेट लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 7।8 अरब यूरो के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे।रफाल दो इंजन वाला मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन ने बनाया है।

विवाद कई मुद्दों पर है।पहला ये कि शुरू में 126 विमान के ऑर्डर को बदल कर 36 विमान क्यों कर

दिया गया।दूसरा, इसके दाम को लेकर है। डासो एविएशन की 2016 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2016 तक 20 करोड़ तीन लाख 23 हजार यूरो के रफाल लड़ाकू विमान के पुराने ऑर्डर थे जबकि 31 दिसंबर, 2015 तक 14 करोड़ एक लाख 75 हजार यूरो के ही ऑर्डर थे। डासो का कहना है कि 2016 में भारत से 36 रफाल डील पक्की होने के बाद यह बढ़ोतरी हुई थी।तीसरा विवाद उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर है। उनकी कंपनी रिलायंस डिफेंस की प्रोफाइल और कंपनी की योग्यता को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कंपनी ने जितने बड़े करार किए हैं, उसके हिसाब से अनिल अंबानी की कंपनी कथित तौर पर अनुभवहीन है। इस विवाद के दौरान फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का चैंकाने वाला बयान आया था कि करोड़ों डॉलर के रफाल सौदे में अनिल अंबानी को भारत सरकार ने ऑफसेट पार्टनर के तौर पर फ्रांस पर थोपा था। 31 जनवरी, 2012 फ्रांस से रफाल को लेकर बातचीत 2012 से ही चल रही थी। डासो को टेंडर मिला जिसने एयरोफाइटर और स्वीडन की साब जैसी कंपनियों को मात दी। लेकिन दो साल तक बातचीत के बाद भी कोई औपचारिक समझौता न हो सका। जुलाई, 2014 मोदी सरकार के सत्ता में आने के दो महीने से भी कम समय में फ्रांस के विदेश मंत्री और अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री लॉरेंट फेबियस ने रफाल सौदे पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दिसंबर, 2014 भारत और फ्रांस ने 126 रफाल फाइटर जेट्स के लिए सौदे को तेजी से ट्रैक करने के लिए मूल्य निर्धारण और डासो के लिए एक गारंटी क्लॉज जैसे मुद्दों पर विचार किया।

10 अप्रैल, 2015 : रक्षा खरीद के मापदंडों को किनारे रखते हुए भारत और फ्रांस ने घोषणा की कि भारतीय वायुसेना 36 रफाल लड़ाकू विमानों को फ्लाई-अवे की स्थिति में खरीदेगी। ये भारतीय वायु सेना के दो स्क्वाड्रंस को 18 विमान से लैस करेंगे।

3 अक्टूबर, 2016 : अनिल अंबानी का नाम आधिकारिक रूप से इस डील में सामने आया। अंबानी की रिलायंस डिफेंस और डासो एविएशन ने संयुक्त उद्यम की घोषणा की। सितंबर, 2018 केंद्र को पहला झटका तब लगा जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने खुलासा किया कि उनके पास भारतीय ऑफसेट साथी (रिलायंस डिफेंस) का चयन करने के लिए कोई विकल्प नहीं था और भारतीय पक्ष द्वारा रिलायंस का नाम फ्रांसीसी प्रकाशन मीडियापार्ट को दिया गया था। इसी महीने सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की जिसमें अंतर-सरकारी समझौते को रद्द करने की माँग की गई थी। 14 दिसंबर, 2018 भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि रफाल सौदे में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है।

मई, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण और अन्य कई लोगों के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

14 नवंबर, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी फर्म डासो एविएशन के साथ रफाल फाइटर जेट सौदे में सरकार को क्लीन चिट देने वाले 2018 में फैसले की समीक्षा की माँग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

रफाल विमान के सौदे में दलाली और संदेह के बादल फिर से लौट आए हैं। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट ने तीन कड़ियों में खोजी रिपोर्ट पेश करने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने दावा किया है विमान बनाने वाली कंपनी दसाल्ट कंपनी ने एक भारतीय बिचैलियों को कथित रूप से करीब आठ करोड़ की रिश्वत दी है। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में रफाल विमान आने वाला था। गोदी मीडिया के चैनलों ने उसके विजुअल से स्क्रीन को भर दिया। रफाल विमान की खूबियां जोर जोर से बताने लगा और उन लोगों को चिढ़ाने लगा जो रफाल के सौदे पर आरोप लगाया करते थे कि इस डील के जरिए अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। चैनलों पर रफाल को लेकर चमकदार हेडिंग लगाई गई, ऐसे जैसे गुलाब जल लेकर बारात के स्वागत में एंकर दरवाजे पर खड़े हों। रफाल विमान के सौदे में दलाली और संदेह के बादल फिर से लौट आए हैं। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट ने तीन कड़ियों में खोजी रिपोर्ट पेश करने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने दावा किया है विमान बनाने वाली कंपनी दसाल्ट कंपनी ने एक भारतीय बिचैलियों को कथित रूप से करीब आठ करोड़ की रिश्वत दी है। मीडिया पार्ट ने अपनी पहली रिपोर्ट में लिखा है कि इस डील में संदिग्ध बिचैलिए थे, दलाली दी गई और डील से उन शर्तों को हटाया गया जिनका पता चलने पर सजा का प्रावधान था। यही नहीं गुप्त माने जाने वाले संवेदनशील दस्तावेज लीक किए गए। किसके फायदे के लिए? मीडिया पार्ट के यान फिलिपिन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांस के एंटी करप्शन अथॉरिटी ने रफाल बनाने वाली कंपनी की ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई है। वेबसाइट इस जांच से संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करने की बात कर रहा है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। फ्रेंच एंटी करप्शन ब्यूरो ने रफाल बनाने वाली कंपनी दसौ की ऑडिट के दौरान पाया है कि इस सौदे के लिए एक मिलियन यूरो की पेमेंट उस व्यक्ति को दी गई जिसकी जांच भारत सरकार किसी दूसरे मामले में कर रही है। इसी बिचैलिए को करीब साढ़े आठ करोड़ से अधिक के पेमेंट होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया पार्ट का दावा है कि भले ही भारत और फ्रांस की सरकारों ने इन मामलों को दबा दिया लेकिन अनगिनत पन्नों की पड़ताल से पता चलता है कि करप्शन हुआ था। 23 सितम्बर 2016 को रफाल डील पूरी हो जाने के बाद दसौ ने ये रकम एक भारतीय सब-कॉंट्रैक्टर डेफसिस`वसनजपवदे को देने का वादा किया था। दसौ ने कहा था कि ये रकम रफाल जेट के 50 बड़े डुप्लिकेट मॉडल बनाने के लिए दिए गए थे। दसौ इस बात का प्रमाण नहीं दे सका कि ये मॉडल बनाए भी गए या नहीं। यानी पैसा दे दिया और जहाज का पता नहीं। हवाई जहाज हवा हो गया। जिस रकम को कर्मोलि `वसनजपवदे को दिया गया उसे दसौ ने ष्हपजि जव बसपमदजेष की हेडिंग में लिखा हुआ है। दसौ ने जवाब में एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक कर्मोलि को 50 डमी मॉडल बनाने के लिए 1 मिलियन यूरो का 50: दिया गया था। हर मॉडल की कीमत 20 हजार युरो से ज्यादा थी। मगर इसे तोहफे के तौर पर एंट्री में क्यों डाला गया इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। भारत के जिस बिचौलियों को पेमेंट देने की बात हो रही है उसका नाम मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन कंपनी का नाम है तो इस सिलसिले में स्क्रोल की रिपोर्ट है कि मालिक सुशेन गुप्ता को मार्च 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें बेल हो गई थी। इसे लेकर कांग्रेस फिर से हमलावकर हो गई है। 2019 के चुनाव में रफाल सौदे में दलाली का मुद्दा खूब उठा था। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि साठ हजार करोड़ के रक्षा घोटाले की कलई फिर से खुल गई है। क्या प्रधानमंत्री अब जवाब देंगे? यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोर्ट अपनी निगरानी में जांच करे। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। यशवंत सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि सच्चाई आखिर बाहर आ ही गई। हमारी जांच एजेंसियों ने पर्दा डालने का काम किया है। फ्रांस में सच्चाई सामने आई है। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमारी जांच एजेंसियों को भी शर्म आनी चाहिए। यशवंत सिन्हा का ये बयान है। सब इस मामले में मीडिया की चुप्पी का भी हवाला दे रहे हैं। भारत का मीडिया रफाल की खूबियां बताने लगता है जब भी दलाली की बात होती है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब रफाल आने वाला था तब किस तरह से हंगामा मचा था कि रफाल आ गया रफाल आया। उनकी हेडलाइन रफाल के गाने गा रही थी लेकिन दलाली के सवालों से बच रही थी। हमने प्राइम टाइम में रफाल आया रफाल आया के जुनून पर तंज किया था। जब भी सवाल उठता है आपको बताया जाता है कि रफाल की खूबी क्या है। जबकि मीडियापार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डील से एंटी करप्शन की शर्तें हटाई गईं और गुप्त जानकारियों को लीक किया गया। अक्तूबर 2018 में कोर्ट ने सरकार से कहा कि 36 रफाल फाइटर विमानों के कीमतों की जानकारी बंद लिफाफे में दे। कोर्ट ने कहा था कि गुप्त संवेदनशील जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। तब के चीफ जस्टिस और आज के राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की बेंच इस मामले को सुन रही थी। सरकार ने पहले कहा था कि वह कीमतों की जानकारी नहीं देगी लेकिन बाद में कोर्ट को बंद लिफाफे में ये जानकारी देने के लिए तैयार हो गई। कोर्ट ने इसके बाद याचिका खारिज कर दी।

जाहिर है अब सरकार को भी प्रतिक्रिया देनी थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद कि रफाल सौदे में आठ करोड़ की दलाली दी गई है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने वे दस्तावेज थे जिसके बारे में मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है? अगर नए साक्ष्य भी आएंगे तब भी क्या जांच नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है।

महिलाओं के उत्थान में नीतीश सरकार ने निभायी अग्रणी भूमिका

नचिकेता पांडा

महिला सशक्तिकरण, देश, समाज और परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार जबसे सत्ता में आए तो उन्होंने अपने शुरूआती दौर से ही न्याय के साथ विकास के सिद्दांत का अनुसरण किया, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रमुख अवयव के रुप में शामिल रहा। प्रारंभ में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में तथा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, सूबे के सभी पुलिस जिलों में महिला पुलिस जिला थानाकी स्थापना, महिला बटालियन का गठन, 559 थानों में महिला शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था तथा ह्जीविकाह्व कार्यक्रम के तहत महिला-स्वयं सहायता-समूहों का गठन, महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम हैं। इन सभी पहल से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए, उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ और उनकी आत्मनिर्भरता दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है।

राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। बालिकाओं को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने एवं उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालिका पोशाक योजना, बालिका सायकिल योजना लागू की गई। योजना के वर्ष 2007-08 में प्रारंभ के समय नवम वर्ग में पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या मात्र 1 लाख 63 हजार थी जो वर्ष 2016-17 में लगभग 9 लाख 47 हजार पहुंच गयी। इसके बाद तो यह रफ्तार इतनी बढ़ी कीस्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। नीतीश सरकार ने मैट्रीक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना एवं हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर देश में एक नजीर पेश की। इससे बालिकाएं उच्च शिक्षा के प्रति तो जागरूक तो हुई हीं साथ ही उनके गतिशील होने से सामाजिक अनुशासन एवं भागीदारी की नींव रखी गयी। बच्चियों तथा माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने निरंतर पहल की, जिससे जननी बाल सुरक्षा योजना से संस्थागत प्रसव में आशातीत वृद्धि हुई है। गर्भवती-शिशुवती माताओं को आशा एवं ममता जैसी प्रशिक्षित कार्यकताओं से स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त हुआ। बिहार में नियमित टीकाकरण वर्ष 2005 में 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 84 प्रतिशत हो गया है।

राज्य सरकार ने आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय के तहत राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अवसर बढ़े, आगे पढ़े, निश्चय के तहत जी।एन।एम संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए।एन।एम संस्थान की स्थापना कर रही है। विकसित बिहार के सात निश्चय में एक शौचालय निर्माण घर का सम्मान भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए मार्च 2015 में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 लागू की गयी। जीविका परियोजना के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया था जो आज पूरा होने के करीब है।जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम हुई हैं। यह एक मूक क्रांति है। उनकी सांगठनिक शक्ति का बेहतरीन उदाहरण शराबबंदी है।

बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरूद्ध वर्तमान में विशिष्ट कानून लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अनुसार लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं समय-समय पर हुए इनके संशोधनों के अनुसार दहेज का लेन देन भी कानूनी अपराध है और कानून में दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बाल विवाह के कई कारण हैं यथा बालिका अशिक्षा, पिछड़ापन, गरीबी, लैंगिक असमानता, लड़कियों को लेकर असुरक्षा की भावना

आदि। बाल विवाह के दुष्परिणाम केवल बालिकाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं बल्कि अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करते हैं। बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है। कम उम्र में गर्भ धारण करने के कारण माताएं अस्वस्थ और कम अविकसित शिशु को जन्म देती हैं, जो आगे चलकर बच्चे बौनेपन एवं मंदबुद्धि के शिकार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य में वर्ष 2006 से 2016 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे बौनेपन का शिकार हो रहे हैं। जन्म से बालिकाओं के प्रति भेदभाव के चलते ही राज्य में बालिकाओं का शिशु मृत्यु दर 46 तथा बालकों का 31 है। यह राज्य में लैंगिक असमानता को भी बढ़ाता है। किसी भी बालिका को उम्र से पहले विवाह के बंधन में बांधकर उन्हें अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर उनके सर्वांगीण विकास को बाधित करना उनके मानव अधिकार का हनन है। बालिकाओं की शिक्षा का राज्य तथा देश की जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिल्कुल सीधा संबंध है। बेटियों का अगर बिना भेदभाव के समान रूप से पालन पोषण हो तो वे शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने तथा परिवार के लिए सहारा बनेंगी।

दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, जो कानूनन अपराध होने के बावजूद समाज में पूरी स्वीकार्यता के साथ व्याप्त है। यह प्रथा समय के साथ और व्यापक हुई है और समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीब वर्गों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2015 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वैसे तो महिला अपराध की दर में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का 26वां स्थान है पर दहेज मृत्यु के दर्ज मामलों की संख्या में बिहार का स्थान देश में दूसरा है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इनके विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त इन दोनों सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध लागू कानूनकी समीक्षा कर अपेक्षित संशोधन तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संरचानात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर नीतीश सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव लाया।

शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बिहार में साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर रहते थे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि पहले बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएंगे क्योंकि स्कूल तक पहुंचाना भी अपने आप में एक शिक्षा है। उसी का नतीजा है कि बच्चे-बच्चियों की संख्या स्कूलों में बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन किया गया। आगे की पढ़ाई के लिए निफ्ट (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी), चाणक्या लॉ यूनीवर्सिटी बना, आई।आई।एम। की तर्ज पर चंद्रगुप्त इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई। एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी बनाया गया। कई एग्रीकल्चर कॉलेज खुले, हॉर्टीकल्चर कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब खुले। इन सारे तथ्यों से नीतीश कुमार का महिलाओं के सम्मान को लेकर किए गए प्रयास का नतीजा है कि उनकी सरकार देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है।

...और आखिरकार चिराग तले अंधेरा ही रह गया

जब तक रामविलास पासवान थे, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) का अपना अलग वजूद था। वो अलग तरह की राजनीति करते थे। चाहे किसी की भी सरकार बने उनका मंत्री बनना तय था। ये बात अलग है कि बिहार की सियासत में भले ही उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया हो मगर देश की सत्ता में हमेशा काबिज रहे। एक नजर डालते हैं अपने पिता की विरासत संभाल रहे लोजपा के राजकुमार चिराग पासवान पर, तो ये जनाब पिता के निधन के बाद पार्टी को समेट पाने में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसका प्रमाण है एक ही दिन बिहार में लोजपा के 200 से अधिक नेताओं का जदयू में ज्वाइन कर लेना। इतना से भी अगर बात खत्म हो जाती तो मान लेते जिस भाजपा के प्रक्षेपास्त्र बनकर बिहार में नीतीश के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे उनकी एक मात्र विधान पार्षद नूतन सिंह ने भी लोजपा का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

राजनीतिक सुझबूझ का अभावः कोरोनाकाल के दौरान बिहार विधान सभा चुनाव 2020 का आगाज हुआ। इसी दौर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। हलांकि अपने जीते जी पासवान ने अपने इकलौते पुत्र चिराग पासवान को लोजपा की कमान सौंप दी थी। चिराग को लेकर राजनीतिक गलियारे में काफी उम्मीदें पाल रखी थी लोजपा ने तो विपक्षी इनकी कार्यशैली से खार खाए हुए थे। वक्त की नजाकत बदली और चिराग को बिहार विधान सभा 2020 चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई। उन्होंने मेहनत भी किया, मगर अफसोस की दिशाहीन होकर सत्तारुढ़ दल के खिलाफ ही मैदान में ताल ठोंक दिया। बात यहां तक होती तो चल भी जाती मगर जनाब भाजपा के कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजेंद्र सिंह और जनसंघी भाजपाई रामेश्वर चैरसिया, उषा विद्यार्थी को ही तोड़कर नीतीश कुमार को मात देने के लिए भाजपा को ही तोड़ने लगे। आज उसी का नतीजा है कि जदयू ने उनके 200 से अधिक सदस्यों को अपने साथ कर लिया तो भाजपा ने भी लोजपा विधान पार्षद नूतन सिंह को अपने साथ लाकर रही सही कसर पूरी कर दी।

नीतीश के साथ नहीं तो किसके साथः बिहार में नीतीश के चेहरे को आगे करके एनडीए ने चुनाव लड़ा और सत्ता पर पुनः काबिज हुई। बिहार का विकास मॉडल की पूरी दुनिया मुरीद है। जिस बिहार से लोग पलायन कर रहे थे, उस बिहार की गद्दी पर नीतीश के बैठने के बाद बिहार की परिभाषा ही बदल गई और आज की तारीख में बिहार विकास की इबारत लिख रहा है। पर्यटकों को लुभाने के साथ शिक्षा के अपने पुराने गौरव को वापस स्थापित कर रहा है। वैसे में लोजपा नेता चिराग पासवान, जो की अपरोक्ष रुप में भाजपा के गाईडलाइन पर काम करने की बातें कही जाती रही हैं। आज उसी चिराग तले अंधेरा रह गया है। लोजपा के एक मात्र विधायक राजकुमार सिंह ने एक बयान में कहा था कि वो उस एनडीए का हिस्सा हैं जिसके बिहार में नीतीश कुमार नेता हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी नेता हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान क्या बोलते हैं और नीतीश कुमार को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं इससे उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी की विचारधारा अलग है और उनकी व्यक्तिगत राय अलग है। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोजपा के अंदरखाने में क्या चल रहा है।

बसपा के बाद अब जनता दल युनाइटेड की नजर लोजपा पर है। पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह की हाल के दिनों में जदयू के नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। राजकुमार सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में कानून के राज को स्थापित करने से लेकर राज्य को नीतीश कुमार नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं।

अपने ही जाल में फंस गए चिरागः राजनीति को अपने फिल्मी करियर की तरह ही हल्के में लेने वाले चिराग पासवान अपने मूल से भटक गए या यों कहें की अतिमहत्वाकांक्षा ने उनकी लुटिया डूबो दी। बिहार की सियासत के तीन खिलाड़ी रामविलास, लालू और नीतीश हैं। लालू और नीतीश अपने-अपने तरीके से बिहार की सत्ता पर बने रहे। लेकिन रामविलास पासवान भी इनसे पीछे नहीं रहे और वो अपने संपूर्ण जीवन केंद्रीय मंत्री बनकर राज करते रहे। जिस तरह लालू ने नीतीश की पाठशाला में तेजस्वी और तेजप्रताप को राजनीति के पाठ पढ़ाए आज उसी का नतीजा है कि लालू के लाल कमाल कर रहे हैं। जबकि रामविलास के लाल चिराग को पासवान ने स्थापित कर ही दिया। इनके आने से तो लगा था कि बिहार की सत्ता में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। मगर यहां तो एनडीए के साथ रहकर भी एनडीए के एक साथी जदयू के खिलाफ पूरे चुनाव आग उगलते रहे उसी का नतीजा रहा कि लोजपाचारोखाने चीत हो गई।जिस वक्त चिराग को अपना कैंपेन चलाना था तो वो एनडीए के साथ रहकर नीतीश को उखाड़ फेंकने का सपना पाल रखे थे। वो शायद ये भूल गए कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जब नीतीश को बिहार में अपना नेता मानकर चुनाव मैदान में थी, तो इस इशारे को चिराग का नहीं समझना उनको उनके ही चाल में फंसा दिया।

बंगाल में छिड़ा सियासी जंग किसके सिर पर बंगाल का ताज?

'मातृदेवो भव' मातप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली की। रैली से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मोदी के साथ मंच साझा किया। प्रगतिशील बांग्ला और शोनार बांग्ला के नारे के साथ पीएम ने अपने भाषण की शुरूआत की। इसके बाद मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा हुए कई आरोप लगाए और कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ दिया और बंगाल को अपमानित किया।

मोदी ने कहा, कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है इसलिए ही कहा जा रहा है - लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। मोदी ने एक बार 'आशोल पोरिबोरतोन' की बात की। उन्होंने कहा, आशोल पोरिबोरतोन मतलब, ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल पोरिबोरतोन मतलब, ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी।मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में निवेश और उद्योग बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा की भी बात की। कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर (भविष्य का शहर) नहीं बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार को भी बल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टेक्नॉलॉजी, ऐसे विषयों की पढ़ाई, बांग्ला भाषा में भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा।

मोदी ने वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस के साथ आने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ लेकिन फिर बंगाल पर वोटबैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने और बढ़ाया और नारा दिया- कांग्रेसेर कालो हाथ, भेंगे दाओ, गुड़िये दाओ।

ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग तीन दशक तक सत्ता संभाली। आज उस काले हाथ का क्या हुआ? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं।

पीएम ने कहा कि न तो बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया और न ही औद्योगीकरण में। उन्होंने कहा कि माटी की बात करने वालों ने बंगाल का कण-कण, तिनका-तिनका, बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। मोदी ने राजनीति में खून खराबे का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अपनों का खून बहते देख रहे हैं, कई लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और कई पलायन के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने कहा, पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है- आर नॉय औन्नॉय। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ममता बनर्जी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आपको दीदी की भूमिका में चुना था। लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे-भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गईं? आप भी भाई-भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाईं, जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं आप तो भारत की बेटी हैं! कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सभी प्रार्थना कर रहे थे कि आप सकुशल रहें! अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है, उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेतीं।

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए और 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित, सभी दोस्तों को उनकी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी केंद्र सरकार की योजनाएं के लिए मिले पैसे का उपयोग नहीं कर रही। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है, उसका बहुत बड़ा

हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। बंगाल के चायवाले, यहां के टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे भाई-बहन तो मेरे विशेष दोस्त हैं। मेरे ऐसे कामों से उनकी भी अनेक परेशानियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से मेरे इन चायवाले दोस्तों को सोशल सेक्योरिटी स्कीम्स का भी लाभ मिलना तय हुआ है।

कोरोना वैक्सीन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टीका लगाने का प्रबंध किया। मोदी ने कहा कि ममता सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि करप्शन ओलंपिक्स का खेल आयोजित हो जाए। मोदी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य कर्ज.मे डूब गया। यहां भर्ती परीक्षाओं में, किस तरह का खेल होता है, छोटी-छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किस घर में जाकर मंजूरी ली जाती है, कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये किसी से छिपा नहीं है।अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा।

मोदी ने आरोप लगाया कि ममता मे उन्हें, कभी रावण कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा कहा। दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है, जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकताओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा।। ही सर्वोपरि है। जीवन में माता ही परवरिश का प्रथम गुरू है। मानव के जीवन का पहला आवास गर्भ होता है, जहाँ गर्भरूपी वस्त्र और भोजन मिलता है। ऐसी माता हीं सर्वप्रथम जीवन में बालिका होती है। ऐसे भी देखा जाय तो सृष्टि में नर और नारी के बिना सृष्टि अधूरा है। समाज में धरती को स्त्री और आकाश को पुरूष माना जाता है। उसी प्रकार सूर्य को पुरूष और चंद्रमा को स्त्री कहते है। वहीं सागर को पुरूष और नदियाँ को स्त्री कहते हैं।

वर्त्तमान समय में बालिकाओं के लिए व्यापक प्रबंध होने से कुरीतियों पर कुठाराघात हो रहा है। आज पूरे देश में, गाँव-गाँव में बालिकायें निर्भीक होकर साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगीं हैं। इसे परिवर्त्तन की ताजा हवा कहा जाता है। अब बालिकाओं के लिए गाँव-गाँव में शिक्षा का प्रचार और प्रशिक्षण का प्रबंध होना चाहिए ताकि बालिकाओं में शक्ति का संचार हो।

यह सही है कि प्रत्येक प्राणवान वस्तु, स्त्री और पुरूष में विभाजित है। भौगोलिक रूप से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वहीं सूर्य सम्पूर्ण आकाश-गंगा को आलोकित करती हैं, जिससे सूर्य का अस्तित्व पृथ्वी से ही प्रमाणित होता है। इसी तरह स्त्री की महत्ता भी है जो बालिका होने से ही प्रारंभ होती है। बालिका हीं विकसित हो कर माँ बनती है। जब बालिका रहेगी तभी हम माँ को बचा पायेंगे।

तकनीकी युग में तकनीक हमें समृद्ध करने के लिए बनाई गई है, लेकिन हमलोग इसी तकनीक का दुरुपयोग कर बालिकाओं की संख्या कम करने में लगे है, इसलिए लगता है कि यह तकनीक विनाश का कारण बन गया है। भारत में जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है वहीं उसे आज कई जगहों पर मात्र संतानोत्पत्ति का उपकरण माना जा रहा है। यह सही है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरूषवादी व्यवस्था यह भूल जाते हैं कि कुलवंश की वृद्धि बिना स्त्री के सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। तकनीक तो एक कारण है हीं, साथ ही दहेज प्रथा भी इसका एक कारण है। जिसके कारण लोगों में मात्र पुत्र की आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, इसलिए लोग नई तकनीक के माध्यम से गर्भ के लिंग की जाँच करा गर्भ को नष्ट कर देते हैं। जबकि यह एक जघन्य अपराध है। अब तो इन जघन्य पापों से बची हुई लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं रहतीं। शिशु से लेकर वयस्क लड़की कहाँ सुरक्षित है? आये दिन जबर्दस्ती की दिल दहला देने वाली घटनायें होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं से डरे हुए लोग भी लड़की को जन्म ही नहीं होने देना चाहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कंधों से कंधे मिलाकर महिलाओं/बालिकाओं ने भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मी बाई, बनमाला बोस, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई थी। भारत में केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बागडोर भी महिलाएँ ने सम्भाली थी।

जब प्रधानमंत्री की कुर्सी इन्दिरा गाँधी के हाथ में आई तब एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में महिला की ख्याति प्राप्त हुई। आज तो बालिकाओं ने देश की सेवा में सेनाओं के साथ भी डटकर खड़ी है। भारत में बालिका को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। लोग यह भूल रहे हैं कि समाज की आँखों में आँखें डालकर बालिकायें बता रही हैं कि मैं हर जगह परचम लहराऊँगी। इसलिए बुद्धिजीवीओं को सोचना पड़ेगा कि समाज को, जन जन को किसी तरह शिक्षित प्रशिक्षित किया जाय ताकि बलात्कार और हत्या जैसा जघन्य अपराध बंद हो सके। भारतीय बालिकायें किसी से कम नहीं है। उनके हाथों में जिसकी बागडोर थमाई जाय, वह बखूबी कुछ उत्कृष्ट करके दिखा देती हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ स्त्री कार्यरत नहीं है। देश की आतंरिक सुरक्षा यानी पुलिस, बाह्य सुरक्षा यानि सेना सभी स्थान पर बालिकायें बखूबी काम सँभाल रही हैं।

पीएम मोदी ने लॉकडाउन क्या अहम मंत्रालयों से पूछे बगैर लगाया था?

कोरोना वायरस के कारण देश में पहली बार लॉकडाउन लगाने की घटना को एक साल पूरा हो गया है-

क्या आपको ये शब्द याद हैं? - ष्आज से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अगले 21 दिनों तक आपको यह भूल जाना होगा कि घर से बाहर निकलना क्या होता है।

24 मार्च रात आठ बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को रोक दिया था ताकि, ष्कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके और संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सके।

जिस दिन पीएम ने लॉकडाउन का एलान किया, उस दिन तक देश में कोविड-19 के 519 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। संक्रमण से नौ मौतें भी हो चुकी थीं। प्रधानमंत्री ने उस रात अपनी स्पीच में बताया था कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए राज्य सरकारों से मिल कर काम कर रही है। साथ ही सरकार स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर भी काम कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने यह दिखाया था कि अगले ढाई महीनों तक इस वायरस पर अपनी निगरानी और इसे रोकने की अपनी कोशिश के तहत यह सबको साथ लेकर चली है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, ष्प्रधानमंत्री खुद कोरोना संक्रमण को रोकने और इसके खिलाफ कदम उठाने की तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। हालांकि, बीबीसी की ओर से की गई एक विस्तृत पड़ताल ने साफ किया है कि केंद्र की ओर से कोरोना के खिलाफ सबसे कड़ा कदम यानी लॉकडाउन लगाने से पहले सलाह-मशविरे की प्रक्रिया बहुत कम या नहीं के बराबर अपनाई गई।

बीबीसी ने सूचना का अधिकार कानून, 2005 का इस्तेमाल करते हुए कई प्रमुख एजेंसियों, संबंधित सरकारी विभागों और कोरोना संक्रमण से पैदा हालातों को काबू करने में जुटे राज्य सरकारों से संपर्क किया। हमने पूछा कि क्या उन्हें पूरे देश में लगाए जाने वाले लॉकडाउन के बारे में पहले से पता था? क्या उन्हें पता था कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके विभागों और क्षेत्र को क्या तैयारी करनी है। या फिर लॉकडाउन से पैदा मुश्किल हालातों को कम करने के लिए क्या तैयारी करनी है? 1 मार्च, 2021 को हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संपर्क साधा ताकि इस स्टोरी के लिए केंद्र सरकार के नजरिये का पता चल सके। लेकिन अब तक न तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और न ही उनके सचिव अमित खरे इंटरव्यू

देने के लिए राजी हुए हैं।

बीबीसी ने जिन लोगों से बात की या संपर्क किया, उनमें से अधिकतर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन कैसा होगा इस बारे में उनसे कोई मशविरा नहीं किया गया और न ही उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी। तो फिर भारत सरकार ने कैसे यह फैसला ले लिया कि लॉकडाउन लगाना है? और लोगों की मदद के लिए लागू किए जाने वाले लॉकडाउन के बारे में सरकारी मशीनरी और इसके अहम हिस्सों को पता कैसे नहीं था?

जनवरी 2020 के मध्य से ही यानी 24 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान से दो महीने पहले ही केंद्र सरकार ने कहा था कि वह कोरोना संक्रमण पर पूरी मुस्तैदी से निगाह रखे हुए है और इसे रोकने की तैयारी कर रही है। 22 फरवरी, 2020 को जब भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशाल स्वागत समारोह की तैयारी में लगा था तो देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ। हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि, ष्भारत का मजबूत हेल्थ सर्विलांस सिस्टम कोरोना संक्रमण को देश में घुसने से रोकने में कामयाब रहा है। जब देश में धीरे-धीरे कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो 5 मार्च 2020 को उन्होंने संसद में कहा, केंद्र और राज्य सरकारें पीपीई किट और 95 मास्क का बफर स्टॉक बनाए हुए हैं। देश के स्पेशलियटी केयर अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का पूरा इंतजाम है ताकि संक्रमण से लड़ा जा सके।फिर भी, तीन सप्ताह से कम वक्त के भीतर ही देश भर में एक कड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के अपने फैसले को मजबूती देने के लिए 24 मार्च को केंद्र सरकार ने कहा कि पीएम के ऐलान से पहले ही ष30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (पहले से ही) पूरी तरह लॉकडाउन लगा चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नहीं बताया वो यह कि लॉकडाउन के ज्यादातर फैसले राज्यों ने अपने यहां के हालातों और तैयारियों के मद्देनजर खुद लिए थे। कुछ राज्यों में लॉकडाउन 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी थे। जबकि प्रधानमंत्री ने जिस लॉकडाउन का ऐलान किया था, वह पूरे तीन सप्ताह तक चलने वाला था।

।।और बाकी दुनिया में क्या हो रहा था

भारत ने जब लॉकडाउन की घोषणा की उस दौरान कुछ यूरोपीय देशों ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया था लेकिन वहां बड़े पैमाने पर पाबंदियां लागू कर दी गई थीं। इनमें इटली (डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त तक यहां कोरोना संक्रमण के 60 हजार मामले सामने आ चुके थे। लगभग छह हजार लोगों की मौतें भी हो चुकी थी), स्पेन (उस वक्त तक कोरोना संक्रमण के 50 हजार मामलों की पुष्टि हो चुकी थी और तीन हजार लोग मारे जा चुके थे) और फ्रांस (उस वक्त तक यहां कोरोना संक्रमण के 20 हजार मामले आ चुके थे और इस कारण 700 मौतें हो चुकी थीं)। लेकिन चीन में उस वक्त तक कोरोना संक्रमण के 80 हजार केस सामने आ चुके थे और 300 मौतें हो चुकी थीं। इसके बावजूद उसने सिर्फ हुबेई प्रांत में लॉकडाउन लगाया था। चीन ने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही 24 मार्च को सार्वजनिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन सरकार की फाइलों में यह काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश के जरिये हो चुका था। यह आदेश संख्या थी 1-29/2020। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री एनडीएमए के चेयरपर्सन हैं। एनडीएमए के पॉलिसी एंड प्लान डिवीजन की ओर से जारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को संबोधित 24 मार्च 2020 के आदेश में कहा गया है, लॉकडाउन से संबंधित तमाम कदमों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने और अमल में लाने की जरूरत है।।। एनडीएमए ने भारत सरकार के मंत्रालयोंध्विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्रशासनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश देने का फैसला किया है ताकि देश में कोविड-19 को देश भर में फैलने से रोका जा सके।गृह सचिव एनडीएमए की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने उसी दिन निर्देश जारी किए। इस तरह लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी चल रही थी। इस बारे में पता करने के लिए हमने एनडीएमए से संपर्क किया। हमने अपने आरटीआई आवेदन में उन सभी सार्वजनिक प्रशासनोंध्विशेषज्ञोंध्व्यक्तियोंध्सरकारी संस्थानोंध्निजी संस्थानों और राज्य प्रशासनों की सूची मांगी, जिनसे लॉकडाउन से जुड़े फैसले लागू करने से पहले सलाह-मशविरा किया गया था।

हम यह जानना चाह रहे थे कि 24 मार्च, 2020 से पहले कोरोना संक्रमण पर एनडीएमए की कितनी बैठकें हुईं, जिनमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे थे। हमारे आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा गया कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। कोरोना एनडीएम से मिली जानकारी

याद कीजिये कि इस मामले को किस तरह दिखाया गया- यही कि प्रधानमंत्री खुद इस संक्रमण की शुरूआत से ही इसके बचाव में उठाए जा रहे कदमों का नेतृत्व कर रहे हैं? इसलिए हमने कोरोना संक्रमण से जुड़ी पीएमओ की उन सभी बैठकों की सूची मांगी, जिनमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे थे। हमने उन सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सलाहकारों की सूची मांगी, जिनसे नेशनल लॉकडाउन घोषित किए जाने से पहले पीएमओ ने सलाह-मशविरा किया था। पीएमओ ने दो बार मांगी गई सूचना नहीं दी। एक बार हमारी दरख्वास्त श्अस्पष्टश कह कर रद्द कर दी गई। कहा गया कि आवेदन श्रोविंग इन नेचरश है।संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीएमए की कोई बैठक नहीं हुई थी।

दूसरा आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि यह आरटीआई एक्ट, 2005 के सेक्शन 7(9) के तहत आता है। इस सेक्शन में कहा गया है, ष्किसी सूचना को उस प्रारूप में तभी मुहैया कराया जाएगा जब वह सार्वजनिक अथॉरिटी के संसाधनों को असंगत तौर पर दूसरी ओर न मोड़े या फिर जो रिकॉर्ड मांगा गया है वह तभी दिया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि यह आवेदन इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए खतरा नहीं है। लेकिन सरकार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मसले पर काम करने वालीं अंजलि भारद्वाज के मुताबिक यह सेक्शन सरकार को सूचना मुहैया कराने से छूट नहीं देता। उन्होंने कहा, ष्यह सेक्शन सिर्फ यह कहता है कि अगर सरकार को लगता है कि आवेदन पर सूचना देने में इसे जरूरत से ज्यादा समय और संसाधन खर्च करना होगा तो यह किसी दूसरे रूप में मुहैया कराई जा सकती है। हालांकि मैं सोचती हूं कि सेक्शन 7(9) के तहत सूचना देने से इंकार करना गैरकानूनी है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान करने से चार दिन पहले यानी 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। लेकिन पीएमओ की ओर से जारी इसकी प्रेस-रिलीज में श्लॉकडाउनश शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं था। लिहाजा हमने यह जानकारी मांगी कि बैठक में देशभर में लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर चर्चा हुई थी या नहीं? लेकिन पीएमओ ने हमारे आरटीआई आवेदन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया। इसके बाद वहां से यह गृह मंत्रालय को भेजा गया। और आखिर में वही प्रेस रिलीज देखने को कह दिया गया, जो 20 मार्च की बैठक के बाद पीएमओ की ओर से जारी की गई थी।

अब गृह मंत्रालय की बात करते हैं

इस रिपोर्ट के संदर्भ में इन दो पहलुओं की वजह से गृह मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला यह कि गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत ही देश में लगे लॉकडाउन से जुड़े निर्देश जारी किए गए थे। दूसरा पहलू यह कि लॉकडाउन का फैसला लेने में विभिन्न अहम विभागों और मंत्रालयों ने योगदान दिया था, उसके बारे में जानने के लिए जब भी हमने उन्हें आरटीआई आवेदन किया, उन्हें गृह मंत्रालय भेज दिया गया। जिन विभागों और मंत्रालयों ने हमारे आरटीआई आवेदनों को गृह मंत्रालय को भेजा था उनमें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, वित्त मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैसी संस्था शामिल थीं। हमने लॉकडाउन के ऐलान के पहले गृह मंत्रालय में हुए विचार-विमर्श को भी जानने के लिए आरटीआई आवेदन दिया लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया।

आरटीआई आवेदनों को खारिज करने की वजह क्या थी? हमने गृह मंत्रालय को जो आवेदन दिया था, उसके जवाब में कहा गया, सूचना के आधिकार, 2005 के सेक्शन 8(1) और (म) के तहत देश के रणनीतिक और आर्थिक हित और इससे जुड़ी ऐसी सूचनाएं, जिनसे विश्वास के संबंध पर विपरीत असर पड़ता है, आरटीआई के तहत प्रकट नहीं की जा सकतीं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में दाखिल हमारे जिन आरटीआई आवेदनों को गृह मंत्रालय को भेजा गया था, उनके जवाब में भी यही दोहराया गया। कुछ मामलों में गृह मंत्रालय ने उन आवेदनों को उन्हीं मंत्रालयों और विभागों को वापस भेज दिया, जहां से वे इसके पास आए थे। गृह मंत्रालय ने उन्हीं मंत्रालयों को हमारे उन आवेदनों का जवाब देने को कहा।

क्या राज्यों को लॉकडाउन के फैसले के बारे में पता था? देश की राजधानी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को केंद्र की ओर से लॉकडाउन लगाए जाने से पहले विचार-विमर्श किए जाने की कोई सूचना नहीं थी। इसी तरह का जवाब असम और तेलंगाना के सीएमओ (बेपर्मा डपदपेजमते ंिपबमे) ने भी दिया। उनका भी कहना था कि उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, जिससे ये संकेत मिलता कि लॉकडाउन लगाने से पहले कोई विचार-विमर्श हुआ था। यह भी दिलचस्प है कि जब हमने उत्तर प्रदेश सीएमओ को इस संबंध में अपना आरटीआई भेजा तो उन्होंने इसे यह कहकर लौटा दिया कि केंद्र सरकार से ही पता कर लें। पूर्वोत्तर भारत को महामारी से बचाने के लिए संबंधित राज्यों के साथ मिल

कर काम कर चुके केंद्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने भी कहा कि लॉकडाउन से पहले उससे कोई मशविरा नहीं किया गया।

कोरोना वायरस मामले में बने मंत्रियों के समूह का क्या हुआ?

3 फरवरी, 2020 को सरकार ने पीएम के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय मंत्री समूह के गठन का ऐलान किया, ताकि ष्नोवल कोरोना वायरस के प्रबंधन की समीक्षा की जा सके।

मंत्रियों के इस समूह की अगुवाई कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉ। हर्ष वर्धन। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की अगुवाई करने वाले मंत्री भी शामिल थे। 3 फरवरी से लॉकडाउन लागू होने के बीच मंत्रियों के इस समूह की कई बार बैठकें हुईं। उन्होंने सभी अंतरराष्ट्रीय कॉमर्शियल यात्री विमानों की भारत में एंट्री रोकने समेत कई अहम ऐलान किए। हमने कैबिनेट सचिवालय से भी यह पूछा कि क्या उनके पास ऐसी कोई सूचना थी, जिससे यह पता चले कि मंत्रियों के इस समूह ने लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी या फिर इस पर कोई सलाह-मशविरा किया था।

हमने कैबिनेट सचिवालय से यह सवाल क्यों पूछा?

हमने कैबिनेट सचिवालय से इसलिए पूछा क्योंकि ष्यह (कैबिनेट) सचिवालय ही कैबिनेट और इसकी कमेटी को सचिवालय संबंधी सहायता देता है। साथ ही यह अंतर-मंत्रालय को-ऑर्डिनेशन के जरिये सरकार के अंदर फैसले लेने में मदद करता है। यह देश में किसी बड़े संकट की स्थिति को संभालने और इसके प्रबंधन में भी मदद करता है। ऐसी स्थिति में तमाम मंत्रालयों के बीच को-ऑर्डिनेशन से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देना भी कैबिनेट सचिवालय का ही काम है। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने भी हमारा आरटीआई आवेदन गृह मंत्रालय को भेज दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद गृह मंत्रालय से यह जवाब आ गया ष्मांगी गई सूचना आरटीआई एक्ट, 2005 के सेक्शन 8(1) (ं) और (म) के दायरे में नहीं आती। यही आरटीआई आवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय में भी दाखिल किया गया है लेकिन अभी तक वहां से इसका जवाब नहीं आया है। मंत्रालय का जवाब आते ही हम इसे शामिल कर स्टोरी को अपडेट कर देंगे। कैबिनेट सचिवालय से जो जानकारी मिली उसमें यह बताया गया कि लॉकडाउन के पहले कुछ दिनों के दौरान यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी लेकिन इसमें कोरोना महामारी या लॉकडाउन की कोई चर्चा हुई, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई।

हमें पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तो लॉकडाउन के बारे में पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने सरकार के थिंक टैंक नीति-आयोग के वाइस चैयरमैन डॉ। राजीव कुमार से इस बारे में पूछा। डॉ। कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन बगैर किसी योजना के लगा दिया गया। भारत की विविधता और इसकी कमजोरियों को देखते हुए इसे ऐसे ही लॉकडाउन की जरूरत थी। हमने लॉकडाउन पर चर्चा की थी। इसके बाद ही इसे लागू किया गया। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इसे यूं ही लगा दिया गया। पीएम ने हर किसी से बात की थी।

हमारे आरटीआई आवेदनों पर एनडीएमए और गृह मंत्रालय से हमें जो जवाब मिले थे उनकी समीक्षा करते हुए अंजलि ने कहा, जब आपदा प्रबंधन की बात आती है तो सरकार के अधिकार काफी व्यापक हो जाते हैं। हालांकि इस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। ष्कोरोना वायरस के मामले जनवरी में ही आने शुरू हो गए थे और भारत में लॉकडाउन लगाया गया मार्च के आखिरी हफ्ते में। यह कोई बाढ़ या भूकंप नहीं था जो रातों-रात आ गया हो। इसलिए पीएम ने जब लॉकडाउन का एलान किया तो यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि इसका फैसला करने से पहले सलाह-मशविरा हुआ होगा और सभी क्षेत्रों की तैयारियों का जायजा लिया गया होगा। हमारे आरटीआई आवेदन जिस तरह से खारिज हुए इस पर उनका कहना था, ष्जो जवाब मिले हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार के अंदर सलाह-मशविरे की ऐसी कौन-सी बात होती है, जिसे गुप्त रखा जा सकता है और जिसे जनता से साझा नहीं किया जा सकता। यह नजरिया लोकतंत्र की शुचिता के खिलाफ है। जब उनसे पूछा गया कि राज्यों को तो लॉकडाउन के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई तो उन्होंने कहा, ष्इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे सवाल नहीं किए जा सकते। राज्य तो यह कह कर आसानी से पल्ला झाड़ लेंगे कि हमें को कुछ पता ही नहीं था।

आयकर की छूट पा रहे ट्रस्ट-सोसाइटी या संस्थानों का फिर से होगा आकलन

इसे लेकर इनकम टैक्स के नियम में किया गया अहम बदलाव, 1 अप्रैल से यह नियम हो गया लागू

पहले यह सुविधा पा रहे सभी संस्थानों से कहा गया 30 जून तक ऑनलाइन कर लें आवेदन

इनकम टैक्स रिटर्न दायर और अपनी आय प्रदर्शित करने की छूट पा रहे ट्रस्ट-सोसाइटी या ऐसे अन्य सभी तरह के संस्थानों का फिर से आकलन किया जायेगा। यह सभी तरह के चैरिटेबल और धार्मिक संस्थानों पर भी लागू होगा, जिन्हें जनसेवा या अन्य तरह की सेवाओं के नाम पर आयकर देने से छूट मिली हुई है। आयकर विभाग इनके इनकम और कार्यप्रणाली का फिर से मूल्यांकन करेगा। इसके बाद यह तय किया जायेगा कि इन्हें आयकर देने या आय प्रदर्शित करने की छूट जारी रखी जाये या नहीं। इसके लिए एक अप्रैल से 30 जून तक सभी संबंधित संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसके बाद इन सभी चैरिटेबल संस्थानों से जुड़े तमाम पहलुओं की समुचित जांच करने के बाद ही उन्हें आयकर देने से छूट प्रदान की जायेगी। जो संस्थान निर्धारित समयसीमा के अंदर आवेदन नहीं करेंगे, उनका निबंधन स्वत रद्द मान लिया जायेगा। जो संस्थान सभी मानक पर सही पाये जायेंगे, उन्हें एक यूआरएन यानी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा। इसके आधार पर ही इन संस्थानों की अपनी पहचान होगी।

बिहार में काफी पुराने संस्थानों का कोई हिसाब ही नहीं : बिहार में हाल के कुछ वर्षों में करीब 10 हजार संस्थानों को आयकर विभाग की तरफ से 12-ए सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अपनी आय पर टैक्स देने में छूट मिली हुई है। परंतु बिहार में बहुत बड़ी संख्या ऐसे संस्थानों की भी है, जो ये सुविधा 30-35 साल या इससे ज्यादा समय से उठा रहे हैं। इन बेहद पुराने संस्थानों की संख्या बिहार में कितनी है, इसकी कोई सूचना आयकर विभाग के पास नहीं है। अब नये स्तर से संस्थानों का रजिस्ट्रेशन होने से विभाग को एकदम सटीक आंकड़ा मिल जायेगा कि कितने संस्थानों को ऐसी सुविधा प्राप्त है।

आयकर के नियम में हुआ अहम बदलाव : केंद्र सरकार ने इससे संबंधित आयकर विभाग के कानून 12-ए में एक अहम बदलाव किया है। पहले 12-ए सर्टिफिकेट जिस संस्थान, ट्रस्ट या सोसाइटी को मिल जाता था, उन्हें सालाना अपनी आय दिखाने और किसी तरह का टैक्स देने से पूरी तरह से छूट मिल जाती थी। यह छूट उन्हें आजीवन मिलती रहती होती थी। परंतु अब इसमें अहम संशोधन करते हुए संस्थानों को 12-ए-बी सर्टिफिकेट दिया जायेगा। इस नये बदलाव में यह किया गया है कि यह सर्टिफिकेट सिर्फ पांच साल के लिए वैद्य होगा। प्रत्येक पांच साल पर इन्हें अपने क्रिया-कलापों को प्रदर्शित करते हुए आय की पूरी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट के साथ देनी होगी। यानी प्रत्येक पांच साल पर इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा। इसके बाद ही उन्हें अपने आय पर इनकम टैक्स देने की छूट जारी रहेगी। अगर कोई गड़बड़ी पायी गयी, तो यह सर्टिफिकेट रद्द हो जायेगा और संबंधित संस्थानों को टैक्स जमा करना होगा। यह नियम एक अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया है।

दुनिया की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक है सिंगापुर

ज्यादातर भारतीय पर्यटक दुबई जाना पसंद करते हैं। पीक सीजन में तो दुबई जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वहीं दुबई के अलावा सिंगापुर एक ऐसा टूरिस्ट स्पोर्ट है, जो अन्य विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से टॉप पर है। अगर आप भी विदेश में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिंगापुर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आइए, जानते हैं यहां क्या है खास। सिंगापुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में तीन संग्रहालय, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर, सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिन्दू, चीनी व बौद्ध मंदिर तथा चीनी व जापानी बाग शामिल हैं।

स्नैक्स के साथ सिंगापुर के स्पेशल जायकों का लीजिए मजा

यहां फैले फूड स्टॉल्स में कई व्यंजन मिलते हैं। पाक कला और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जुलाई के महीने सिंगापुर में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। सिंगापुर में मेक्डोनाल्ड, पीजा हट, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, जैसे इंटरनैशनल फूड चेन रेस्त्रां भी मिल जाएंगे। अगर आपको च्युइंगम पसंद है, तो सिंगापुर प्रवास के दौरान परेशानी हो सकती है। यहां पर च्युइंगम बैन है।

डेस्टिनेशन : कपल के लिए जन्नत से कम नहीं है ऊटी, इन खूबसूरत जगहों में बसी है दुनिया

लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लेजर लाइटों से सिंगापुर की हर गली जगमगा उठती है। आर्चर रोड, सिंगापुर रिवर, बरस बासा, बुगीस, सीबीडी और मरीना बे में बोट का रोमांचकारी सफर, नदियों पर लेजर शो रोशनाई का

आयोजन, पेड़ पर लिपटी लाइटें रात के समय बहुत ही दिलचस्प लगती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहां जाते हैं, तो आपकी ट्रिप और भा यादगार बन जाएगी।

भारतीय संस्कृति की झलक

सिंगापुर में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए यहां के फेसम मॉल्स में भारतीय सामान आसानी से मिल जाते हैं। कपड़े, एंटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, टीवी, गैजेट्स, मोबाइल्स, परफ्यूम, साज-सजावट के सामान, ब्यूटी प्रॉडक्ट्स के अलावा एक से बढ़कर एक बेहतरीन चीजें यहां के मार्केट में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप भारतीय खाने को मिस करें, तो आपको यहां कई भारतीय डिश भी मिल जाएगी।

नेचर की सुंदरता के लिए घूमें 158 साल पुराना बोटेनिकल गार्डन

सिंगापुर पर्यावरण के नजरिए से भी बेहतर प्लेस माना जाता है। यहां स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। शायद ही कोई जगह मिले, जहां गंदगी दिख जाए। शहर की शान को बढ़ाती गगनचुंबी इमारतें सुखद अहसास देती हैं। आप सिंगापुर दर्शन के लिए जाएं, तो बॉटेनिकल गार्डन जरूर देखें। यह 158 साल पुराना गार्डन है। इस गार्डन को देखकर आपको लगेगा कि सिंगापुर को प्रकृति का वरदान मिला है। सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन 52 हेक्टेयर इलाके में फैला है, जहां नेशनल ऑर्किड कलेक्शन के तहत तीन हजार से ज्यादा ऑर्किड उगाए गए हैं। यहां की सरकार सुंगेई बुलोह वेटलैंड्स रिजर्व को लोगों को उनके आधुनिक जीवन के तनाव से दूर करने के लिए इसे एक शांत डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रही है।

कैसे पहुंचे

आप इंटरनेशनल फ्लाइट से सिंगापुर पहुंच सकते हैं। यहां घूमने के लिए टूरिस्ट कैब और टैक्सी उपलब्ध है।

कब जाएं

फरवरी से अप्रैल के बीच का मौसम बहुत खुशनुमा रहता है।

बीमारी की वजह बनी बर्फ, जांच में 95% बर्फ के नमूने फेल

कुमारी स्मिता

अगर आप भी तपती गर्मी से निजात पाने के लिए बर्फ से बनने वाली चीजों की ओर रुख कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। हाल में बीएमसी द्वारा बर्फ के गोले, शरबत और जूस की दुकानों से जांच के लिए बर्फ के ढेरों नमूने लिए गए थे। इस जांच में करीबन95 प्रतिशत बर्फ के नमूने फेल हो गए और खाने-पीने लायक नहीं पाए गए।

खतरनाक बैक्टिरिया

74 प्रतिशत बर्फ के नमूनों में पेट की बीमारी फैलाने वाले ई-कोलाई बैक्टिरिया पाए गए। ऐसे में डॉक्टरों ने सड़क किनारे लगने वाली जूस की दुकानों और बर्फ से बनने वाले अन्य उत्पादों से दूरी बनाने की सलाह दी है। मुंबई में इन दिनों तापमान के तेवर चढ़े हुए हैं।

नतीजतन लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बाहर खुले में बिकने वाले बर्फ मिश्रित पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी में बीएमसी द्वारा 363 बर्फ के नमूने होटलों, जूस स्टॉल और डिस्ट्रिब्यूटर्स से कलेक्ट किए गए थे। जांच में 363 नमूनों में 346 नमूने खाने योग्य नहीं थे, जबकि 270 नमूनों में ई-कोलाई बैक्टिरिया होने की बात सामने आई। केईएम अस्पताल के डीन डॉ. अविनाश सुपे कहते हैं, ई-कोलाई बैक्टिरिया से लोगों में चेस्ट व लिवर इन्फेक्शन, जुलाब, उल्टी, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। ऐसे में बचाव के मद्देनजर बाहर के अस्वच्छ खाने-पीने वाली चीजों से परहेज करना चाहिए।

बढ़ रही है पेट की बीमारी

दूषित खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन से पेट संबंधी समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा स्वच्छ और ताजा खाना खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि दौड़ती-भागती जिंदगी में इन बातों का ध्यान रखना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। शायद यही वजह है कि महानगर में पेट से संबंधित बीमारियों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी से फरवरी के बीच मुंबई में 1362 लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियों की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। आंकड़े के अनुसार, इस वर्ष जनवरी में 722 और फरवरी में 640 लोग गैस्ट्रो बीमारी की चपेट में आए, जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 635 और फरवरी में 578 था। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. ओम श्रीवास्तव ने बताया कि ई-कोलाई बैक्टिरिया पेट की बीमारियों को जन्म देने का एक मुख्य कारण है। यह बैक्टिरिया दूषित खाने और पानी में पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर पेट की बीमारियों को जन्म देते हैं।

14 साल में इतना गंभीर हो गया है गॉलब्लडैर कैंसर

दिल्ली समेत उत्तर भारत में गॉलब्लैडर कैंसर के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में पुरुषों को प्रभावित करने वाले सभी कैंसरों के बीच गॉलब्लैडर कैंसर (जीबीसी) का स्थान 1998 में 24वां था वहीं महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसरों के बीच इसका स्थान पांचवां था। लेकिन 14 सालों में यानी 2012 के आंकड़े के मुताबिक पुरुषों के प्रभावित करने वाले कैंसरों में इसका स्थान नौवां और महिलाओं के लिए तीसरा स्थान हो गया है। दरअसल यह चौंकाने वाला खुलासा एम्स के रिसर्चर्स द्वारा तैयार एक रिपोर्ट से हुआ है जिनलगों ने सरकार के आबादी आधारित कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत दिल्ली में जीबीसी केसों के 25 साल के डेटा का विश्लेषण किया है।

गॉलब्लैडर क्या है?

गॉलब्लैडर पाउच जैसा एक छोटा अंग है जो लिवर के नीचे पाया जाता है। इसमें बाइल नाम का लिक्विड स्टोर रहता है जो लीवर से पैदा होता है। यह लिक्विड वसा वाले खाने को तोड़ने का काम करता है। शरीर के अंदर बने जहरीले पदार्थों को हटाने का काम बाइल करता है।

दिल्ली समेत उत्तर भारत सर्वाधिक प्रभावित

जनसंख्या आधारित रजिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि उत्तरी भारत खासकर गंगा के इलाके और पूर्वी भारत में देश के अन्य भाग के मुकाबले जीबीसी के ज्यादा केस पाए जाते हैं। डॉ.रथ ने बताया, 'जीबीसी भारत में इतना सामान्य क्यों है, इसका सही कारण किसी को पता नहीं है। हम इस क्षेत्र के कैंसर मरीजों का जेनेटिक विश्लेषण कर रहे हैं। इसका मुकाबला अन्य इलाके के लोगों के जींस से किया जाएगा।' डॉ.जी.के.रथ, प्रफेसर एवं एम्स के भीमराव आंबडेकर इंस्टिट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल (ब्रेर्च) ने कहा कि दिल्ली में जीबीसी के 11 केस प्रति 1 लाख आबादी पाए जाते हैं। दिल्ली देश का दूसरा राज्य है जहां जीबीसी के ज्यादा मामले पाए जाते हैं। असम के कामरूप जिले में सबसे ज्यादा 17 केस प्रति 1 लाख आबादी पाए जाते हैं। रथ ने बताया, 'जीबीसी घातक कैंसरों में से एक है। बहुत सारे मामले में बीमारी का पता देर से चलता है जब सर्जरी नहीं की जा सकती है और मामला सामने आने के एक साल के अंदर 95 फीसदी मरीजों की मौत हो जाती है।'

संभावित कारण

जीबीसी में तेज वृद्धि का सही कारण पता नहीं है। डॉक्टरों का अनुमान है कि बढ़ती हुई मोटापा और पर्यावरण की समस्याएं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। वैसे तो जीबीसी का गॉलस्टोन से काफी गहरा संबंध है लेकिन कई अन्य चीजें जैसे मोटापा, स्मोकिंग, शराब का सेवन, खाने की आदत और अभ्यास से भी इसका संबंध है। एक स्टडी में पता चला है कि स्मोकिंग न करने वालों के मुकाबले स्मोकिंग करने वाले लोग में जीबीसी होने का ज्यादा खतरा रहता है। एक डॉक्टर ने बताया, 'हाल की एक स्टडी में पता चला है कि 1998 से 2010 तक पुरुषों में स्मोकिंग के मामले 220 फीसदी बढ़ गए हैं जबकि 2005-10 के बीच महिलाओं में यह दोगुना हो गया।' उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक में दिल्ली की आबादी के बीच फास्ट फूड, फ्राइड फूड का सेवन काफी बढ़ गया है इससे भी जीबीसी का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी में कहा गया है कि इसका एक कारण दूषित पानी भी हो सकता है। दिल्ली में पेयजल का मुख्य स्रोत गंगा और यमुना नदी हैं। दोनों नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। डॉ.रथ ने बताया कि इस बीमारी का हल या रोकथाम का पता लगाने के लिए रिसर्च की फंडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) कर रहा है।

एनएसए के दुरुपयोग को लेकर सवालों में यूपी सरकार, हाईकोर्ट ने 120 में 94 केस किए रद्द

एक बार फिर यूपी सरकार ठरअ के दुरुपयोग को लेकर सवालों के घेरे में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका दिया है। योगी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (ठरअ) के तहत 120 मामलों में से 94 मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 120 मामलों की सुनवाई में यह फैसला दिया है।

दरअसल यूपी में जनवरी 2018 से लेकर दिसबंर 2020 तक एनएसए के तहत 120 मामले दर्ज कराए गए थे। जिनमें से 94 मामलें रद्द कर दिए गए। रद्द किए गए 94 मामलों में से 32 मामले डीएम की तरफ से दर्ज कराए गए थे। बता दें कि, इन मामलों में कोर्ट ने कैद किए गए लोगों को भी छोड़ने के आदेश दिए हैं।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कोर्ट में दर्ज रासुका के मामलों का अध्ययन किया। जिसमें सभी मामलों में एक खास पैटर्न नजर आया है।

गौहत्या के आरोप सबसे ऊपर

जिन मामलों में रासुका लगाया गया है उनमें गौहत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं। कुल 41 मामले ऐसे हैं जिनमें गौहत्या का आरोप लगाया गया है, ये हाईकोर्ट पहुंचे कुल मामलों के एक तिहाई के बराबर हैं। इन सभी मामलों में जिन्हें आरोपी बनाया गया है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इन पर गौहत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें जिलाधिकारी के आदेश पर हिरासत में लिया गया।

बता दें कि, इनमें से 30 मामलों में हाई कोर्ट ने यूपी प्रशासन को तगड़ी फटकार लगाते हुए आदेश को रद्द कर दिया और याची को फौरन रिहा करने के आदेश दिए। बाकी बचे 11 मामले में से भी सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें हिरासत बरकरार रह सकी। उसमें भी लोवर कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने यह कह कर जमानत दे दी कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है।

इस पड़ताल में कुछ मुख्य बातें जो सामने आई हैं वो कुछ इस तरह है:-

झ 11 मामलों में, अदालत ने आदेश पारित करते हुए डीएम द्वारा दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करने का हवाला दिया है।

13 मामलों में, अदालत ने कहा कि हिरासत में लिए गए शख्स को एनएसए को चुनौती देने के लिए सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने का अवसर से वंचित किया गया था। सात केस में, अदालत ने कहा कि ये मामले कानून और व्यवस्था के दायरे में आते हैं और एनएसए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6 मामलों में कोर्ट ने पाया कि हिरासत में लिए गए आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

कॉपी-पेस्ट की कहानी

इन सभी एफआईआर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानों इन्हें कट-पेस्ट किया गया हो। करीब 9 मामलों में, एफआईआर के आधार पर एनएसए लगाया गया था जिसमें दावा किया गया था कि गो हत्या को लेकर अज्ञात मुखबिर की खबर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।13 मामले उन एफआईआर के आधार पर थे, जिनमें दावा किया गया था कि गो हत्या कथित तौर पर खुले कृषि क्षेत्र या एक जंगल में हुआ था। 9 मामलों में, डीएम ने एफआईआर पर भरोसा करते हुए कहा कि कत्ल कथित तौर पर एक निजी आवास की चार दीवारी के

अंदर हुआ था और पांच मामले में, डीएम ने एफआईआर पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि एक दुकान के बाहर कथित रूप से गो हत्या हुई थी। इन सभी में एक बात और गौर करने वाली थी जिसमें एफआईआर में लिखी गई बात ही नहीं, यहां तक कि एनएसए लगाने के आदेशों में डीएम द्वारा बताए गए आधार भी करीब-करीब एक जैसे हैं।

ये भी पढ़ें-समंदर में बूंद बराबर है अंबानी पर सेबी का जुमार्ना

इन मामलों में गो हत्या से जुड़े सात मामलें में आरोप लगाते हुए, एनएसए आदेश में लिखा है कि भय और आतंक के माहौल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। साथ ही छह मामले ऐसे है जिनमें ठरअ के आदेशों में छह समान बातों का इस्तेमाल किया गयाः कुछ अज्ञात व्यक्ति मौके से भाग गए; घटना के कुछ मिनट बाद, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया; पुलिस पार्टी पर हमले के कारण, लोगों ने भागना शुरू कर दिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई; लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए दौड़ने लगे; माहौल के कारण, लोग अपने रोज मर्रा के काम में शामिल नहीं हो रहे हैं; आरोपी के कार्य के कारण, क्षेत्र की शांति और कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी।

क्या कहती है यूपी सरकार ?

इस पूरे मामले पर यूपी सरकार से भी सवाल किया गया है। इस खबर को लेखर विस्तृत सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर।के। तिवारी को भेजे गए। इनमें पूछा गया है कि जिलाधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों को हाईकोर्ट में रद्द किए जाने के बाद क्या कुछ सुधार किया गया है? मुख्य सचिव से यह भी पूछा गया है कि, कोर्ट के आदेश से यह नहीं लगता कि जिलाधिकारियों के रासुका लगाने के अधिकारों पर सख्त नजर रखी जाए? उनसे मामलों में सरकार द्वारा दोबारा अपील किए जाने के बारे में भी पूछा गया है। इन सभी सवालों का अखबार को कोई जवाब नहीं मिला है।

किस स्थिति में सरकार लगा सकती है ये कानून?

इस कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को रासुका भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों लोगों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने से संबंधित ये कानून है। अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में उसके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह उसे सरकार एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा किसी समय सरकार को ये लगता है कि कोई व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार करवा सकती हैं।

2018 से देश भर कितने लोगों पर लगा ये कानून?

वर्ष 2018 में, देश भर में रासुका के तहत 697 लोगों को हिरासत में लिया गया जिसमें से 406 को समीक्षा बोर्डों द्वारा रिहा किया गया जबकि 291 हिरासत में हैं। मध्य प्रदेश में, वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में एनएसए के तहत 795 लोगों को हिरासत में लिया गया था। समीक्षा बोर्डों द्वारा 466 लोगों को रिहा किया गया जबकि 329 हिरासत में हैं।

जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता फिल्म रिलीज नहीं करूंगा : विकास वर्मा

भारत और पौलेंड के साझा प्रयासों से नो मीन्स नो फिल्म बनाने वाले फिल्ममेकर विकास वर्मा 22 मार्च को अपनी फिल्म रिलीज करने वाले थे, लेकिन अचानक से बढ़े कोविड संक्रमण के मामलों की वजह से उन्होंने अपना फैसला टाल दिया है। अब वह कहते हैं कि फिल्म तब तक रिलीज नहीं करूंगा, जब तक एक-एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती। उनका मानना है कि ओटीटी से ज्यादा लोग आज भी सिनेमा के दीवाने हैं। इसलिए ओटीटी पर फिल्म रिलीज करने का कोई तुक ही नहीं।

आईएएनएस से विशेष बातचीत में विकास वर्मा ने बताया, यह फिल्म विंटर ओलंपिक विषय पर नहीं, बल्कि लव स्टोरी पर आधारित है। फिल्म का टीन एज हीरो स्कीइंग का खिलाड़ी है जो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पौलेंड जाता है। फिल्म में उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद होने वाली घटनाओं पर यह फिल्म बनी है। इस फिल्म को पौलेंड में काफी अच्छे से शूट किया गया है। किसी तरह के वीएफएक्स का प्रयोग नहीं किया गया। कलाकारों और पूरी प्रोडक्शन की टीम ने काफी मेहनत की है। -31 डिग्री तापमान में कैसे लोगों ने शूटिंग की, ये हम लोग ही जानते हैं। विकास कहते हैं, विंटर ओलंपिक एक खास खेल है। हमारे यहां भी कश्मीर गुलमर्ग में स्कीइंग की काफी संभावनाएं हैं। आज एक दो साल का बच्चा भी स्कीइंग कर रहा है। इसे हमारे यहां शुरू होना ही चाहिए। उनकी फिल्म वर्ल्ड क्लास की एक्शन फिल्म है। बॉलीवुड में लोगों को एक्शन काफी पसंद है। लंदन में तो इस फिल्म की तुलना जेम्स बॉन्ड सीरीज से कर रहे हैं। काफी प्यार और सराहना मिल रही है लोगों की अभी से।विकास वर्मा कहते हैं कि यह इंडो पोलिश लव स्टोरी है। लव स्टोरी सभी देखना पसंद करते हैं। इसमें हरिहरन ने संगीत दिया है और श्रेया घोषाल ने गीत गाए हैं। शामक डावर की कोरियोग्राफी भी आपको देखने को मिलेगी। पौलेंड के वायलन बजाने वाले कलाकारों ने भी फिल्म को सपोर्ट किया है और उनका भी काम फिल्म में दिखेगा। नो मीन्स नो फिल्म के टाइटल के बारे में विकास वर्मा बताते हैं कि यह महिलाओं से जुड़ा शब्द है। अब तक महिलाओं को अबला कहा गया, लेकिन अब नारी ऐसी नहीं है। फिल्म में कुछ हद तक यह भी संदेश है। नए हीरो ध्रुव को रखने पर वर्मा कहते हैं कि यह एक टीनएज लव स्टोरी है। रिसर्च करने पर पता चला कि यह फिल्म 15 से 35 साल के लोगों के बीच ही काफी लोकप्रिय होगी। फेसबुक व अन्य माध्यमों से रिसर्च करके ही यह फिल्म बनाई गई है, युवाओं को देखते हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो टाइटैनिक जैसी फिल्म भी भले ही जहाज पर बनी हो लेकिन उसका केंद्र बिंदु लव स्टोरी ही था। फिल्म रिलीज के बारे पूछने पर विकास ने कहा, 22 मार्च को इसे रिलीज करने की तैयारी हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से रोक दी गई। पौलेंड में भारतीय राजदूत से बात की गई तो पता चला वहां बड़े प्रीमियर का इस समय कोई फायदा नहीं होगा। संक्रमण बढ़ने की आशंका से यह रोक दिया गया। पौलेंड की सरकार ने भी हमारा काफी सहयोग किया है। फिल्म में संजय दत्त और प्रीति जिंटा का भी सहयोग मिला है। गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार इतनी ठंड में भी शूटिंग करते रहे। वहां ठंड से बचने के लिए हम लोग तरह-तरह के इंतजाम कर रहे थे। एक जगह खड़े होना मुमकिन नहीं था तो उछल कूदकर इधर उधर चलकर शरीर में गर्मी ला रहे थे। मजबूरन हम लोगों को ठंड से बचने के लिए ब्रांडी तक पीनी पड़ी। एक सवाल के जवाब में विकास वर्मा बताते हैं कि आज ओटीटी भले ही आगे चल रहा हो, लेकिन लोगों को पर्दे से प्यार है। लोगों के अंदर सिनेमा का जुनून आज भी देखा जा सकता है। हमने 70 एमएम स्क्रीन का जादू देखा है जो आज भी कायम है।